ई-पत्रिका
₹ 49/-

▶ **आखिर इस हवा की** दवा क्या है?

▶ **वर्चस्व का नया** रणनीतिक गलियारा

# CULT CURRENT

वर्ष: 8 अंक: 12 दिसंबर, 2025

WE MAKE VIEWS

# डूबते मेट्रोपोलिस

## पैरों तले धंसती धरती

## Let's 360°

- Media Consultancy
- Web solution
- Advertising
- Publication
- Languages Services
- Survey & Research
- Branding
- AV Production
- Campaign management
- Event organizer
- PR partner, PR associate
- Content writer & provider
- Media analyst

URJAS MEDIA VENTUE IS PERHAPS THE ONLY CONSULTING FIRM THAT CAN GIVE YOUR ORGANISATION A 360 DEGREE MEDIA BUSINESS GROWTH CONSULTING THROUGH IT'S 360 CAPABILITIES. FOR US, CONSULTING DOES NOT ONLY MEAN MECHANICAL COST REDUCTION THROUGH BETTER IT APPLICATIONS, WE FIND OUT WHAT YOUR ORGANISATION REALY NEEDS AND GIVE YOU AN INTELLECTUAL SOLUTION THAT HELP YOU REDUCE COST AS WELL AS HELPS YOURS BUSINESS GROW AND BEAT THE COMPETITION.

**NOW!! OUR CONSULTANT WILL GET BACK TO YOU IN 24 HOURS AND PUT YOU IN TO THE HIGH GROWTH PATH**

SMS 'BUSINESS GROWTH' TO +91-8826-24-5305 OR E-MAIL info@urjasmedia.com

URJAS MEDIA VENTURE

BEAT THE COMPETITION

www.urjasmedia.com

# गुमनाम नायक

## गांव लौटा युवक बना किसानों की उम्मीद

प्रिंस शुक्ला

24 वर्ष की उम्र में प्रिंस शुक्ला ने कभी नहीं सोचा था कि उनकी सबसे बड़ी सफलता एक असफलता से जन्म लेगी। स्विट्ज़रलैंड की स्कॉलरशिप की तैयारी और बेंगलुरु में नई नौकरी के बीच ही कोविड-19 ने सब कुछ रोक दिया। योजनाएँ टूट गईं, इंटरव्यू रुक गए और उन्हें मजबूरन अपने बिहार के छोटे से गाँव लौटना पड़ा, जिसे आसपास के लोग पीछे की ओर कदम मान रहे थे। गाँव लौटकर उन्होंने दशकों से किसानों को जकड़े रखी कमियों को नज़दीक से देखा — पुराने तौर-तरीके, बाज़ार से कमजोर जुड़ाव, घटिया बीज और बुनियादी औज़ारों की भारी कमी। बदलाव की ठानकर उन्होंने पिता से 1 लाख रुपये उधार लेकर 'एग्रेट' की शुरुआत की, जो छोटे किसानों को बेहतर बीज, ड्रिप सिंचाई सिस्टम और पर्यावरण–अनुकूल खाद जैसे सस्ते संसाधन उपलब्ध कराता है। साथ ही वे ग्राफ्टिंग, मल्टी–क्रॉपिंग और टिकाऊ खेती जैसी उन्नत तकनीकों का प्रशिक्षण देकर किसानों की पैदावार और आमदनी बढ़ाने में जुट गए। देखते–देखते एग्रेट ने हज़ारों किसानों तक पहुँच बनाकर कंपनियों के साथ साझेदारियाँ कीं और प्रिंस की कभी उपहास की गई 'देहाती' पहचान आज करोड़ों के कारोबार और किसानों की बदली ज़िंदगी में बदल गई।

संपादकीय टोली


संपादकीय

**राष्ट्रीय संपादक**
संजय श्रीवास्तव

**संपादक**
श्रीराजेश

**प्रबंध संपादक**
सच्चिदानंद पाण्डेय

**रोमिंग संपादक**
डॉ. राजाराम त्रिपाठी

**राजनीतिक संपादक**
अंशुमान त्रिपाठी

**मेट्रो संपादक**
शक्ति प्रकाश श्रीवास्तव
डॉ. रुद्र नारायण

**अंतर्राष्ट्रीय संपादक**
श्रीश पाठक

**कारपोरेट संपादक**
गगन बत्रा

**खेल संपादक**
जलज श्रीवास्तव

**डिजीटल संपादक**
सुनीता त्रिपाठी

**सहायक संपादक**
संदीप कुमार

**उप संपादक**
मनोज कुमार
संतु दास

**साहित्य संपादक**
अनवर हुसैन

**कला संपादक**
जया वर्मा

**वेब एवं आईटी विशेषज्ञ**
अनुज कुमार सिंह

**फोटो संपादक**
विवेक पाण्डेय

**विशेष संवाददाता**
कमलेश झा
विकास गुप्ता

**संवाददाता**
संदीप सिंह
अनिरुद्ध यादव

**ब्यूरो प्रमुख (अंतर्राष्ट्रीय)**
अकुल बत्रा (अमेरिका)
सी.शिवरतन (नीदरलैंड)
जी. वर्मा(लंदन)
डॉ. मो. फहीम अकबर (पाकिस्तान)
ए. असगरजादेह (ईरान)
डॉ. निक सेरी (मलेशिया)

**ब्यूरो प्रमुख (राष्ट्रीय)**
आर. रंजन (नई दिल्ली)
संजय कुमार सिंह (लखनऊ)
कैप्टन सुधीर सिन्हा (रांची)
निमेष शुक्ल (पटना)
नागेन्द्र सिंह (कोलकाता)
राकेश रंजन (गुवाहाटी)

**विपणन**
**सत्यजीत चौधरी**
महाप्रबंधक

**ऑनलाइन प्रसार**
**सृजीत डे**



वर्षः 8 अंकः 12 दिसंबर, 2025

Follow us:
fb.com/cultcurrent @Cult_Current cultcurrent@gmail.com

**URJAS MEDIA VENTURE**
**Head office:** Swastik Apartment, GF, Pirtala, Agarpara, Kolkata 700 109, INDIA, Tel: +91 6289-26-2363
**Corporate Office:** 14601, Belaire Blvd, Houston, Texas 77083 USA Tel: +1 (832) 670-9074
Web: http://cultcurrent.in

Cult Current is a monthly e-magazine published by Urjas Media Ventures from Swastik Apartment, GF, Pirtala, Agarpara, Kolkata 700 109.
**Editor: Srirajesh**



**Disclaimer:** All editorial and non-editorial positions in the e-magazine are honorary. The publisher and editorial board are not obligated to agree with all the views expressed in the articles featured in this e-magazine. Cult Current upholds a commitment to supporting all religions, human rights, nationalist ideology, democracy, and moral values.

COVER STORY 30

# डूबते मेट्रोपोलिस
पैरों तले धंसती धरती

12 आखिर इस हवा की दवा क्या है?

18 पूर्वी मोर्चा
गहराता भू-संकट

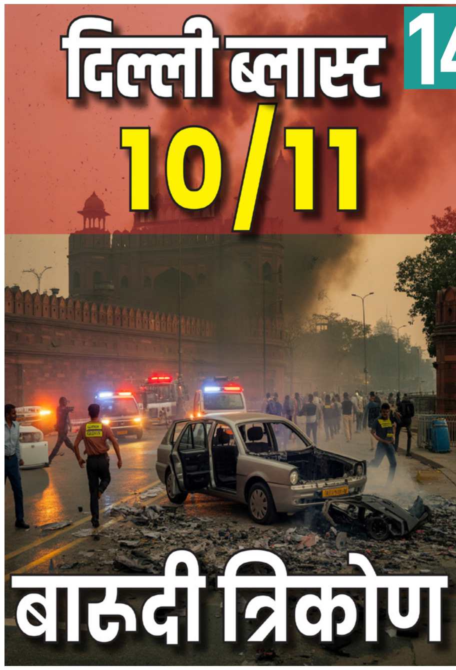

दिल्ली ब्लास्ट 10/11 14
बारूदी त्रिकोण

CONTENT


लाभार्थी-आधारित राजनीति का उभार 22

SIR: प. बंगाल में 'रिवर्स एक्सोडस' 26

हाल-ए-पाकिस्तान: वर्दी में लोकतंत्र 40

भारत-पाक-अफगान: उभरता त्रिकोण 46

वाशिंगटन-रियाद: नई करवट 50

नया तेल, नया खेल 54

रुसी दांव, अमेरिकी चाल, भारत से दोस्ती... 58

सूख रहा ईरान 62

नौसेनाओं का नवजागरण काल... 66

व्यस्व का नया रणनीतिक गलियारा 68

धर्मेंद्र: सिनेमाई सूरज ढला 72

तीन बहनें: काव्य सी बहती कहानी और... 74

76 बॉयफ्रेंड संग फिर स्पॉट हुई
Malaika Arora

## Small talk

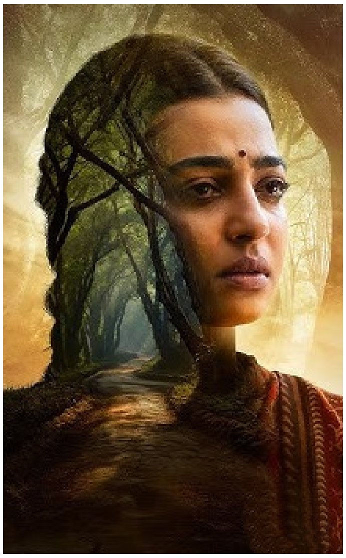

### राधिका आप्टे की फिल्म 'साली मोहब्बत' OTT पर होगी रिलीज

बॉलीवुड अभिनेत्री राधिका आप्टे और 'मिर्जापुर' से मशहूर हुए अभिनेता दिव्येंदु ओटीटी पर धमाका करने के लिए तैयार हैं। उनकी आगामी चर्चित फिल्म 'साली मोहब्बत' का ट्रेलर जारी कर दिया गया है। इस फिल्म के जरिए अभिनेत्री टिस्का चोपड़ा निर्देशन की दुनिया में कदम रख रही है। वहीं फिल्म के निर्माता ज्योति देशपांडे, मनीष मल्होत्रा और दिनेश मल्होत्रा हैं। निर्माताओं ने 'साली मोहब्बत' का ट्रेलर जारी करते हुए फिल्म की रिलीज तारीख से भी पर्दा उठा दिया है। साली मोहब्बत' एक क्राइम-थ्रिलर फिल्म है जिसमें राधिका छोटे शहर की महिला स्मिता का किरदार निभा रही हैं। फिल्म में भावनाओं, धोखा और फरेब का फुल तड़का लगाया गया है। ●

## 2025 में तहलका मचाने वाली खोजें

### मेमोरी एडिटिंग!

बोस्टन यूनिवर्सिटी के न्यूरोसाइंटिस्ट स्टीव रामिरेज़ लिखते हैं कि जब मेरे स्वर्गीय सहकर्मी जू लियू और मैंने पहली बार एक विशेष याददाश्त (engram) को संग्रहित करने वाली मस्तिष्क कोशिकाओं को प्रकाशित किया, तो यह एक विचार को वापस जीवन में आते देखने जैसा था। हमने चूहों के हिप्पोकैंपस में न्यूरॉन्स के एक समूह को उत्तेजित किया, जो मेमोरी का भौतिक आधार है। हमें तब यह अहसास नहीं था कि हम न्यूरोसाइंस की सबसे रोमांचक सीमा में कदम रख रहे थे। ●

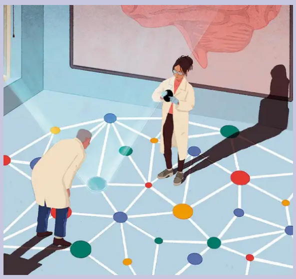

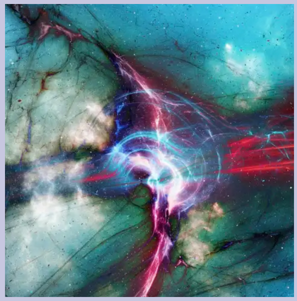

### डार्क मैटर पर नई चुनौती!

डार्क मैटर शोधकर्ताओं के लिए यह एक अवास्तविक समय है। दुनिया भर की सरकारों द्वारा फंडिंग में कटौती के बावजूद, डार्क मैटर भौतिकी में सबसे बड़ी अनसुलझी पहेली बनी हुई है। हमारे ब्रह्मांड का अधिकांश पदार्थ अदृश्य है- दृश्य पदार्थ के प्रत्येक किलोग्राम के लिए, लगभग 5 किलोग्राम डार्क मैटर मौजूद है। हम यह केवल इसलिए जानते हैं क्योंकि हमने ब्रह्मांड के दृश्य तत्वों की संरचना पर इसके प्रभाव को देखा है। ●

### आधुनिक AI चिंताएँ!

सुकरात, जो स्वयं कोई पाठ न छोड़ने के लिए प्रसिद्ध थे, का मानना था कि लेखन स्मृति को कमजोर करता है। हालांकि लेखन से स्मृति सुधरती है, लेकिन उनके संज्ञानात्मक प्रौद्योगिकियों के प्रति अविश्वास की भावना आज भी जीवित है। मनोवैज्ञानिक और दार्शनिक अब चिंतित हैं कि ChatGPT जैसे जनरेटिव AI उपकरण- सूचना याद रखने की हमारी शक्ति को घटा देंगे और स्पष्ट तर्क क्षमता को मंद कर देंगे। यह चिंता है कि सुविधा के लिए इन उपकरणों पर अत्यधिक निर्भरता मानव बुद्धि की मौलिक क्षमताओं को प्रभावित कर सकती है। ●

## ठंडे पानी में तैराकी - मस्तिष्क और शरीर दोनों के लिए फायदेमंद

ठंडे पानी में तैरने के शारीरिक लाभों पर शोध लगातार बढ़ रहा है। अब वैज्ञानिक यह भी खोज रहे हैं कि यह हमारे मस्तिष्क को स्थायी रूप से बेहतर बना सकता है। सुबह 8 बजे, लंदन के बेकनहैम प्लेस पार्क में अपनी स्थानीय झील के किनारे खड़े होकर, मैं और मेरा दोस्त पानी के एकल-अंक तापमान के बावजूद तैरने जाते हैं। पानी में पहला कदम सांस खींच लेता है, लेकिन शरीर के अभ्यस्त होने और एक बड़ा चक्कर लगाने के बाद, एक नई ऊर्जा और ताजगी महसूस होती है। यह अभ्यास मस्तिष्क को सकारात्मक रूप से बदल सकता है। ●

## महिंद्रा XEV 9S लॉन्च, 7-सीटर देगी फुल मजा

महिंद्रा ने 27 नवंबर 2025 को भारत में अपनी नई सात-सीटर इलेक्ट्रिक SUV, XEV 9S, लॉन्च कर दी है। इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 19.95 लाख है। XEV 9S 7-सीटर है और इसे कंपनी के INGLO इलेक्ट्रिक प्लेटफार्म पर तैयार किया गया है, जिससे यह काफी स्पेस, आधुनिक डिज़ाइन और एडवांस फीचर्स के साथ आती है। ●

# नियुक्ति

**सूर्यकांत,** मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट

जस्टिस सूर्यकांत ने भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश (CJI) के रूप में शपथ ली है। उनका कार्यकाल 15 महीने का होगा और वह CJI भूषण आर गवई का स्थान लेंगे, जिन्होंने सेवानिवृत्ति से पहले परंपरा के अनुसार उनके नाम की सिफारिश की थी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जस्टिस सूर्यकांत को शपथ दिलाई है।

**वरुण बेरी ,** सीईओ, ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज

ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज ने सोमवार को बताया कि उसके वाइस चेयरमैन, प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी वरुण बेरी ने इस्तीफा दे दिया है। ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने शेयर बाजार के बताया कि कंपनी ने रक्षित हरगवे को 15 दिसंबर, 2025 से अपना प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है।

# उन्होंने कहा

**डोनाल्ड ट्रंप**
राष्ट्रपति, अमेरिका

"दक्षिण अफ्रीका में मानवाधिकार की उल्लंघन जारी है और यह पूरी तरह से शर्मनाक है कि G20 दक्षिण अफ्रीका में आयोजित किया जा रहा है।"

**सिरिल रामाफोसा**
राष्ट्रपति, दक्षिण अफ्रीका

"बहिष्कार की राजनीति कभी काम नहीं करती। अगर संयुक्त राज्य अमेरिका बाहर खड़े रहने का विकल्प चुनता है, तो भी हम संवाद, विश्वास और सहयोग के लिए द्वार खुला रखेंगे।"

# श्रद्धांजलि

**अटल बिहारी बाजपेयी**
(25/12/1924-16/08/2018

अटल बिहारी वाजपेयी भारत के ऐसे राजनेता थे जिनकी वाणी में ओज था, विचारों में स्पष्टता और आचरण में संयम। 25 दिसंबर 1924 को ग्वालियर में जन्मे वाजपेयी आगे चलकर भारतीय राजनीति की उस धारा के प्रतिनिधि बने, जिसमें राष्ट्रवाद और लोकतंत्र दोनों सही संतुलन के साथ मौजूद थे। एक प्रखर वक्ता, संवेदनशील कवि, तेजस्वी विचारक और व्यवहार से बेहद सरल व्यक्ति, वाजपेयी ने राजनीति को संघर्ष से साधा और शासन को संवाद से संचालित किया। वे तीन बार भारत के प्रधानमंत्री बने, जिसमें 1998–2004 का कार्यकाल सबसे प्रभावशाली माना जाता है। पोखरण-II परमाणु परीक्षण कर भारत को पराक्रम और आत्मविश्वास की नई पहचान दिलाने का साहस भी उन्हीं के नेतृत्व में दिखा। उन्होंने बस सेवा के माध्यम से पाकिस्तान से संवाद का पुल बनाने का प्रयास किया, जो उनकी शांतिपूर्ण कूटनीति की अनूठी पहचान है। राजधर्म और सुशासन को आधार बनाकर उन्होंने विकास, बुनियादी ढाँचा और आर्थिक उदारीकरण पर जोर दिया। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना, ग्रामीण सड़क योजना और दूरसंचार क्षेत्र में आमूल बदलाव उनके कार्यकाल की महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ रहीं। शब्दों की गरिमा और विरोधियों के प्रति सम्मान उनकी राजनीतिक संस्कृति की पहचान थी। उनके भाषण में कविता, राजनीति और संवेदना का अद्भुत मिश्रण मिलता है। जीवन के अंतिम वर्षों में बीमारी से संघर्ष करते हुए भी वे राष्ट्र के लिए प्रेरणा बने रहे। 16 अगस्त 2018 को उनके निधन के साथ भारतीय राजनीति का एक उज्ज्वल युग शांत हो गया, पर विचार, कविता और कर्म की रोशनी आज भी उन्हें अमर बनाए हुए है। वाजपेयी न केवल राजनीति के मंच के सितारे थे, बल्कि भारतीय आत्मा के कवि भी। उनकी विरासत आने वाली पीढ़ियों को राष्ट्रहित, संयम और संवाद की राह पर चलने की प्रेरणा देती रहेगी। ●

## अमेरिकी अधिकारी ने यूक्रेन संघर्ष लंबा खींचने पर यूरोप को चेताया

न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, एक वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारी ने पिछले सप्ताह कीव में यूरोपीय राजनयिकों को चेतावनी दी कि रूस की लंबी दूरी के हथियार बनाने की क्षमता बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि यूक्रेन संघर्ष का शीघ्र समाधान न होने से इसके बढ़ने की संभावना ही बढ़ेगी। अमेरिकी सेना सचिव डैन ड्रिस्कॉल ने कहा कि रूस की उत्पादन क्षमता उसे न केवल यूक्रेनी ठिकानों पर हमला जारी रखने देगी, बल्कि हथियारों का अधिशेष भी बनाने देगी। इस ब्रीफिंग में मौजूद लोगों ने इन टिप्पणियों को इस निहितार्थ के रूप में लिया कि संघर्ष तब तक फैल सकता है जब तक कि इसे वाशिंगटन की प्रस्तावित शांति योजना के माध्यम से हल नहीं किया जाता। यूरोपीय सरकारें यूक्रेन को समर्थन देते हुए यह मानती रही हैं कि यूक्रेनी सैनिक पश्चिम को रूसी आक्रामकता से बचा रहे हैं। ●

## क्या ट्रंप द.अफ्रीका को G20 शिखर सम्मेलन से बाहर कर पाएंगे?

अमेरिका और दक्षिण अफ्रीका के बीच बिगड़ते संबंधों के बीच, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की है कि वह अगले साल के G20 शिखर सम्मेलन में दक्षिण अफ्रीका के भाग लेने पर प्रतिबंध लगा देंगे। ट्रंप ने इस साल दक्षिण अफ्रीका में आयोजित G20 को 'पूरी तरह से शर्मनाक' बताया था और उन पर श्वेत किसानों के खिलाफ 'श्वेत नरसंहार' करने का आरोप लगाया है—एक ऐसा दावा जिसे दक्षिण अफ्रीका खारिज करता है। चूँकि अगले साल G20 की अध्यक्षता अमेरिका के पास होगी। ●

## गिनी-बिसाऊ में तख्तापलट, सेना ने सत्ता संभाली

गिनी-बिसाऊ में सैनिकों के एक समूह ने बलपूर्वक सत्ता पर कब्जा कर लिया, जिसके कारण राष्ट्रपति और संसदीय चुनावों के परिणाम की घोषणा से पहले ही चुनाव प्रक्रिया निलंबित कर दी गई। 26 नवंबर की सुबह, निवर्तमान राष्ट्रपति उमारो सिस्कोको एम्बालो को चुनाव में हारते हुए देखा गया था, और विपक्ष के फर्नांडो डायस की जीत तय मानी जा रही थी। तभी राष्ट्रपति भवन और चुनाव आयोग भवन से गोलीबारी की आवाजें आईं। सैन्य कमान के प्रवक्ता डिनिस एन'चमा ने घोषणा की कि सैनिकों ने 'राष्ट्रीय सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था बहाल करने' के लिए देश पर नियंत्रण कर लिया है। ●

## जकार्ता बना दुनिया का सबसे बड़ा शहर

संयुक्त राष्ट्र की नई रिपोर्ट के अनुसार, इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता 41.9 मिलियन लोगों के साथ दुनिया का सबसे बड़ा शहर बन गया है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका 36.6 मिलियन आबादी के साथ दूसरे स्थान पर पहुँच गई है। 2000 में दुनिया का सबसे बड़ा शहर रहा टोक्यो (33.4 मिलियन) अब तीसरे स्थान पर खिसक गया है। संयुक्त राष्ट्र का अनुमान है कि 2050 तक ढाका दुनिया का सबसे बड़ा शहर बन जाएगा। रिपोर्ट के मुताबिक, दुनिया में अब मेगासिटी (1 करोड़ से अधिक आबादी वाले शहर) की संख्या बढ़कर 33 हो गई है, जिनमें से 19 एशिया में हैं। ●

## हांगकांग में 100 साल की सबसे भीषण आग, 65 लोगों की मौत, 279 लापता

हांगकांग के ताई पो इलाके में 27 दिसंबर को कई ऊंची इमारतों में लगी आग से कम से कम 65 लोगों की मौत हो गई है और 279 लोग लापता हैं। अधिकारियों ने इसे 100 से अधिक वर्षों में शहर की सबसे भीषण आग बताया है। बाँस के मचान से शुरू हुई यह आग तेजी से फैली। गुरुवार सुबह तक, अग्निशमन कर्मियों ने चार इमारतों में आग पर काबू पा लिया, लेकिन तीन अन्य पर काम जारी था। इस हादसे में लगभग 70 लोग घायल हुए हैं। 1918 के बाद यह हांगकांग की सबसे घातक आग है। ●

## इमरान खान की मौत की अफवाहें खारिज

पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की स्थिति और मौत की अफवाहों के बीच, अदियाला जेल प्रशासन ने बुधवार को बयान जारी कर इन अटकलों को निराधार बताया। रावलपिंडी जेल के अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि इमरान खान को जेल से शिफ्ट नहीं किया गया है, और वह 'पूरी तरह से स्वस्थ हैं तथा उन्हें पूर्ण चिकित्सा सुविधा मिल रही है।' ये अफवाहें तब फैलीं जब खान की बहनों और समर्थकों मुलाकात की मांग की थी उन्हें बीते तीन सप्ताह से जेल प्रशासन द्वारा मिलने नहीं दिया जा रहा था। ●

## गाजा में रिकॉर्ड तोड़ आर्थिक तबाही 69 साल की प्रगति हुई तबाह

संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन की रिपोर्ट के अनुसार, इज़राइल और हमास के बीच दो साल के युद्ध के बाद गाजा सबसे खराब आर्थिक पतन का सामना कर रहा है। रिपोर्ट में बताया गया है कि 2024 में सकल घरेलू उत्पाद पिछले वर्ष की तुलना में 83% तक गिर गया, जबकि प्रति व्यक्ति जीडीपी गिरकर $161 (प्रति दिन 50 सेंट से कम) हो गई, जो दुनिया में सबसे निचले स्तरों में से है। संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन का अनुमान है कि गाजा की अर्थव्यवस्था सिकुड़कर 2022 के आकार का केवल 13% रह गई है। यहाँ मुद्रास्फीति 238% है, बेरोजगारी 80% के करीब है, और सभी 23 लाख निवासी गरीबी रेखा से नीचे धकेल दिए गए हैं। यूएनसीटीएडी ने कहा कि सैन्य अभियानों ने गाजा की आर्थिक नींव को नष्ट कर दिया है, जिससे यह 'पूरी तरह से बर्बाद' हो गया है और इसने 69 साल की प्रगति को मिटा दिया है। ●

## चीन ने किया आपातकालीन अंतरिक्ष यान शेनझोउ-22 लॉन्च

चीन ने अपने क्रू वाले तियांगोंग अंतरिक्ष स्टेशन पर एक प्रतिस्थापन यान शेनझोउ-22 भेजा, जिससे अंतरिक्ष यात्रियों के पास आपात स्थिति में पृथ्वी पर लौटने का साधन सुनिश्चित हो गया। शेनझोउ-20 परिवहन यान की खिड़की में अंतरिक्ष मलबे से आई दरार के कारण वह उड़ान भरने के लिए अयोग्य हो गया था, जिससे अंतरिक्ष यात्री 11 दिनों तक बिना वापसी वाहन के स्टेशन पर थे। चीन मानवयुक्त अंतरिक्ष एजेंसी ने इस अंतराल को भरने के लिए यह पहला त्वरित आपातकालीन लॉन्च किया। ●

## जर्मन गठबंधन सरकार पर पेंशन सुधार विवाद का संकट

जर्मनी के चांसलर फ्रीडरिष मैर्त्स की पार्टी सीडीयू, सहयोगी सीएसयू और एसपीडी के नेता बर्लिन में गठबंधन समिति की बैठक करेंगे। इस बैठक में पेंशन सुधार पैकेज सबसे बड़ा विवाद का मुद्दा है, जिसके तहत 2031 तक सेवानिवृत्ति भुगतान को वेतन से जोड़ने की कोशिश है। सीडीयू/सीएसयू के युवा सांसद इस पैकेज का विरोध कर रहे हैं। यदि वे इसे अस्वीकार करते हैं, तो संसद में गठबंधन का बहुमत खतरे में पड़ सकता है। चांसलर मैर्त्स पहले ही स्वीकार कर चुके हैं कि मध्य वामपंथी सहयोगी एसपीडी के साथ सामाजिक कल्याण बजट में कटौती आसान नहीं होगी। ●

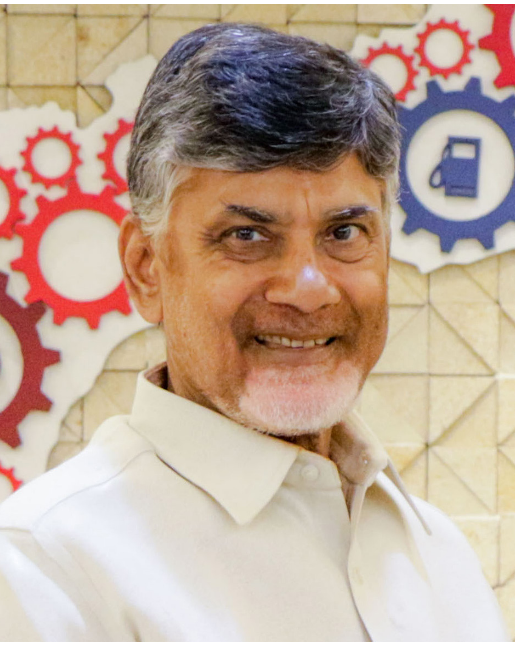

## अमरावती में बनेगा तिरुमाला जैसा भव्य वेंकटेश्वर मंदिर

आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने अमरावली के वेंकटपालेम में वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर के विस्तार की आधारशिला रखी। तिरुमाला मंदिर की तर्ज पर 260 करोड़ रुपये मंदिर का विस्तार किया जाएगा। इस मंदिर को सिर्फ ढाई साल में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। दरअसल, मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने अमरावती में वेंकट पालम वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर के एक बड़े विस्तार की आधारशिला रखी। तिरुमाला की तर्ज पर बनने वाले इस मंदिर को सिर्फ ढाई साल में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। पहले चरण में 140 करोड़ और दूसरे चरण में 120 करोड़ खर्च होंगे। इसमें सात मंजिला राजगोपुरम, पुष्करिणी, अन्नदानम परिसर, विश्राम गृह और बड़ी पार्किंग जैसी सुविधाएं बनाई जाएंगी। ●

## SIR को लेकर बीएलओ पर बढ़ा काम का बोझ

बिहार में एसआईआर का मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में ही लंबित है लेकिन इस बीच चुनाव आयोग ने 12 अन्य राज्यों में भी एसआईआर कराने की घोषणा कर दी। चार नवंबर से शुरू हुए एसआईआर के इस दूसरे चरण के तहत इस काम को एक महीने के भीतर यानी चार दिसंबर तक पूरा करना है। एसआईआर मतदाता सूचियों को अपडेट करने की एक विशेष प्रक्रिया है जिसके तहत बीएलओ यानी बूथ लेवल ऑफिसर्स को घर-घर जाकर मतदाताओं की जानकारी सत्यापित करनी पड़ती है। चुनाव आयोग का दावा है कि एसआईआर से मतदाता सूचियां और ज्यादा सटीक होंगी और फर्जी वोटिंग रोकी जा सकेगी। ●

## भारत ने लॉन्च किया नया एंटी-सबमरीन युद्धपोत INS माहे

भारतीय नौसेना ने तटीय रक्षा और पनडुब्बी रोधी अभियानों के लिए INS माहे को शामिल किया है। यह उन्नत सेंसर, हथियार और संचार प्रणाली से लैस है, जो समुद्र की उथली गहराइयों में लंबे समय तक अभियान चलाने और पनडुब्बी खतरों का सटीक पता लगाने में सक्षम है। जहाज़ का 80% हिस्सा भारत में निर्मित हुआ है और इसे कोचीन शिपयार्ड ने डिजाइन किया। 'मेक इन इंडिया' के तहत यह स्वदेशी रक्षा क्षमताओं की बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। ●

## भारत में सैन्य क्रांति की ओर तकनीक का बढ़ता दबदबा

चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने चाणक्य डिफेंस डायलॉग में कहा कि भविष्य की युद्ध क्षमता के लिए नवाचार, अनुसंधान और कूटनीतिक रणनीति आवश्यक है। उन्होंने बताया कि युद्ध निरंतर बदलता है और उभरती तकनीकें रणनीति का केंद्र बन रही हैं। चौहान के अनुसार, युद्ध में भूगोल से अधिक तकनीक निर्णायक होगी और कई उभरती तकनीकों का एकीकरण आगामी सैन्य क्रांति को परिभाषित करेगा। ●

## वंशवाद के आरोपों पर आरएलएम में भूचाल —सात नेताओं का इस्तीफ़ा

राष्ट्रीय लोक मोर्चा (आरएलएम) में उपेंद्र कुशवाहा के फैसले ने भारी राजनीतिक हलचल पैदा कर दी है। नीतीश कुमार सरकार में मंत्री बनाए जाने की उम्मीद स्नेहलता कुशवाहा से हटकर सीधे उनके बेटे दीपक प्रकाश पर टिक गई, जिन्हें पंचायती राज विभाग सौंपा गया है—जबकि वे न विधानसभा के सदस्य हैं, न परिषद के। इससे पार्टी में असंतोष फूट पड़ा और राज्य अध्यक्ष महेंद्र कुशवाहा, उपाध्यक्ष जितेंद्र नाथ सहित सात वरिष्ठ नेताओं ने इस्तीफ़ा दे दिया। ●

## माता-पिता के तलाक के बाद दोनों साथ रहें बच्चे: सुको

देश के सर्वोच्च न्यायालय ने एक मामले की सुनवाई के दौरान टिप्पणी करते हुए कहा कि अगर किसी दंपती के बीच झगड़ा होता है और मामला तलाक तक पहुंचता है, तो ऐसे में भाई बहनों को साथ में रहना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। दरअसल, मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि जब कोई दंपती जिसके दो बच्चे हैं, किसी शादी के झगड़े की वजह से अलग रहने लगते हैं, तो बच्चे भी अलग हो जाते हैं, जिसमें एक माँ के साथ और दूसरा पिता के साथ रहता है। बेंच ने कहा कि हमें यह जानकर दुख हो रहा है कि नाबालिग भाई-बहन अलग रह रहे हैं। भाई बहन का यह अलगाव बहुत दर्दनाक है। ●

## अरुणाचल विवाद पर फिर बढ़ा तनाव—शंघाई एयरपोर्ट की घटना से भड़की नई चिंगारी

भारत–चीन संबंधों में अरुणाचल प्रदेश दशकों से विवाद और कूटनीतिक तनातनी का विषय रहा है। चीन इसे 'दक्षिणी तिब्बत' कहकर अपना क्षेत्र बताता है, जबकि भारत इसे अपने अभिन्न अंग के रूप में स्पष्ट रूप से स्थापित करता है। हाल की घटना ने इस पुराने विवाद को फिर हवा दे दी है। लंदन से जापान जा रही अरुणाचल की नागरिक प्रेमा वांगजोम थोंगडोक को चीन के शंघाई एयरपोर्ट पर घंटों रोका गया और अधिकारियों ने दावा किया कि उनका भारतीय पासपोर्ट मान्य नहीं, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश चीन का हिस्सा है। इस दौरान उनकी कनेक्टिंग फ्लाइट भी छूट गई। बाद में भारतीय दूतावास के हस्तक्षेप के बाद ही उन्हें छोड़ा गया, जिसके पश्चात भारत ने इसे अंतरराष्ट्रीय नियमों और एविएशन कन्वेंशनों का उल्लंघन बताते हुए औपचारिक विरोध दर्ज कराया है। इससे पहले भी चीन द्वारा अरुणाचल के लोगों को स्टेपल वीज़ा जारी करने पर विवाद हुआ था और भारत ने कई खिलाड़ियों को चीन यात्रा से रोका था। यह घटना न केवल पुराने विवाद को दोहराती है बल्कि यह आने वाले समय में द्विपक्षीय संबंधों को और जटिल बना सकते हैं। ●

## बर्थ सर्टिफिकेट के रूप में मान्य नहीं होगा आधार कार्ड

महाराष्ट्र एवं उत्तर प्रदेश सरकार ने एक अहम फैसला लेते हुए आदेश जारी कर कहा कि आधार कार्ड अब जन्मतिथि प्रमाण पत्र के रूप में मान्य नहीं होगा। इस संबंध में एक आदेश भी जारी किया गया है। आदेश में कहा गया है कि आधार कार्ड में दर्ज जन्मतिथि किसी भी प्रमाणित दस्तावेज के आधार पर तय नहीं होती है, यही कारण है कि इसे आधिकारिक प्रमाण पत्र के रूप में नहीं स्वीकार किया जा सकता। नियोजन विभाग के विशेष सचिव अमित सिंह बंसल ने यूआइडीएआइ के पत्र का हवाला देते हुए कहा कि आधार कार्ड में जन्मतिथि का कोई प्रमाणित दस्तावेज संलग्न नहीं होता। ●

## भारत की जीडीपी दूसरी तिमाही में 8.2 प्रतिशत बढ़ी

भारत की सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की वृद्धि दर दूसरी तिमाही में 8.2 प्रतिशत बढ़ी। सरकारी आंकड़ों के अनुसार पिछले वित्त वर्ष की समान तिमाही में यह 5.6 प्रतिशत थी। सरकार की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था ने जुलाई-सितंबर तिमाही में 8.2 प्रतिशत की वृद्धि दर हासिल की। यह छह तिमाहियों का उच्चतम स्तर है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जीएसटी दर में कटौती से उपभोग बढ़ने की उम्मीद में कारखानों ने अधिक उत्पाद तैयार किए। दूसरी तिमाही में सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर पिछले तीन महीनों के 7.8 प्रतिशत और एक वर्ष पूर्व की समान अवधि के 5.6 प्रतिशत से बेहतर रही। विनिर्माण, जो देश के सकल घरेलू उत्पाद का 14 प्रतिशत है, दूसरी तिमाही में 9.1 प्रतिशत बढ़ा। ●

**श्रीराजेश,** संपादक

# रुपये - रूबल स्वतंत्र प्रवाह

**रुपया और रूबल का यह संगम सिर्फ भुगतान का पुल नहीं, शक्ति-संतुलन की नई भू-रेखा है। पश्चिम दीवारें खड़ा कर रहा है, भारत–रूस गलियारे बना रहे हैं—पूरा विश्व मानचित्र अब अलग लिपि में लिखा जा रहा है।**

वैश्विक शक्ति संतुलन कभी सेनाओं और युद्धपोतों से तय होता था, फिर तेल, गैस और समुद्री तंत्र इसकी भाषा बने। पर आज की दुनिया में सत्ता का नया निर्धारक उभर रहा है — डिजिटल भुगतान प्रणालियाँ, मुद्रा निपटान और वित्तीय संप्रभुता। रूस और भारत द्वारा अपने राष्ट्रीय भुगतान नेटवर्क — मीर और रूपे — को जोड़ने की दिशा में निर्णायक कदम इसी परिवर्तन का सबसे जीवंत संकेत है। यह सिर्फ तकनीकी सुविधा नहीं, बल्कि डॉलर-केन्द्रित वैश्विक ढाँचे के सामने एक वैकल्पिक वित्तीय धुरी की स्थापना है।

राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की आगामी नई दिल्ली यात्रा इस प्रक्रिया को औपचारिक रूप दे सकती है। कुछ वर्ष पहले तक अंतरराष्ट्रीय भुगतान की दुनिया वीजा, मास्टरकार्ड और स्विफ्ट के आधिपत्य में थी, और दुनिया उसे ही अंतिम मानती थी। लेकिन पश्चिमी प्रतिबंधों ने स्वयं अपने ही ढाँचे में सुराख कर दिए। रूस पर लगाए गए वित्तीय प्रतिबंधों ने मास्को को झुकाने के बजाय उसे एक नई राह दिखा दी — उसने भुगतान नेटवर्क विकसित किया, और भारत की तरह अपनी डिजिटल संप्रभुता को आकार दिया। भारत का रूपे और यूपीआई आज केवल घरेलू भुगतान प्रणाली नहीं बल्कि दुनिया में सबसे तेज़ और व्यापक डिजिटल ढाँचों में से एक है। अब दोनों देशों का लक्ष्य इन प्रणालियों का एकीकरण करना है, ताकि व्यापार और लेन-देन किसी तीसरे देश या मुद्रा पर निर्भर न रहे।

यह कदम केवल पर्यटन, एटीएम कार्ड या क्यूआर भुगतान तक सीमित नहीं है। असली उथल-पुथल उस स्तर पर हो रही है जहाँ मुद्रा विनिमय पर नियंत्रण ही शक्ति का मापदंड बनता है। आज रूस और भारत के बीच 90 प्रतिशत व्यापार सीधे रूपया-रूबल या मित्र देशों की मुद्राओं में होता है — यानी डॉलर को दरकिनार करते हुए। तेल, कोयला, खाद — सभी सौदे ऐसे रास्तों से गुजर रहे हैं जिन पर पश्चिम की पकड़ नहीं। यह वित्तीय व्यवस्था नहीं, संप्रभुता का प्रदर्शन है — वह अधिकार जो कभी वाशिंगटन के बैंकिंग सिस्टम की कृपा पर निर्भर था।

रूस और भारत के भुगतान नेटवर्क के एकीकरण के बाद स्थिति और नाटकीय रूप से बदल सकती है। विशेषज्ञों के अनुसार पहले चरण में मीर–रूपे जोड़ना संभव है, फिर अगला कदम होगा रूस की फास्टर पेमेंट सिस्टम और भारत की यूपीआई को सीधा जोड़ना। उस स्तर पर पहुँचने के बाद भुगतान न डॉलर में होंगे, न किसी अमेरिकी प्रणाली की अनुमति पर टिका हुआ रहेगा। लेन-देन की लागत लगभग तीस प्रतिशत तक घट सकती है, और व्यापारी क्यूआर कोड या मोबाइल वॉलेट से निपटान कर सकेंगे। जब व्यापार की धारा स्वतंत्र होती है, तो शक्ति समीकरण भी स्वतंत्र होते हैं।

पश्चिमी दुनिया के लिए यह परिवर्तन असहज है। उसकी पूरी वित्तीय सत्ता तीन खंभों पर खड़ी रही — ऊर्जा का मूल्य डॉलर में तय होना, भुगतान स्विफ्ट नेटवर्क से गुजरना, और वीजा–मास्टरकार्ड जैसा निजी ढाँचा पूरी दुनिया पर लागू होना। रूस–भारत भुगतान पुल इन्हीं खंभों में पहली दरार है। चीन पहले ही अपनी वैकल्पिक भुगतान प्रणाली तैयार कर चुका है। यदि भारत और रूस सफलतापूर्वक इस डिजिटल वित्तीय गठजोड़ को स्थापित करते हैं, तो पश्चिम की वित्तीय वर्चस्व-व्यवस्था केवल चुनौती नहीं झेलेगी, बल्कि धीरे-धीरे अपनी केंद्रीयता खोने लगेगी। यह भविष्य का संकेत नहीं — यह भविष्य का प्रारूप है।

इस पूरी प्रक्रिया में भारत की भूमिका विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। यह देश न मॉस्को की छाया है न वाशिंगटन का छात्र। वह स्वयं एक ध्रुव है, जिसका भू-राजनीतिक लक्ष्य स्पष्ट है — अपने हितों, अपनी ऊर्जा सुरक्षा और अपनी वित्तीय संप्रभुता को सर्वोपरि रखना। यही कारण है कि रूस–भारत भुगतान संपर्क सिर्फ तकनीकी जोड़ नहीं बल्कि शक्ति-मानचित्र का पुनर्संरेखन है, जहाँ एशिया महज़ बाज़ार नहीं बल्कि निर्णयकर्ता बनकर उभर रहा है।

रूस और भारत का यह कदम दुनिया को तीन बातें स्पष्ट संदेश देता है — वित्तीय स्वतंत्रता अब कूटनीति का परिशिष्ट नहीं, बल्कि शक्ति का केंद्र है; डिजिटल भुगतान महासागर है जिसे पुराने साम्राज्य बाँध नहीं पाएँगे; और ग्लोबल साउथ अब उपभोक्ता नहीं, बल्कि निर्माता है।

संक्षेप में, पश्चिम अभी भी प्रतिबंधों की दीवारें खड़ी कर रहा है, जबकि भारत और रूस नए गलियारे बना रहे हैं। भविष्य उन दीवारों का नहीं जो विश्व को विभाजित करती हैं, बल्कि उन रास्तों का है जो दो महाद्वीपों को जोड़ते हैं और पूरी प्रणाली को बदल डालते हैं। यह सिर्फ वित्तीय सुविधा नहीं — यह एक नई विश्व-व्यवस्था का प्रारंभिक खाका है।

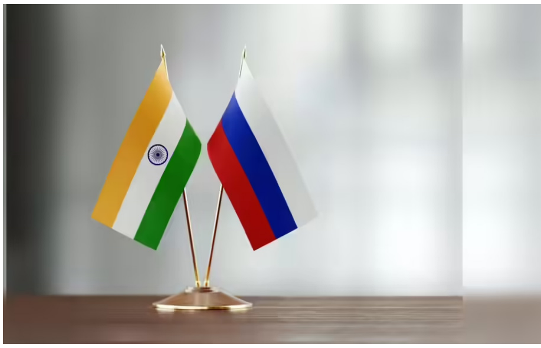

Ajesh

srirajesh.journalist @srirajesh cultcurrent@gmail.com

# आखिर इस हवा की दवा क्या है ?

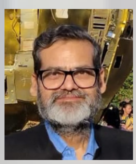

संजय श्रीवास्तव

**चीन ने वायु प्रदूषण से निबटने के लिए हमारा साथ देने का वादा किया है। जहरीली हवा से बहुत से देश और उनके शहरों ने अपनी कोशिशों से निजात पाई है, पर क्या इस दूषित वायु की उपचार प्रणाली हमें भी रास आयेगी, उनकी दवा हम पर भी असरदार होगी? या फिर हमें अपनी व्यवस्था, सरकार, समाज, मिजाज वाला कोई इलाज तलाशना होगा ?**

पृथ्वी पर सबसे जहरीली हवा हमारी राजधानी की है जिसके बाद आने वाला शहर उससे तकरीबन तीन गुने पीछे है। नई दिल्ली की हवा में ज़हर घुला है', हर साल अक्तूबर से फरवरी तक यह खबर मीडिया में तकरीबन रोज रिपीट होती है। इसकी निरंतरता प्रमाण है कि हम इस जहर के प्रति उदासीन हैं। डब्ल्यूएचओ ने साल 2016 के लिए दुनिया के सबसे 15 प्रदूषित शहरों की सूची जारी की तो भारत के 14 शहर उसमें शामिल थे। नीले की बजाए भूरे, धूसर रंग के आसमान वाली दिल्ली अव्वल थी, आज 2025 में भी हमने अपनी यह जगह बरकरार रखी है।

संसार में हमारी राजधानी की हवा का कोई मुकाबला नहीं। सर्दियों में इसकी हवा विश्व स्वास्थ्य संगठन के मानक से दस गुना और राष्ट्रीय मानक से तीन गुना खराब बनी रहती है। राजधानी में एयर क्वालिटी इंडेक्स 500 के पार और उसके कुछ इलाके बहुधा 700 भी पार कर जाते हैं। कभी 177 प्रदूषित देशों में हमारा स्थान 155वां था,फिर 180 में 176 आज 183 देशों में 177वां। जनमानस में यह धारण बलवती है कि दिल्ली की अथवा बड़े औद्योगिक शहरों की हवा ही ज़हरीली है या फिर कभी कभार समाचार में आने वाले कुछ छोटे बड़े शहरों की हवा के अलावा बाकी दुरुस्त है, पर ऐसा नहीं है।

राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, हरियाणा सहित दक्षिणी राज्यों का भी शायद ही कोई शहर एयर क्वालिटी इंडेक्स पर 100 सूचकांक से नीचे नजर आए, यह खराब की श्रेणी में ही है, पर 500 से 700 के मुकाबले संतोषजनक। देश ज्यादातर शहरी 200 से 400 के बीच बेहद खराब और जानलेवा हवा के बीच जी रहे होते हैं वे यह सोच भी नहीं सकते कि नार्वे के ओस्लो का औसत एक्यूआई मान महज 1 से 2 तक, ऑटो इंडस्ट्री के चलते कभी वायु प्रदूषण के लिए कुख्यात डेट्रॉइट का 8, व्यस्त तटीय शहर भारी वाहन यातायात, औद्योगिक गतिविधियों के लिये जाना जाने वाला अल्जीरिया के अल्जीयर्स का 11, आस्ट्रेलिया के सिडनी का 16, साल्ट लेक सिटी का 17 भी हो सकता है। भारतीय नगरों के नागरिक तो क्या ग्रामीण भी शायद यह कभी महसूस न कर पाएंगे कि ऐसी हवा कैसी होती है। ऐसा ही रहा तो कुछ बरसों में देश के औद्योगिक शहरों का वातावरण दमघोंटू हो जायेगा। सवा दशक पहले के बीजिंग, हैबई और तिंजियान जैसे कुछ शहरों की तरह अस्पतालों के बेड़ वायु प्रदूषण प्रभावित बीमारों से भर जायेंगे, लोग केन या पाउच में अपनी साफ हवा लेकर चलेंगे। एयर प्यूरीफायर, ह्यूमिडिफायर, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रीसिपिटेटर और कैटालिस्ट कनवर्टर, डीह्यूमिडिफायर और उन्नत फ़िल्टरेशन सिस्टम, खास तरह के मास्क, पोर्टेबल ऑक्सीजन कैन, जैसे उत्पादों वाला प्रदूषण का बाजार फलफूल रहा होगा। भले सरकार की हो या समाज की, यह लापरवाही आत्मघाती है, पर प्रश्न है कि इसका करें क्या? इस हवा के इलाज की कोई अकसीर दवा भी है? क्या अपने शहरों का सैकड़ों के सूचकांक वाले वायु प्रदूषण को दहाई तक लाने वाले देशों ने जो उपाय अपनाए हमारी सरकार क्यों नहीं कर रही? क्या हमें वे उपाय रास नहीं आएंगे अथवा हम उसे करना नहीं चाहते?

चीन, यूरोप और अमेरिका में आम तौर पर एयर क्वालिटी इंडेक्स 100 के ऊपर जाते ही तात्कालिक सुधारात्मक उपाय शुरू कर दिए जाते हैं। नॉर्वे ने जीवाश्म ईंधन चालित वाहनों को बड़े पैमाने पर घटा इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहित किया तो कोलंबिया ने अपनी राजधानी बोगोटा में सार्वजनिक बस नेटवर्क का विद्युतीकरण करने के साथ साइकिल के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर वायु प्रदूषण पर काबू पाया। पर हमारे लिए चीन एक संभावित मॉडल लगता है क्योंकि दोनों के लिए विकास और शहरीकरण वायु प्रदूषण के समान कारक हैं। उसने दीर्घ अवधि की नीतियाँ और त्वरित क्रियाओं को मिलाकर लागू किया। भौगोलिक उपायों के तहत शहरों में विंड-वेंटीलेशन कॉरिडोर बनाया, ताकि स्मॉग जमा न हो सके। स्टील उत्पादन, सीमेंट निर्माण जैसे भारी प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों को बंद या अपग्रेड किया अथवा कहीं दूर स्थानांतरित कर दिया साथ ही उद्योगों को पर्यावरण प्रोटोकॉल का पालन करने के लिए मजबूर किया। शहरों को अपनी वायु गुणवत्ता मानकों में सुधार के लिए प्रेरित किया तथा रिन्यूएबल एनर्जी और स्वच्छ प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देते हुये कोयले का इस्तेमाल न्यून किया, स्वच्छ ऊर्जा जैसे नेचुरल गैस, सोलर पावर का उपयोग बढाया, पुराने वाहनों को सड़कों से हटा कर इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा दिया। वायु गुणवत्ता के लिए और अधिक कठोर मानक ही नहीं पेश किया बल्कि कड़ी निगरानी व्यवस्था के साथ विचलन पर कठोर दंड लगाया। दंडात्मक दृष्टिकोण ने जवाबदेही की संस्कृति को बढ़ाया। उसने 'ग्रेट ग्रीन वॉल' जैसी बड़ी वृक्षारोपण परियोजनाएं चलायी इसके अलावा ऊर्जा प्रणाली में सुधार, उद्योगों में प्रदूषण नियंत्रण और स्वच्छ ऊर्जा का उपयोग बढ़ाने वाली उसकी तीन वर्षीय ब्लू स्काई योजना बेहद सफल साबित हुई। इसने बहुत से शहरों में वायु प्रदूषण लगभग 60 फीसदी तक कम किया। चीनी नीतियों ने चार साल के भीतर बीजिंग सहित कई शहरों का वायु प्रदूषण 35 प्रतिशत सालाना तक घटा लिया।

चीन में हवा की गुणवत्ता के आंकड़े बिना हेरफेर के रीयल टाइम जारी होते हैं, 72 घंटे पहले बता दिया जाता है कि हवा में प्रदूषण की मात्रा कितनी रहने वाली है। पोल्यूशन इमरजेंसी लगा कर स्कूल बंद करना, वाहनों पर प्रतिबंध लगाना, नागरिकों को सार्वजनिक स्वास्थ्य अलर्ट भेजना शुरू हो जाता है। चीनी सरकार ने वायु और सौर ऊर्जा में भारी निवेश किया है। इसके चलते सैकड़ों में रहने वाला एक्यूआई दहाई तक पहुंचा है। चीन की सफलता उल्लेखनीय है। उसने हमें वायु प्रदूषणॅ से निबटने में सहयोग का वादा भी किया है। सरकार सीमा और दूसरे विवाद को भुला कर उसके प्रस्ताव का स्वागत अवश्य करेगी। पर सवाल यह है कि क्या उसकीउपचार प्रणाली हमारी हवा का भी इलाज बन पायेगी? हम चीन की तरह संयमित, सख्त वायु-प्रदूषण नियंत्रण रणनीति अपना सकेंगे? पर्यावरणीय स्वास्थ्य की कीमत पर होने वाले औद्योगिक विकास को थामना, कॉरपोरेट को पर्यावरणीय नियमों में ढील देना रुकेगा? पर्यावरण मंत्रालय का घटा हुआ बजट, वैज्ञानिक अनुसंधान बढ़ पायेगा? इस मद में राज्यों को आवंटित बजट पूरा खर्च करने पर बाध्य करने के अलावा केंद्र राज्यों को साधन संसाधन देकर इस बावत दीर्घकालिक योजना चलवाएगी? बिजली चालित वाहनों को बढ़ावा देने के लिए लाखों चार्जिंग स्टेशन और उनके लिए विद्युत आपूर्ति के लिए सरकार कितनी तैयार है? चीन की तरह मज़बूत पर्यावरणीय निगरानी, वोट और चुनावी चंदे के प्रबंधक कारपोरेट, उद्योग आदि के प्रति कठोर दंड व्यवस्था कितना आसान होगा? आम जन न इसकी भयावहता के बारे में न जागरूक हैं न चिंतित और सतर्क। तिस पर सरकार के लिए यह वोट का मुद्दा नहीं है ऐसे में शासन तंत्र की जवाबदेही और नागरिक जागरूकता का स्तर कैसे बढ़ेगा?

साफ बात यह भी कि जब तक वायु प्रदूषण की शिकार जनता खुद इसके लिये आंदोलन कोशिश नहीं करेगी तब तक किसी की सहायता से अथवा कोई मॉडल अपनाने से बड़ा बदलाव लाना मुश्किल है। हम हवा को पानी की तरह पीने का और अन्य काम आने वाले पानी की तरह वर्गीकृत करके उसकी आपूर्ति नहीं कर सकते। हमें समूचे वायुमंडल को सांस लेने लायक बनाने के लिए किसी उधारी मॉडल की बजाए आत्मनिर्भर हो कर अपने देश समाज व्यवस्था के अनुरूप योजना बनानी चाहिये ईमानदारी तथा पूरी ईच्छाशक्ति से अभियान चलाना चाहिये इस हवा की यही दवा है।

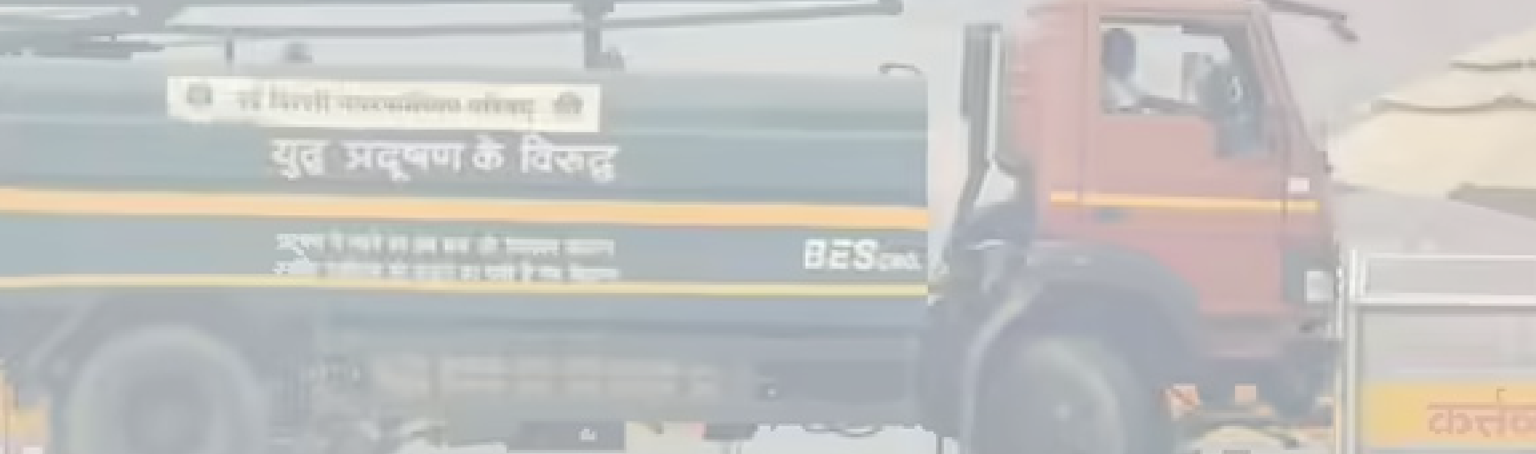

# दिल्ली ब्लास्ट 10/11

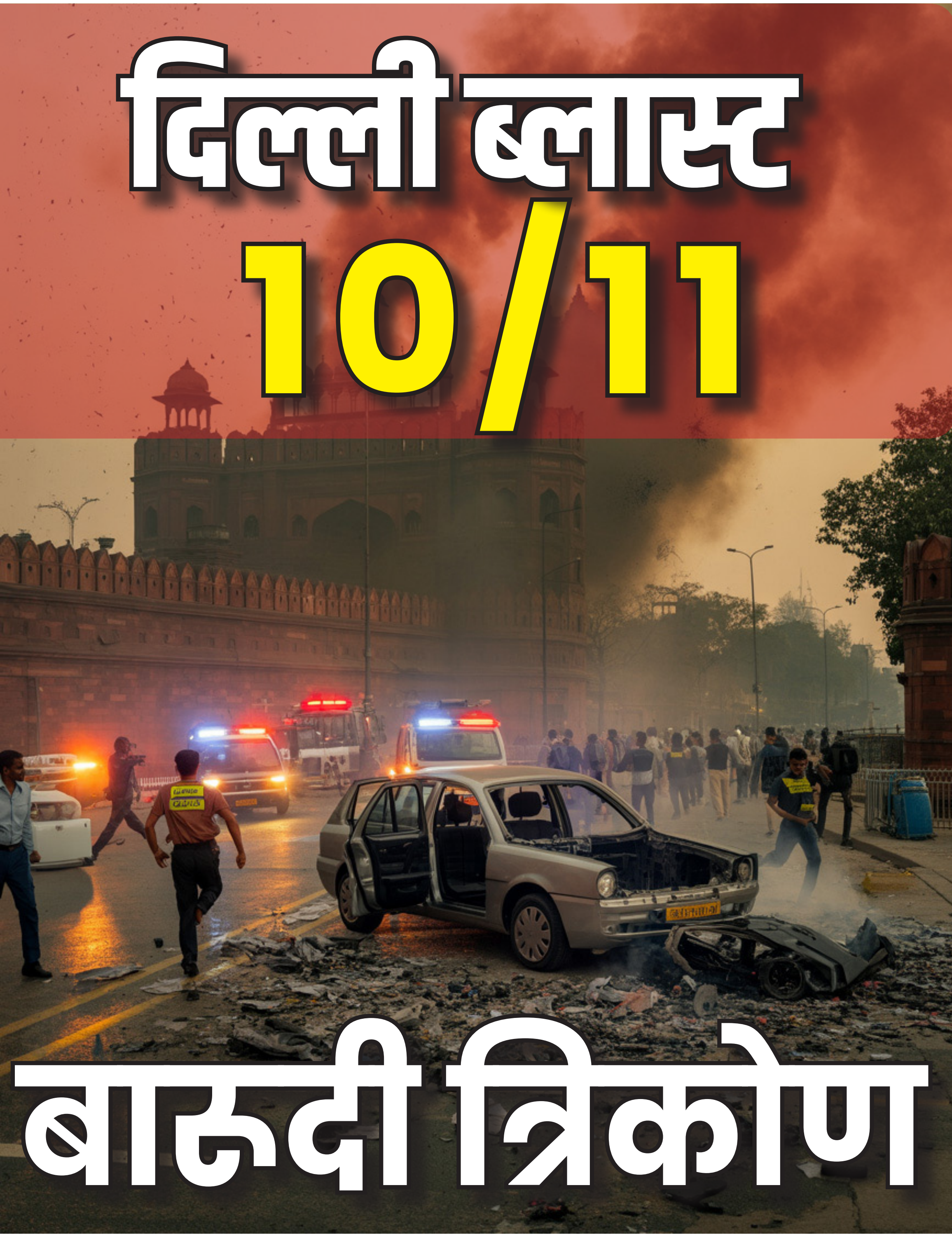

# बारूदी त्रिकोण

संतोष कुमार

लाल किले की प्राचीर पर 10 नवंबर की शाम केवल धमाका नहीं हुआ, बल्कि देश का भरोसा भी लहुलूहान हुआ। जब 'धरती के भगवान' कहे जाने वाले डॉक्टर ही मौत के सौदागर बन जाएं, तो समाज कहां जाए? यह 'सफेदपोश आतंक' तुर्की-पाक-बांग्लादेश गठजोड़ की वह नई प्रयोगशाला है, जिसने भारत की सुरक्षा-नीति को झकझोर कर रख दिया है।

10 नवंबर, 2025 की शाम जब दिल्ली का आसमान धुंध और ऐतिहासिक लाल किले की रोशनी में नहाया हुआ था, ठीक उसी वक्त एक भीषण विस्फोट ने न केवल राजधानी की धरती को हिला दिया, बल्कि भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के विमर्श को एक नए और खौफनाक अध्याय में धकेल दिया। लाल किला, जो भारत की संप्रभुता और शक्ति का प्रतीक है, उसके साये में हुआ यह हमला महज एक विस्फोट नहीं था; यह भारतीय लोकतंत्र और उसकी सुरक्षा एजेंसियों के लिए एक खुली चुनौती थी। हुंडई आई20 कार के परखच्चे उड़ने के साथ ही 14 निर्दोष जानें चली गईं, लेकिन धुएं के गुबार के छठने के बाद जो सच सामने आया, वह बारूद की गंध से भी ज्यादा जहरीला था।

यह हमला किसी अनपढ़, भटके हुए युवा द्वारा नहीं, बल्कि समाज के सबसे प्रतिष्ठित पेशे से जुड़े लोगों—'डॉक्टरों'—द्वारा रचा गया था। स्टेथोस्कोप थामने वाले हाथ जब डेटोनेटर थाम लें, तो समझ लेना चाहिए कि आतंकवाद ने अपनी रणनीति बदल ली है। इसे सुरक्षा एजेंसियों ने 'व्हाइट कॉलर टेरर' का नाम दिया है। लेकिन इस घटना की परतें जैसे-जैसे खुल रही हैं, जांच की सुई सिर्फ पाकिस्तान पर नहीं रुक रही, बल्कि तुर्की के अंकारा से लेकर बांग्लादेश की सीमाओं तक एक बड़े अंतरराष्ट्रीय षड्यंत्र का नक्शा खींच रही है।

## डॉक्टर मॉड्यूल: 'धरती के भगवान' या मौत के सौदागर?

इस त्रासदी का सबसे विचलित करने वाला पहलू 'फरीदाबाद डॉक्टर मॉड्यूल' है। जांच में मुख्य आरोपी डॉ. उमर उन-नबी (जिसका शरीर विस्फोट में चिथड़े हो गया) और उसके सहयोगियों—डॉ. मुजम्मिल, डॉ. शाहीन शाहिद (मैडम सर्जन)—की भूमिका ने यह साबित कर दिया है कि कट्टरपंथ अब मदरसों की चारदीवारी से निकलकर मेडिकल कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के वातानुकूलित कमरों तक पहुंच गया है।

अल-फलाह यूनिवर्सिटी, फरीदाबाद, जो शिक्षा का केंद्र होनी चाहिए थी, वह इस आतंकी नेटवर्क का 'नर्व सेंटर' बन गई। यह बेहद चिंताजनक है कि डॉ. उमर, जिसे एक मरीज की मौत के कारण कश्मीर के अनंतनाग अस्पताल से निकाला गया था, वह दिल्ली-एनसीआर में विस्फोटक से भरी कार लेकर 11 घंटे तक बेखौफ घूमता रहा। यह तथ्य हमारी जमीनी खुफिया तंत्र और तकनीकी निगरानी की एक गंभीर चूक की ओर इशारा करता है।

डॉक्टरों का आतंकी नेटवर्क में शामिल होना जैश-ए-मोहम्मद की एक सोची-समझी 'टैलेंट हंट' रणनीति का हिस्सा है। डॉक्टर होने के नाते उन्हें रसायनों (जैसे अमोनियम नाइट्रेट) तक आसान पहुंच मिलती है, समाज में उन पर शक कम किया जाता है, और वे अपनी कमाई से संगठन की फंडिंग भी कर सकते हैं। डॉ. शाहीन शाहिद का 'मैडम सर्जन' के रूप में महिला विंग का नेतृत्व करना यह दर्शाता है कि जेंडर और प्रोफेशन अब आतंकी प्रोफाइलिंग के पुराने मानकों को ध्वस्त कर चुके हैं।

## 'उकासा' का जाल: तुर्की कनेक्शन और एर्दोगान का तुर्क विजन

लाल किला ब्लास्ट की जांच में जो सबसे विस्फोटक खुलासा हुआ है, वह है—तुर्की कनेक्शन। 'उकासा' (अरबी में जिसका अर्थ मकड़ी होता है) नाम का हैंडलर अंकारा में बैठकर इस पूरे नेटवर्क को निर्देशित कर रहा था। जांच एजेंसियों के अनुसार, आरोपी 2022 में तुर्की गए थे, जहां उनकी मुलाकात विदेशी आकाओं से हुई।

तुर्की का इस षड्यंत्र में शामिल होना भारत के लिए महज एक

आपराधिक मामला नहीं, बल्कि एक भू-राजनीतिक चेतावनी है। पिछले कुछ वर्षों में, रेचब तैयब एर्दोगान के नेतृत्व में तुर्की ने खुद को इस्लामी दुनिया का नया खलीफा बनाने की महत्वाकांक्षा पाली है। कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान का मुखर समर्थन और अब भारतीय जमीन पर आतंकी हमलों के लिए लॉजिस्टिक्स और फाइनेंशियल हब के रूप में अंकारा का इस्तेमाल, भारत-तुर्की संबंधों में एक 'टर्निंग पॉइंट' है।

तुर्की का इस्तेमाल 'रिमोट कंट्रोल' की तरह किया जा रहा है। 'सेशन' जैसे हाई-एनक्रिप्शन ऐप्स के जरिए अंकारा से फरीदाबाद तक निर्देश भेजे जा रहे थे। यह साबित करता है कि तुर्की अब केवल पाकिस्तान का कूटनीतिक मित्र नहीं है, बल्कि भारत के खिलाफ हाइब्रिड वॉरफेयर में एक सक्रिय भागीदार बन चुका है। भारत को अब यह स्वीकार करना होगा कि पश्चिम एशिया में उसका एक नया और सक्षम दुश्मन खड़ा हो रहा है, जो नाटो का सदस्य होने के कवच का फायदा उठाता है।

## पाकिस्तान: पुराना दुश्मन, नई चालें

भले ही हैंडलर तुर्की में बैठा हो, लेकिन आतंकी विचारधारा और बारूद की गंध का स्रोत अभी भी पाकिस्तान ही है। 68 संदिग्ध मोबाइल नंबर, जो विस्फोट के वक्त लाल किला और पार्किंग क्षेत्र में सक्रिय थे, उनके तार पाकिस्तान और तुर्की के 'आईपी क्लस्टर्स' से जुड़े मिले हैं। 'सर्वर हॉपिंग' और 'वर्चुअल नंबरों' का इस्तेमाल कर जैश-ए-मोहम्मद ने यह सुनिश्चित करने की कोशिश की कि डिजिटल पदचिह्न मिटा दिए जाएं।

पोस्टर में 'ऑपरेशन सिंदूर' के जवाब और 6 दिसंबर (बाबरी विध्वंस की बरसी) के आसपास बड़े हमले की योजना ('डी-6 मिशन') यह बताती है कि पाकिस्तान का 'डीप स्टेट' (आईएसआई और सेना) भारत की आंतरिक स्थिरता को भंग करने के लिए अब सांप्रदायिक प्रतीकों का सहारा ले रहा है। यह हमला भारत की आर्थिक प्रगति और वैश्विक छवि को धूमिल करने का एक हताश प्रयास है।

## बांग्लादेश: तीसरा मोर्चा और 'एनसर्कलमेंट' का खतरा

लश्कर-ए-तैयबा के कमांडर सैफुल्लाह सैफ का यह दावा कि 'बांग्लादेश को लॉन्चपैड के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा,' भारत के लिए खतरे की घंटी है। बांग्लादेश में राजनीतिक अस्थिरता और कट्टरपंथी तत्वों के उभार का फायदा उठाकर पाकिस्तान वहां अपनी जड़ें जमा रहा है।

अगर हम तुर्की-पाकिस्तान-बांग्लादेश के इस गठजोड़ को एक साथ देखें, तो यह भारत की 'चिकन नेक' (सिलीगुड़ी कारिडोर) और पूर्वी सीमाओं के लिए एक गंभीर रणनीतिक खतरा है। इसे भारत की 'घेराबंदी' की रणनीति कहा जा सकता है। पश्चिम में पाकिस्तान, उत्तर-पश्चिम में तुर्की का डिजिटल और लॉजिस्टिक समर्थन, और पूर्व में बांग्लादेश का संभावित लॉन्चपैड—यह त्रिकोण भारत की सुरक्षा एजेंसियों के लिए 'थ्री-फ्रंट वॉर' जैसी स्थिति पैदा कर सकता है, जो पारंपरिक युद्ध न होकर 'आतंक और विद्रोह' का युद्ध होगा।

## तकनीकी युद्ध और खुफिया विफलता: एक आत्मविश्लेषण

इस हमले ने यह भी उजागर किया है कि हम 'फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर' के दौर में जी रहे हैं। टेलीग्राम, सिग्नल और सेशन जैसे ऐप्स के जरिए आतंकी संचार को पकड़ना मुश्किल हो रहा है। 'उकासा' जैसे हैंडलर तुर्की में बैठकर भारत में एक डॉक्टर को आत्मघाती हमलावर बना देते हैं, और हमारी एजेंसियां अंधेरे में रहती हैं। 300 किलो विस्फोटक अभी

भी गायब है। एक कार विस्फोटक लेकर राजधानी के सबसे संवेदनशील इलाकों (इंडिया गेट, कर्तव्य पथ) से गुजरती है और पकड़ी नहीं जाती। यह 'बीट पुलिसिंग' और 'इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस' के बीच के तालमेल की कमी को दर्शाता है। यह प्रश्न उठना लाजमी है कि क्या हम तकनीकी रूप से इतने सक्षम हैं कि 'सर्वर हॉपिंग' और 'डेटा स्पाइक्स' को रियल टाइम में डिकोड कर सकें?

## भावनात्मक और सामाजिक प्रभाव: विश्वास का संकट

एक भारतीय नागरिक के दृष्टिकोण से, यह घटना दिल को तोड़ने वाली है। डॉक्टर, जिसे समाज 'मसीहा' मानता है, अगर वही जान लेने पर आमादा हो जाए, तो आम आदमी किस पर भरोसा करेगा? यह केवल सुरक्षा का संकट नहीं है, यह एक सामाजिक विश्वास का संकट है। जब उच्च शिक्षित वर्ग—इंजीनियर, डॉक्टर, प्रोफेसर—कट्टरपंथ की राह चुनते हैं, तो यह उस तर्क को खारिज करता है कि गरीबी और अशिक्षा ही आतंकवाद की जड़ है। यह एक वैचारिक वायरस है, जो अब बौद्धिक वर्ग को संक्रमित कर रहा है।

## भारत की प्रतिक्रिया और कूटनीतिक चुनौतियां

इस घटना के बाद भारत की विदेश नीति और सुरक्षा नीति में आमूलचूल परिवर्तन की आवश्यकता है। भारत को तुर्की के साथ अपने संबंधों की समीक्षा करनी होगी। राजनयिक स्तर पर यह संदेश देना होगा कि अंकारा का इस्तेमाल भारत विरोधी गतिविधियों के लिए होना बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। भारत को तुर्की के विरोधियों (जैसे ग्रीस, साइप्रस और आर्मेनिया) के साथ रणनीतिक साझेदारी को और गहरा करना चाहिए। वहीं सर्जिकल स्ट्राइक या एयर स्ट्राइक के अलावा, भारत को पाकिस्तान को कूटनीतिक और आर्थिक रूप से अलग-थलग करने की नीति जारी रखनी होगी। अब समय आ गया है कि 'साइबर और स्पेस' डोमेन में पाकिस्तान के खिलाफ आक्रामक क्षमता विकसित की जाए। साथ ही साथ ढाका में सरकार चाहे किसी की भी हो, भारत को वहां के सुरक्षा तंत्र के साथ मिलकर यह सुनिश्चित करना होगा कि बांग्लादेश की धरती का इस्तेमाल भारत के खिलाफ न हो।

अब इस घटना के बाद अल-फलाह यूनिवर्सिटी जैसे संस्थानों की गहन जांच आवश्यक है। शैक्षणिक संस्थानों में कट्टरपंथ की घुसपैठ को रोकने के लिए सख्त निगरानी तंत्र बनाना होगा। साथ ही, गायब 300 किलो विस्फोटक को ढूंढना अब राष्ट्रीय प्राथमिकता होनी चाहिए, वरना खतरा अभी टला नहीं है।

## मकड़जाल काटने के लिए अपनाना होगा 'चाणक्य नीति'

लाल किले की दीवारों पर लगे धुएं के निशान शायद बारिश में धुल जाएं, लेकिन इस हमले ने जो सवाल खड़े किए हैं, वे आसानी से नहीं मिटेंगे। डॉ. उमर उन-नबी की कार का विस्फोट सिर्फ आरडीएक्स का धमाका नहीं था; यह उस भ्रम का भी विस्फोट था कि हम सुरक्षित हैं।

आज भारत एक ऐसे चौराहे पर खड़ा है जहां उसे अपनी सीमाओं की रक्षा के साथ-साथ अपने समाज के भीतर पनप रहे 'स्लीपर सेल्स' से भी लड़ना है। तुर्की से लेकर पाकिस्तान तक फैले इस मकड़जाल को काटने के लिए भारत को 'चाणक्य नीति' और आधुनिक तकनीक का एक अभूतपूर्व मिश्रण अपनाना होगा। यह लड़ाई अब केवल सैनिकों की नहीं, बल्कि हर जागरूक नागरिक, खुफिया अधिकारी और नीति निर्माता की है। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि लाल किले की प्राचीर से गूंजने वाली आवाज हमेशा 'जय हिंद' की हो, न कि किसी आतंकी विस्फोट की।

यह समय भावुक होने का भी है और कठोर होने का भी। हमारे 14 नागरिकों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। यह रक्तपात भारत को झुका नहीं सकता, बल्कि यह हमारे संकल्प को और फौलादी बनाएगा—आतंक के हर उस हाथ को तोड़ने के लिए, चाहे वह रावलपिंडी में हो, अंकारा में हो, या हमारे अपने पड़ोस के किसी क्लिनिक में।

# पूर्वी मोर्चा
# गहराता भू-संकट

पूर्वी मोर्चा एक बार फिर उबलने लगा है। ढाका की गलियों से उठता कट्टरपंथ, पाकिस्तान–तुर्की–चीन की छाया और सिलीगुड़ी पर बढ़ती भू-रणनीतिक नजरें—ये सब मिलकर दक्षिण एशिया में शक्ति-संतुलन को विस्फोटक मोड़ पर ला खड़ा कर रहे हैं। भारत अब प्रतिक्रिया नहीं, रणनीतिक प्रतिघात के मोड में है।

संदीप कुमार

दक्षिण एशिया का भू-राजनीतिक मानचित्र इस समय एक अभूतपूर्व और विस्फोटक परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है। भारत के पूर्वी पड़ोस में स्थित बांग्लादेश, जिसे कभी 1971 के मुक्ति संग्राम के बाद धर्मनिरपेक्षता और भाषाई राष्ट्रवाद का एक मॉडल माना जाता था, आज अपनी ही पहचान के अस्तित्वगत संकट से जूझ रहा है। ढाका में सत्ता परिवर्तन के बाद जिस तरह की अराजकता, कट्टरपंथ और भारत विरोधी भावनाओं का ज्वार उठा है, उसने नई दिल्ली के साउथ ब्लॉक में खतरे की घंटी बजा दी है। शेख हसीना को सुनाई गई मौत की सजा और अवामी लीग के नेतृत्व के खिलाफ चल रहा प्रतिशोध का दौर केवल एक आंतरिक राजनीतिक घटनाक्रम नहीं है, बल्कि यह भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक गंभीर

चुनौती का संकेत है। इस बदलते परिदृश्य में, जहां एक ओर बांग्लादेश में पाकिस्तान और अन्य विदेशी शक्तियों का प्रभाव बढ़ रहा है, वहीं दूसरी ओर भारत ने अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सिलीगुड़ी कॉरिडोर से लेकर चटगांव तक एक नई और आक्रामक रणनीतिक बिसात बिछाना शुरू कर दिया है।

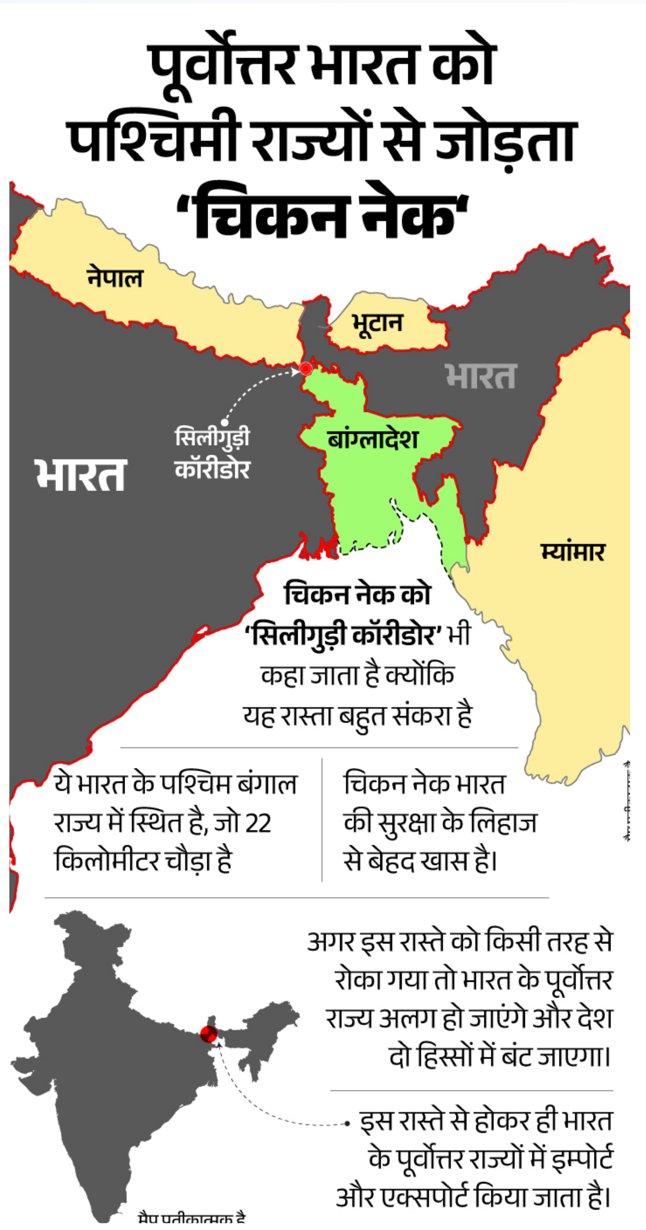


## बांग्लादेश का आंतरिक पतन और कट्टरपंथ का नया अध्याय

वर्तमान में बांग्लादेश जिस दौर से गुजर रहा है, उसे केवल राजनीतिक अस्थिरता कहना स्थिति की गंभीरता को कम करके आंकना होगा। यह एक वैचारिक तख्तापलट है। शेख हसीना की सरकार के पतन के बाद बनी अंतरिम सरकार, जिसका नेतृत्व मोहम्मद यूनुस कर रहे हैं, देश को स्थिरता प्रदान करने के बजाय कट्टरपंथी तत्वों के हाथों की कठपुतली बनती दिख रही है। 2013 की प्रत्यर्पण संधि का हवाला देकर शेख हसीना की वापसी की मांग करना एक कूटनीतिक दबाव की रणनीति है, लेकिन इसके पीछे की मंशा प्रतिशोध से प्रेरित है। इससे भी अधिक चिंताजनक बात यह है कि बांग्लादेश में प्रतिबंधित संगठन हिज्ब-उत-तहरीर जैसे समूह अब खुलेआम ढाका की सड़कों पर 'खिलाफत' की मांग करते हुए रैलियां निकाल रहे हैं। जमात-ए-इस्लामी, जो कभी हाशिये पर थी, अब मुख्यधारा की राजनीति और छात्र संगठनों के साथ तालमेल बिठाकर अपनी जड़ें जमा रही है।

इस कट्टरपंथ का सबसे पहला और आसान शिकार वहां का अल्पसंख्यक समुदाय, विशेषकर हिंदू, बन रहा है। अगस्त 2024 से जून 2025 के बीच 2400 से अधिक हेट-क्राइम के मामले दर्ज होना यह दर्शाता है कि राज्य मशीनरी या तो लाचार है या फिर इन तत्वों को मूक समर्थन दे रही है। बांग्लादेश की स्थापना जिस धर्मनिरपेक्षता के आधार पर हुई थी, उसे सुनियोजित तरीके से ध्वस्त किया जा रहा है। यह सामाजिक और जनसांख्यिकीय परिवर्तन भारत के पूर्वोत्तर राज्यों के लिए सीधा खतरा है, क्योंकि इतिहास गवाह है कि जब भी ढाका में कट्टरपंथ हावी हुआ है, उसका सीधा असर भारत में घुसपैठ और उग्रवाद के रूप में देखने को मिला है।

## पाकिस्तान की वापसी और विदेशी शक्तियों का अखाड़ा

भारत के लिए सबसे बड़ी सामरिक चिंता बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच बढ़ते प्रगाढ़ संबंध हैं। 1971 के घावों को भुलाकर, या यूं कहें कि एक नए भारत-विरोधी एजेंडे के तहत, पाकिस्तानी सेना और खुफिया एजेंसी आईएसआई ने ढाका में अपनी सक्रियता बढ़ा दी है। पिछले एक वर्ष में पाकिस्तानी सेना के उच्च अधिकारियों, जिनमें ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी के चेयरमैन

**यदि बांग्लादेश या वहां सक्रिय विदेशी शक्तियां भारत की 'चिकन नेक' (सिलीगुड़ी) को दबाने की कोशिश कर रही हैं, तो भारत ने भी जवाबी कार्रवाई के लिए बांग्लादेश की दो दुखती रगों—रंगपुर और चटगांव—को चिन्हित कर लिया है। इसे हम भारत की 'टू-नेक' रणनीति कह सकते हैं।**

और नौसेना प्रमुख शामिल हैं, उनका बांग्लादेश दौरा करना सामान्य कूटनीतिक शिष्टाचार नहीं है। यह एक रणनीतिक धुरी का निर्माण है। अतीत में पाकिस्तान ने बांग्लादेश की भूमि का उपयोग भारत के पूर्वोत्तर उग्रवादियों को पनाह देने और आतंकी गतिविधियों को संचालित करने के लिए 'लॉन्चपैड' के रूप में किया था। अब आईएसआई की वापसी और ढाका में सीआईए, तुर्की के इंटेलिजेंस और चीनी एजेंसियों की बढ़ती गतिविधियों ने बांग्लादेश को एक अंतरराष्ट्रीय खुफिया अखाड़े में तब्दील कर दिया है। यह भारत को घेरने की एक बड़ी साजिश का हिस्सा प्रतीत होता है, जहां बांग्लादेश की जमीन का इस्तेमाल भारत के खिलाफ 'छद्म युद्ध' के लिए किया जा सकता है।

## सिलीगुड़ी कॉरिडोर: भारत की 'चिकन नेक' पर संकट

इस भू-राजनीतिक अस्थिरता के केंद्र में भारत का सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, जिसे सामरिक भाषा में 'चिकन नेक' कहा जाता है। यह संकरा गलियारा भारत की मुख्य भूमि को उसके पूर्वोत्तर राज्यों से जोड़ता है। हाल ही में मोहम्मद यूनुस द्वारा 'ग्रेटर बांग्लादेश' की अवधारणा को हवा देना और नक्शे में पूर्वोत्तर भारत के हिस्सों को बांग्लादेश के प्रभाव क्षेत्र में दिखाना, भारत की संप्रभुता पर सीधा प्रहार है। यह केवल एक नक्शा नहीं है, बल्कि यह उस महत्वाकांक्षा का प्रदर्शन है जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर को काट कर भारत को उसके पूर्वोत्तर भाग से अलग करने का सपना देख रही है।

इस खतरे को भांपते हुए भारतीय सुरक्षा प्रतिष्ठान अब रक्षात्मक मुद्रा से बाहर निकलकर आक्रामक तैयारी में जुट गया है। सिलीगुड़ी में पिछले कुछ दिनों से चल रही उच्च-स्तरीय बैठकें सामान्य नहीं हैं। इन बैठकों में सशस्त्र बलों के शीर्ष अधिकारी, मिलिट्री इंटेलिजेंस, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग और इंटेलिजेंस ब्यूरो के अधिकारियों की मौजूदगी यह बताती है कि भारत किसी भी दुस्साहस का जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार है। सिलीगुड़ी और उसके आसपास के क्षेत्रों में राफेल, सुखोई-30 एमकेआई लड़ाकू विमानों, एस-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम और ब्रह्मोस मिसाइलों की तैनाती यह संदेश देती है कि भारत अब केवल कूटनीतिक विरोध दर्ज कराने तक सीमित नहीं रहेगा। ईस्टर्न कमांड के मुख्यालय सुकना में बढ़ी हुई हलचल और जनवरी तक चलने वाले निरंतर सैन्य अभ्यास इस बात का प्रमाण हैं कि भारत 'चिकन नेक' की सुरक्षा के लिए 'जीरो टॉलरेंस' की नीति अपना रहा है।

## भारत का जवाबी दांव: 'टू-नेक' रणनीति

यदि बांग्लादेश या वहां सक्रिय विदेशी शक्तियां भारत की 'चिकन नेक' (सिलीगुड़ी) को दबाने की कोशिश कर रही हैं, तो भारत ने भी जवाबी कार्रवाई के लिए बांग्लादेश की दो दुखती रगों—रंगपुर और चटगांव—को चिन्हित कर लिया है। इसे हम भारत की 'टू-नेक' रणनीति कह सकते हैं। भू-राजनीतिक विश्लेषकों और सुरक्षा एजेंसियों के आकलन के अनुसार, यदि सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर दबाव बढ़ता है, तो भारत के पास चटगांव और रंगपुर डिवीजन में सक्रिय असंतोष का लाभ उठाने का रणनीतिक विकल्प मौजूद है।

चटगांव, जो ऐतिहासिक और सांस्कृतिक रूप से भारत के पूर्वोत्तर से गहरा जुड़ाव रखता है, वर्तमान में अपनी ही आंतरिक समस्याओं और स्वायत्तता की मांगों से जूझ रहा है। वहां के स्थानीय लोगों में ढाका के प्रशासन और चीनी प्रभाव के प्रति गहरा असंतोष है, विशेषकर बंदरगाह को लीज पर देने की खबरों को लेकर। भारत के लिए चटगांव एक रणनीतिक अवसर है। यदि चटगांव भारत के प्रभाव क्षेत्र में आता है या वहां भारत समर्थक माहौल बनता है, तो यह त्रिपुरा और अन्य पूर्वोत्तर राज्यों के लिए समुद्र तक सीधी पहुंच प्रदान कर

सकता है। इससे न केवल पूर्वोत्तर का 'लैंडलॉक्ड' होने का अभिशाप समाप्त होगा, बल्कि क्षेत्र की आर्थिक तस्वीर भी बदल जाएगी। त्रिपुरा मोथा जैसे संगठन पहले से ही चटगांव के साथ एकीकरण या गहरे संबंधों की वकालत करते रहे हैं।

इसी प्रकार, रंगपुर डिवीजन, जो भारत की सीमा से सटा हुआ है, सांस्कृतिक रूप से उत्तर बंगाल और असम के अधिक निकट है। भारत की रणनीति यह हो सकती है कि यदि ढाका सिलीगुड़ी पर बुरी नजर डालता है, तो भारत रंगपुर और चटगांव के रास्तों को अपने नियंत्रण या प्रभाव में लेकर बांग्लादेश को उसी की भाषा में जवाब दे। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा का यह बयान कि 'सिलीगुड़ी पर नजर मत डालो, वरना तुम्हारे दोनों गर्दन हम ले लेंगे,' महज एक राजनीतिक बयान नहीं है। यह भारत के बदलते सुरक्षा सिद्धांत का परिचायक है, जो अब सीमाओं के बदलने की संभावनाओं से इनकार नहीं करता। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का सिंध के संदर्भ में दिया गया बयान कि 'बॉर्डर कभी भी बदल जाया करते हैं,' पाकिस्तान के साथ-साथ बांग्लादेश के लिए भी एक स्पष्ट चेतावनी है।

## सुरक्षा सर्वोपरि और कूटनीति का नया दौर

बांग्लादेश में फरवरी में होने वाले संभावित चुनावों तक स्थिति और अधिक अस्थिर होने की संभावना है। भारत के लिए अब 'पड़ोसी प्रथम' की नीति का अर्थ बदल गया है। अब यह नीति 'सुरक्षा प्रथम' में परिवर्तित हो चुकी है। जिस प्रकार बांग्लादेश की जमीन पर भारत विरोधी ताकतों का जमावड़ा हो रहा है और जिस तरह से वहां की अंतरिम सरकार भारत के रणनीतिक हितों को चुनौती दे रही है, उसे देखते हुए भारत ने अपनी तैयारियों को धार देना शुरू कर दिया है।

सिलीगुड़ी कॉरिडोर में सुरक्षा एजेंसियों का अभूतपूर्व समन्वय और सैन्य तैनाती यह स्पष्ट करती है कि भारत अब किसी भी 'सरप्राइज' के लिए तैयार नहीं रहना चाहता। लाल मुनीरहाट एयरबेस पर रडार की तैनाती हो या सीमा पार से घुसपैठ की कोशिशें, भारत हर गतिविधि पर पैनी नजर बनाए हुए है। एसआईआर जैसी प्रक्रियाओं के माध्यम से आंतरिक सुरक्षा को सुदृढ़ करना और सीमा पर बाड़बंदी को मजबूत करना इसी व्यापक रणनीति का हिस्सा है।

अंततः, भारत का दृष्टिकोण अब स्पष्ट है—यदि बांग्लादेश एक मित्र पड़ोसी की तरह रहता है, तो भारत सहयोग का हाथ बढ़ाएगा, लेकिन यदि वह भारत की अखंडता और सुरक्षा के लिए खतरा बनता है, तो भारत सिलीगुड़ी की रक्षा के लिए चटगांव और रंगपुर जैसे रणनीतिक विकल्पों का उपयोग करने से नहीं हिचकिचाएगा। यह दक्षिण एशिया में शक्ति संतुलन का एक नया अध्याय है, जहां भारत अपनी संप्रभुता की रक्षा के लिए अपनी सीमाओं से परे जाकर भी रणनीतिक गहराई बनाने के लिए तैयार है। यह नया भारत है, जो अपनी 'चिकन नेक' को दबाने वाले का हाथ मरोड़ने की क्षमता और इच्छाशक्ति दोनों रखता है।

## बिहार का जनादेश

# लाभार्थी-आधारित राजनीति का उभार

चुनावी पंडितों ने तरह-तरह भविष्यवाणियां की लेकिन जातिगत समीकरणों के पुराने किले बिहार विधानसभा चुनाव में ढहते नजर आए और विरोध की हर बुलंद आवाज़ एक अनसुनी फुसफुसाहट में बदल गई। बिहार के 2025 के जनादेश ने एक ऐसी राजनीतिक सुनामी को जन्म दिया है, जिसकी लहरों के नीचे दशकों पुरानी सामाजिक संरचनाएं कांप उठी हैं। यह केवल एक गठबंधन की जीत नहीं, बल्कि उस अदृश्य मतदाता की हुंकार है, जिसे अब तक केवल आंकड़ों में गिना जाता था, पर जिसकी खामोशी में एक निर्णायक शक्ति छिपी थी।

जलज श्रीवास्तव

मिथिला के किसी धूल भरे गांव में, एक झुकी हुई कमर वाली वृद्धा, जिसकी आंखों में दशकों की कहानियां सिमटी थीं, एक पत्रकार के माइक पर झुककर कहती है, **'बउआ, नीमकहरामी नय करबइ!'** (बेटा, नमकहरामी नहीं करुँगी)। यह वाक्य किसी राजनीतिक विश्लेषक का जटिल सिद्धांत नहीं, बल्कि 2025 के बिहार जनादेश का सार है। यह उस मौन भूकम्प का केंद्रबिंदु है जिसने 243 सीटों में से 202 पर एनडीए को स्थापित कर दिया और महागठबंधन के सामाजिक समीकरणों के महाद्वीप को इतिहास के गहरे सागर में डुबो दिया। यह वृद्धा किसी एक व्यक्ति का नाम नहीं है; वह उस विशाल, अदृश्य और अब तक खामोश स्त्री-शक्ति का चेहरा है, जिसने इस चुनाव में बिहार की राजनीति का व्याकरण हमेशा के लिए बदल दिया।

हम अक्सर राजनीतिक परिवर्तनों को नारों के शोर, रैलियों के हुजूम और वाद-विवाद की गर्मी से मापते हैं। लेकिन 2025 में बिहार ने जिस बदलाव को जन्म दिया, वह 'मौन' था। यह दबे पांव आया, किसी भूगर्भिक हलचल की तरह, जिसकी सतह पर कोई कंपन महसूस नहीं हुआ, लेकिन जिसने नीचे की टेक्टोनिक प्लेटों को हमेशा के लिए विस्थापित कर दिया। विश्लेषक इसे 'एंटी-

इन्कंबेंसी' की लहर समझ रहे थे, जब मतदान केंद्रों पर महिलाओं की अभूतपूर्व लंबी कतारें लगीं। वे इसे सत्ता परिवर्तन का संकेत मान रहे थे। लेकिन यह एक 'प्रो-इन्कंबेंसी' सुनामी थी, जो नीतीश कुमार के दो दशकों के सामाजिक निवेश और नरेंद्र मोदी के 'लाभार्थी' मॉडल के संगम से पैदा हुई थी। यह एक ऐसा अदृश्य युद्ध था, जिसे जाति के पारंपरिक हथियारों से नहीं, बल्कि राशन कार्ड, पेंशन की बढ़ी हुई राशि और बैंक खातों में सीधे भेजे गए दस हजार रुपयों से लड़ा गया।

आइये, हम उन अदृश्य दरारों की विस्तृत पड़ताल करें जो केवल विपक्षी दलों की नींव में नहीं, बल्कि बिहार की सामाजिक और राजनीतिक संरचना के मूल ढांचे में पड़ गई हैं।

## जब अंकगणित पर रसायनशास्त्र भारी पड़ा

इस राजनीतिक भूकम्प की तीव्रता को समझने के लिए हमें सबसे पहले आंकड़ों के ठंडे, निर्मम सत्य को देखना होगा। एनडीए का 47% वोट शेयर और महागठबंधन का 38% पर सिमट जाना, दोनों के बीच 9% का यह विशाल अंतर किसी मामूली स्विंग का परिणाम नहीं है। यह एक सामाजिक पुनर्गठन का प्रमाण है। दशकों से, बिहार की राजनीति कुछ ठोस 'महाद्वीपों' पर टिकी थीः राजद का 'एम-वाई' (मुस्लिम-यादव) का अभेद्य किला और भाजपा का सवर्ण मतदाताओं का गढ़, जिनके बीच नीतीश कुमार अति पिछड़ों, महादलितों और गैर-यादव ओबीसी के बिखरे हुए द्वीपों को जोड़कर अपना साम्राज्य बनाते थे।

2025 के चुनाव ने इस भूगोल को पूरी तरह बदल दिया। एनडीए ने न केवल अपने पारंपरिक सवर्ण दुर्ग को अक्षुण्ण रखा, बल्कि उस पर विजय पताका फहराते हुए एक नए सामाजिक महाद्वीप की रचना की। इस महाद्वीप की नींव में गैर-यादव ओबीसी और अति-पिछड़ों की विशाल आबादी की ईंटें लगी थीं। आंकड़ों की शल्यक्रिया बताती है कि एनडीए के वोट में 15% का विशाल हिस्सा इसी ईबीसी समुदाय से आया, जो नीतीश कुमार के सामाजिक आधार का भाजपा के संगठनात्मक ढांचे के साथ मिलकर एक दुर्जेय शक्ति में बदलना दर्शाता है। इसी के साथ, दलित समुदाय का एक बड़ा हिस्सा भी इस महाद्वीप का हिस्सा बना, जहाँ एनडीए ने 13% एससी-एसटी वोट हासिल किए, जबकि महागठबंधन 4% पर ही सिमट गया।

बिहार का 2025 का जनादेश केवल एक राज्य का चुनावी परिणाम नहीं है; यह पूरे भारत की राजनीति के लिए एक संदेश है। यह उस 'मौन मतदाता' की शक्ति का उद्घोष है, जिसे अक्सर अभिजात्य विमर्श में नजरअंदाज कर दिया जाता है। क्या यह परिणाम लोकतंत्र के लिए स्वस्थ है? क्या तात्कालिक लाभ, दीर्घकालिक मुद्दों जैसे कि रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य पर भारी पड़ जाएंगे? ये प्रश्न भविष्य के गर्भ में हैं।

सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन राजद के 'एम-वाई' किले में लगी सेंध थी। यद्यपि महागठबंधन को यादवों और मुस्लिमों का बड़ा समर्थन मिला, लेकिन एनडीए ने यादवों के 3% और मुस्लिमों के 2% वोट में सेंध लगा दी। यह छोटी सी सेंधमारी उस मनोवैज्ञानिक दीवार के टूटने का प्रतीक है, जो कहती थी कि ये समुदाय कभी भी भाजपा को वोट नहीं दे सकते। यह केवल अंकगणित नहीं था; यह एक नया सामाजिक रसायनशास्त्र था। प्रधानमंत्री मोदी ने इसे 'महिला-युवा' का नया 'माई' कॉम्बिनेशन कहकर एक नई परिभाषा दी—एक ऐसा समीकरण जो जाति और धर्म की सीमाओं को लांघकर सीधे आकांक्षा और लाभ पर आधारित था।

## नारीवादी लोकतंत्र: बीस साल का मौन निवेश

यह दो दशकों के मौन निवेश का लाभांश था, एक ऐसा ऋण जो बिहार की करोड़ों महिलाओं ने इस चुनाव में विश्वास के वोट से चुकाया। जब राजनीतिक विश्लेषक नीतीश कुमार के स्वास्थ्य और उनकी घटती राजनीतिक ताकत पर बहस कर रहे थे, तब वे यह भूल गए कि नीतीश ने पिछले दो दशकों में चुपचाप बिहार के सबसे बड़े और सबसे मौन वोट बैंक—महिलाओं—में निवेश किया था।

यह यात्रा 2005 में पंचायत चुनावों में 50% महिला आरक्षण के क्रांतिकारी कदम से शुरू हुई थी। यह केवल एक सीट आरक्षित करना नहीं था; यह सत्ता के केंद्र में महिलाओं को भागीदार बनाना था। इसके बाद आई 'साइकिल योजना', जिसने लड़कियों को शिक्षा और गतिशीलता दी। साइकिल पर स्कूल जाती लड़कियों की तस्वीर बिहार में पितृसत्ता की जंजीरों के टूटने का प्रतीक बन गई। फिर शराबबंदी का साहसिक फैसला आया, जो सीधे तौर पर घर की महिला से जुड़ा था। 'जीविका' दीदियों का विशाल नेटवर्क इस 'नारीवादी लोकतंत्र' की रीढ़ बना। 1.4 करोड़ से अधिक महिलाओं का यह स्वयं सहायता समूह केवल एक आर्थिक कार्यक्रम नहीं

रहा; यह एक सामाजिक और राजनीतिक शक्ति बन गया। ये महिलाएं अब केवल लाभार्थी नहीं थीं; वे शासन की शिल्पकार थीं।

चुनाव से ठीक पहले 'मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना' के तहत दस हजार रुपये का हस्तांतरण इस दो दशक की कहानी का चरमोत्कर्ष था। विपक्ष ने इसे 'रिश्वत' कहा, लेकिन उन महिलाओं के लिए यह उनके लंबे भरोसे का प्रतिफल था। यह विश्वास एक दिन में नहीं खरीदा जा सकता; इसे कमाना पड़ता है। 2025 का जनादेश इसी कमाई का प्रमाण था।

## विपक्ष का आत्म-विनाश

यदि एनडीए की विजय एक सुनियोजित महाकाव्य थी, तो महागठबंधन की पराजय आत्म-विनाश की एक दुखद गाथा है। वे उस युद्ध को लड़ने की तैयारी कर रहे थे जो पहले ही खत्म हो चुका था, जिसके हथियार पुराने पड़ चुके थे। तेजस्वी यादव और राजद नेतृत्व इस भ्रम में रहे कि उनका 31% का कोर वोट बैंक उन्हें सत्ता की दहलीज तक पहुंचा देगा। उन्होंने इस किले से बाहर निकलकर ईबीसी, दलितों और अन्य समुदायों के साथ एक व्यापक इंद्रधनुषी गठबंधन बनाने का कोई गंभीर प्रयास नहीं किया। इसके विपरीत, एनडीए ने चिराग पासवान, जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा को साथ लाकर सामाजिक रूप से अधिक समावेशी गठबंधन बनाया। जहाँ एक ओर अमित शाह पटना में डेरा डालकर बागियों को मना रहे थे, वहीं महागठबंधन में 'दोस्ताना लड़ाई' और अंदरूनी कलह जारी थी। तेजस्वी यादव का असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को साथ न लेना एक रणनीतिक भूल साबित हुई, जिसने सीमांचल में मुस्लिम वोटों का विभाजन कर महागठबंधन को भारी क्षति पहुंचाई। और इन सब के ऊपर 'जंगल राज' का भूत मंडराता रहा, जिसकी याद दिलाकर एनडीए ने विकास और सुरक्षा के अपने नैरेटिव को और मजबूत किया।

एक नई राजनीति का उदय

इस जनादेश का सबसे गहरा सबक यह है कि बिहार की राजनीति एक निर्णायक मोड़ पर आ खड़ी हुई है। यह 'मंडल' राजनीति का अंत नहीं है, बल्कि उसका रूपांतरण है। अब राजनीति केवल इस आधार पर नहीं होगी कि 'आप कौन हैं', बल्कि इस आधार पर होगी कि 'आपको क्या मिला है'। 'लाभार्थी वर्ग' एक नई, शक्तिशाली राजनीतिक पहचान के रूप में उभरा है, जो जाति की दीवारों को भेद रही है। जिस व्यक्ति को मुफ्त राशन, उज्ज्वला का सिलेंडर और किसान सम्मान निधि मिली है, उसकी पहली पहचान अब उसकी जाति नहीं, बल्कि एक 'लाभार्थी' की है। यह एक सीधा, व्यक्तिगत संबंध है जो उसने सरकार के साथ बनाया है। इस संबंध के आगे जाति के पुराने समीकरण कमजोर पड़ रहे हैं।

## मौन मतदाताओं की शक्ति का उद्घोष

बिहार का 2025 का जनादेश केवल एक राज्य का चुनावी परिणाम नहीं है; यह पूरे भारत की राजनीति के लिए एक संदेश है। यह उस 'मौन मतदाता' की शक्ति का उद्घोष है, जिसे अक्सर अभिजात्य विमर्श में नजरअंदाज कर दिया जाता है। क्या यह परिणाम लोकतंत्र के लिए स्वस्थ है? क्या तात्कालिक लाभ, दीर्घकालिक मुद्दों जैसे कि रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य पर भारी पड़ जाएंगे? ये प्रश्न भविष्य के गर्भ में हैं। लेकिन एक बात स्पष्ट है। बिहार का यह जनादेश इस बात का प्रतीक है कि मतदाता का विवेक अब बदल चुका है। वह अब केवल पहचान के नाम पर वोट नहीं देगा; वह अपने जीवन में आए ठोस बदलाव के आधार पर फैसला करेगा। बिहार ने जो रास्ता दिखाया है, वह भारत की भविष्य की राजनीति की पटकथा लिख सकता है, जहाँ सबसे बड़ी जाति का नाम 'लाभार्थी' होगा और सबसे बड़ा धर्म 'विकास' होगा। चुनाव हमारा है, लेकिन बिहार ने अपनी पसंद स्पष्ट कर दी है।

# SIR प. बंगाल में ‘रिवर्स एक्सोडस’

अनवर हुसैन

जब भारत–बांग्लादेश सीमा पर सालों से अंधेरे में पार होने वाली परछाइयाँ उजाले में लौटने लगें, तो यह सिर्फ़ पलायन नहीं—एक ऐतिहासिक दरार का उद्घोष है। हाकिमपुर की ख़ामोशी बता रही है कि तुष्टिकरण की दीवारें ढह रही हैं और राष्ट्र अपनी संप्रभु सच्चाई पुनः स्थापित कर रहा है।

भारत-बांग्लादेश सीमा पर जब सूरज ढलता है, तो आकाश की लाली में लिपटी रेत और धूल की परतों पर एक अजीब सी बेचैनी तैरने लगती है। हकिमपुर की सीमा चौकी, जो दशकों से रातों के अंधेरे में दबे पांव आने वाले घुसपैठियों की मूक गवाह रही है, आज एक अभूतपूर्व ऐतिहासिक उलटफेर की साक्षी बन रही है। जहां कभी कटीले तारों के पार से परछाइयां भारत की भूमि पर कदम रखती थीं और रातों-रात इस देश की भीड़ में विलीन हो जाती थीं, आज वही रास्ते दिन के उजाले में वापसी के कदमों से पटे पड़े हैं। यह दृश्य सामान्य नहीं है। यह मात्र पलायन नहीं है, बल्कि उस राजनीतिक और सामाजिक ढांचे के दरकने की आवाज है, जिसने वर्षों तक पश्चिम बंगाल की जनसांख्यिकी को अपनी मुट्ठी में जकड़ रखा था।

हजारों की संख्या में लोग, जिनके हाथों में पुरानी रसीदें नहीं बल्कि

अपने अस्तित्व को समेटे हुए छोटे-छोटे थैले हैं, अब उस देश को छोड़ने के लिए कतार में खड़े हैं जिसे उन्होंने अपना घर मान लिया था। बीएसएफ के अधिकारी इसे 'रिवर्स एक्सोडस' यानी 'उल्टा पलायन' कह रहे हैं, लेकिन क्या यह शब्द उस गहरे राजनीतिक भूचाल को समझाने के लिए काफी है जो इस समय बंगाल की धरती पर आ रहा है? क्या यह स्वैच्छिक वापसी है? क्या यह कानून का डर है? या फिर यह एक ऐसी राजनीतिक सच्चाई का प्रकटीकरण है जिसके सामने दशकों से खड़ा तुष्टिकरण का अवैध किला अब ध्वस्त हो रहा है?

इस पूरी उथल-पुथल के केंद्र में एक प्रशासनिक प्रक्रिया है—स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। यह शब्द सुनने में जितना तकनीकी और नीरस लगता है, इसका प्रभाव उतना ही विस्फोटक है। भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा शुरू की गई मतदाता सूची के पुनरीक्षण की इस प्रक्रिया ने पश्चिम बंगाल की राजनीति में तूफान खड़ा कर दिया है। विपक्ष इसे 'डर की राजनीति' और 'तानाशाही' की संज्ञा दे रहा है, चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर तीखे हमले किए जा रहे हैं, और 'मानवाधिकार' की दुहाई दी जा रही है। लेकिन इस राजनीतिक कोलाहल के बीच, हकिमपुर और घोजडांगा की सीमाओं पर पसरा सन्नाटा सबसे अधिक मुखर है। वह सन्नाटा, जो उन हजारों चेहरों पर लिखा है जो कल तक भारत के मतदाता थे, लेकिन आज अपनी असली पहचान के साथ बांग्लादेश लौटने को मजबूर हैं।

एक गहन विश्लेषणात्मक दृष्टि से देखें तो यह घटनाक्रम केवल चुनावी रस्साकशी नहीं है। यह भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में एक ऐसा क्षण है जहां 'वोट बैंक' और 'राष्ट्रीय सुरक्षा' के बीच की धुंधली रेखा मिटने लगी है। दक्षिणपंथी चिंतकों और भारतीय जनता पार्टी के लिए, यह क्षण एक ऐतिहासिक सुधार का है। उनका मानना है कि यह प्रशासनिक अभ्यास नहीं, बल्कि एक राष्ट्र के रूप में भारत की संप्रभुता की बहाली है। वर्षों से यह तर्क दिया जाता रहा है कि बंगाल में घुसपैठ केवल गरीबी से उपजी समस्या नहीं थी, बल्कि एक सुनियोजित राजनीतिक उद्योग था। आज जब SIR की प्रक्रिया ने उस उद्योग की नब्ज दबा दी है, तो पूरा तंत्र छटपटा रहा है।

इंडियन एक्सप्रेस और अन्य मीडिया रिपोर्ट्स में वर्णित दृश्य किसी मानवीय त्रासदी के पारंपरिक आख्यानों से अलग हैं। पेड़ों के नीचे बैठे अब्दुल मोमिन जैसे लोग, जो अपने जीवन की जमा-पूंजी को प्लास्टिक के बोरों में भरकर सीमा खुलने का इंतजार कर रहे हैं, वे किसी युद्ध के शरणार्थी नहीं हैं। वे एक ऐसे सिस्टम के लाभार्थी थे जो अब टूट चुका है। मोमिन और उनके जैसे हजारों लोग, जो वर्षों से यहां घरेलू कामकाज में लगे थे, कारखानों में पसीना बहा रहे थे, और सबसे महत्वपूर्ण—जो चुनावों में कतारबद्ध होकर वोट डाल रहे थे—आज कह रहे हैं, 'अब यहां और नहीं रहा जा सकता। जोखिम बहुत बड़ा है।' यह वाक्य अपने आप में पूरी कहानी कह देता है। यह जोखिम क्या है? यह जोखिम है पकड़े जाने का। यह जोखिम है उस प्रश्न का उत्तर देने का जिसे बंगाल की राजनीति ने दशकों तक दबा कर रखा—'तुम कौन हो और यहां किस अधिकार से हो?'

SIR ने पहली बार इन लोगों को आईना दिखाया है। यह प्रक्रिया केवल कागजों की जांच नहीं कर रही, बल्कि यह उस अवैध अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ रही है जो घुसपैठ पर पलती थी। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट्स बताती हैं कि सीमा पार करना और भारत का नागरिक बनना एक बाकायदा कारोबार था। पांच से सात हजार रुपये में सीमा पार कराई जाती थी और पंद्रह से बीस हजार रुपये में फर्जी आधार, राशन कार्ड और वोटर आईडी तैयार हो जाते थे। 29 वर्षीय मनीरुल शेख का बयान इस पूरे भ्रष्टाचार की पोल

खोलता है—'मैंने कागजात बनवाने के लिए लगभग बीस हजार रुपये दिए थे, लेकिन SIR ने सब कुछ बदल दिया।' यह स्वीकारोक्ति बताती है कि भारत की नागरिकता और मताधिकार को किस तरह बिकाऊ वस्तु बना दिया गया था। जब तक राजनीतिक संरक्षण था, तब तक यह धंधा फलता-फूलता रहा, लेकिन जैसे ही प्रशासन ने सख्ती दिखाई, यह ताश के पत्तों की तरह बिखरने लगा।

विपक्षी दल और वामपंथी खेमे में इस समय जो बेचैनी है, उसे समझना भी आवश्यक है। वे SIR को गरीबों और अल्पसंख्यकों के खिलाफ एक हथियार बता रहे हैं। उनका तर्क है कि यह प्रक्रिया एक विशेष समुदाय को निशाना बनाने और उन्हें डराने के लिए है। लेकिन यहां एक मौलिक प्रश्न खड़ा होता है—क्या एक संप्रभु राष्ट्र को अपनी मतदाता सूची की पवित्रता जांचने का अधिकार नहीं है? यदि लाखों की संख्या में मृत मतदाताओं के नाम सूची में जीवित हों, यदि हजारों लोग फर्जी दस्तावेजों के आधार पर देश की नीतियों और सरकारों को चुनने में भूमिका निभा रहे हों, तो क्या यह लोकतंत्र के साथ धोखा नहीं है? एक बीएसएफ अधिकारी का यह कथन कि 'वे अंधेरे में आए थे, अब वे उजाले में सही रास्ते से वापस जा रहे हैं।' स्थिति की गंभीरता और विडंबना दोनों को दर्शाता है। यह कोई अत्याचार नहीं, बल्कि 'लॉ ऑफ द लैंड' (देश के कानून) की पुनर्स्थापना है। बंगाल की सीमा पर वर्षों से कानून का राज नहीं, बल्कि 'वोट का राज' चलता था। SIR ने पहली बार इस समीकरण को उलट दिया है।

इस पलायन को 'ऑपरेशन मौन सफाई' कहा जा सकता है। रिपोर्ट्स के अनुसार, पिछले कुछ दिनों में बारह सौ से अधिक लोग वापस लौटे हैं। कतारें दो से तीन किलोमीटर लंबी हैं। पुलिस थाने और बीएसएफ के कैंप अपनी क्षमता से अधिक भरे हुए हैं। यह दृश्य हृदयविदारक हो सकते हैं। एक बच्चा जब कहता है कि वह न्यू टाउन में अपने दोस्तों को याद करेगा, तो वह मानवीय संवेदनाओं को झकझोरता है। लेकिन भावनाएं राष्ट्रीय सुरक्षा का विकल्प नहीं हो सकतीं। यह स्थिति एक कड़वे सत्य को उजागर करती है कि अवैध बसाहट, चाहे वह कितनी भी पुरानी क्यों न हो जाए, उसे वैधता नहीं मिल सकती। यह मानवाधिकार का संकट नहीं, बल्कि एक अवैध व्यवस्था का तार्किक अंत है।

राजनीतिक गलियारों में इस समय जो शोर है, वह दरअसल उस डर की गूंज है जो सत्ता के समीकरण बदलने से उपजा है। तृणमूल कांग्रेस और इंडी गठबंधन के नेता चुनाव आयोग पर भाजपा के प्रवक्ता की तरह काम करने का आरोप लगा रहे हैं। लेकिन निष्पक्ष नजरिए से देखें तो यह आरोप हास्यास्पद लगता है। यदि चुनाव आयोग का काम निष्पक्ष चुनाव कराना है, तो फर्जी मतदाताओं को हटाना उसका प्राथमिक कर्तव्य है। प्रश्न आयोग से नहीं, बल्कि उन दलों से पूछा जाना चाहिए जिन्होंने इन अवैध प्रवासियों को दशकों तक अपना 'वोट बैंक' बनाकर जिंदा रखा। विपक्ष का आरोप है कि यह 'वोटर डिलीशन' और 'राजनीतिक सफाई' है। इस पर विश्लेषकों का एक बड़ा वर्ग मानता है कि हां, यह सफाई है—लेकिन यह किसी धर्म या जाति की सफाई नहीं, बल्कि लोकतंत्र में घुसपैठ कर चुकी फर्जी पहचानों की सफाई है।

सबसे बड़ा और दूरगामी प्रश्न यह है कि क्या SIR अभी से 2026 के बंगाल विधानसभा चुनावों की पटकथा लिख रहा है? यदि अवैध

मतदाता सूची से बाहर होते हैं, यदि घुसपैठियों का वह नेटवर्क टूटता है जो स्थानीय राजनीति को प्रभावित करता था, तो इसका सीधा असर मत-प्रतिशत पर पड़ेगा। टीएमसी, जिसका एक बड़ा आधार ग्रामीण और सीमावर्ती क्षेत्रों में इन्हीं जनसांख्यिकीय समीकरणों पर टिका है, उसे भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। दूसरी ओर, भाजपा के आक्रामक राष्ट्रवादी नैरेटिव को इससे नई धार मिलेगी। यह प्रक्रिया भाजपा के इस दावे को पुख्ता करती है कि बंगाल में जनसांख्यिकीय बदलाव एक वास्तविकता है और उसे रोकने के लिए कड़े कदम उठाने की आवश्यकता थी।

कुछ मानवाधिकार संगठन और बुद्धिजीवी इसे मानवता बनाम संप्रभुता की लड़ाई के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। गरीबी, लाचारी और भय के दृश्यों को ढाल बनाकर तर्कों को मोड़ा जा रहा है। लेकिन राष्ट्रवादी दृष्टिकोण स्पष्ट है—गरीबी किसी को सीमा लांघने और दूसरे देश के कानूनों को तोड़ने का लाइसेंस नहीं देती। भारत का संविधान अवैध प्रवासियों को न तो नागरिकता का अधिकार देता है और न ही राजनीतिक भागीदारी का। ये लोग आर्थिक रूप से विपन्न हो सकते हैं, लेकिन कानून की नजर में वे निर्दोष नहीं हैं। उन्होंने एक देश की सीमाओं का ही नहीं, बल्कि उसकी लोकतांत्रिक व्यवस्था का भी उल्लंघन किया है।

हकिमपुर का यह दृश्य केवल स्थानीय घटना नहीं है, यह भू-राजनीतिक सच्चाई का आईना भी है। बांग्लादेश की सरकार अक्सर भारत की सीमा प्रबंधन पर सवाल उठाती रही है, लेकिन SIR की कार्यवाही ने यह सिद्ध कर दिया है कि समस्या केवल सीमा की बाड़ में नहीं थी। समस्या उस भीतरी तंत्र में थी जो घुसपैठियों का स्वागत करता था, उन्हें दस्तावेज देता था और उन्हें व्यवस्था का हिस्सा बना लेता था। आज जब यह भीतरी तंत्र जांच के दायरे में है, तो सीमा पार भी हलचल है। ढाका अब इस वास्तविकता से मुंह नहीं मोड़ सकता कि उसके नागरिक बड़ी संख्या में अवैध रूप से भारत में रह रहे थे।

दीवारों पर लिखे नारे मिटाए जा सकते हैं, लेकिन इतिहास की दीवार पर जो दरारें उभर रही हैं, उन्हें अनदेखा नहीं किया जा सकता। पश्चिम बंगाल में SIR जिस तरह से परत-दर-परत सच्चाई को उधेड़ रहा है, उसका संदेश स्पष्ट है—राजनीति बदल रही है। मतदाता बदल रहे हैं। और देश अपना लोकतांत्रिक डीएनए पुनर्गठित कर रहा है। घुसपैठ अब केवल एक चुनावी मुद्दा नहीं रह गया है, यह राष्ट्रीय अस्मिता का प्रश्न बन गया है। यह प्रक्रिया उस दशकों पुराने भ्रम को तोड़ रही है कि भारत एक 'सॉफ्ट स्टेट' है जहाँ कोई भी आ सकता है और व्यवस्था का हिस्सा बन सकता है।

निष्कर्षतः, SIR को केवल एक प्रशासनिक कवायद मान लेना भूल होगी। यह भारत की सुरक्षा और संप्रभुता का एक 'सर्जिकल ऑडिट' है। यदि मतदाता सूची शुद्ध होती है, तो इसका लाभ केवल किसी एक दल को नहीं, बल्कि पूरे भारतीय लोकतंत्र को मिलेगा। पलायन करते लोगों की कतारें, उनके चेहरों पर छायी मायूसी और सीमा पर पसरा सन्नाटा—ये सब मिलकर एक नए युग की शुरुआत का संकेत दे रहे हैं। यह युग उस भारत का है जो अपनी सीमाओं को केवल नक्शे पर खींची गई लकीर नहीं मानता, बल्कि उसे राष्ट्र की आत्मा का रक्षक मानता है। आज, उस आत्मा की सफाई हो रही है—धीरे-धीरे, खामोशी से, लेकिन अत्यंत निर्णायक रूप से। और इस प्रक्रिया में, बंगाल की राजनीति हमेशा के लिए बदलने वाली है।

श्रीराजेश

धरती खामोशी में भी बोलती है—बस हम सुन नहीं पाते। उपग्रहों ने 2015–2023 के बीच 50 से अधिक शहरी हॉटस्पॉट्स में उसकी धीमी कराह दर्ज की है। यह कराह भूजल की क्षीण नसों और कंक्रीट के दमन का शोर है। अगर हमने अब भी न सुना, तो हमारे महानगर आसमान को छूते हुए भी ज़मीन पर भरोसा खो देंगे।

# डूबते मेट्रोपोलिस

## पैरों तले धंसती धरती

उत्तरी जकार्ता के मुआरा बारू जिले के तट पर, जहाँ कभी जीवन की चहल-पहल थी, वहाँ आज एक अजीब-सा सन्नाटा पसरा है। उस सन्नाटे के बीच 'वालादुना मस्जिद' एक टूटे हुए जहाज की तरह खड़ी है—अकेली, वीरान और आधी डूबी हुई। उसकी दीवारों पर अब आयतें नहीं, बल्कि काई की मोटी, फिसलन भरी परतें लिखी हैं। जहाँ कभी नमाजियों के माथे सजदे में झुकते थे, वहाँ अब हिंद महासागर का खारा, गंदा पानी हिलोरे लेता है। ज्वार के समय पानी मस्जिद की खिड़कियों तक पहुँच जाता है, मानो समुद्र यह दावा कर रहा हो कि यह इमारत अब इंसान की नहीं, उसकी है। यह मस्जिद किसी युद्ध में बमबारी का शिकार नहीं हुई, न ही किसी अचानक आए भूकंप ने इसे तोड़ा। इसे किसी विदेशी सेना ने नहीं ढहाया। इसे उस जमीन ने निगल लिया जिस पर यह भरोसे के साथ खड़ी थी। यह मस्जिद आज 21वीं सदी का एक 'भूतिया स्मारक' है—इस कड़वी हकीकत का गवाह कि जब धरती अपनी प्यास और कंक्रीट के बोझ से कराहती है, तो वह सबसे पवित्र स्थलों को भी नहीं बख्शती।

जकार्ता का यह दृश्य कोई दूरस्थ डरावनी फिल्म या किसी काल्पनिक 'डिस्तोपिया' का हिस्सा नहीं है। यह भविष्य का वह पारदर्शी आईना है जिसमें भारत के महानगर अपना चेहरा देख रहे हैं, भले ही वे अभी इस भयावह प्रतिबिंब को पहचानने से इनकार कर रहे हों। हम अक्सर आपदाओं को शोर और दृश्यता के साथ जोड़ते हैं। सुनामी का गर्जन, भूकंप की गड़गड़ाहट, बादलों का फटना या चक्रवात का सायरन—ये सभी हमें डरने, भागने और प्रतिक्रिया करने का कम से कम कुछ पल का समय

देते हैं। लेकिन आधुनिक शहरीकरण के युग में जिस आपदा ने हमारे शहरों को घेरा है, वह 'मौन' है। यह दबे पांव आती है, किसी चोर की तरह। यह मिलीमीटर दर मिलीमीटर, एक कछुए की गति से हमारे शहरों की बुनियाद को खोखला कर रही है। इसे वैज्ञानिक शब्दावली में 'लैंड सब्सिडेंस' या भूमि का अवतलन कहते हैं। लेकिन अगर हम इसके भू-राजनीतिक और सामाजिक संदर्भ को देखें, तो यह एक 'इन्फ्रास्ट्रक्चर वॉरफेयर' है—एक ऐसा अदृश्य युद्ध जो हम खुद अपने ही अस्तित्व के खिलाफ लड़ रहे हैं, और जिसमें हमारी हार तब तक तय मानी जा रही है, जब तक कि हम अपनी जल और भूमि प्रबंधन की रणनीतियों में क्रांतिकारी परिवर्तन नहीं करते।

हाल ही में प्रतिष्ठित जर्नल 'नेचर सस्टेनेबिलिटी' में प्रकाशित शोध और 2015 से 2023 के बीच एकत्र किए गए इनसार (इनसार) उपग्रह डेटा ने जिस सच्चाई से पर्दा उठाया है, वह केवल एक पर्यावरणीय चिंता का विषय नहीं है। यह भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक स्थिरता और सामाजिक ताने-बाने के लिए एक अस्तित्वगत खतरा है। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता और बेंगलुरु—भारत की अर्थव्यवस्था के ये पांच महाकाय इंजन—ऐसी जमीन पर दौड़ रहे हैं जो धीरे-धीरे, लेकिन निश्चित रूप से नीचे बैठ रही है। आइये, हम उन अदृश्य दरारों की विस्तृत पड़ताल करें जो हमारी इमारतों की नींव में ही नहीं, बल्कि हमारी भविष्य की सुरक्षा और सभ्यता के ढांचे में भी पड़ रही हैं।

## आंकड़ों की विश्वसनीयता:

इस संकट की गहराई और इसके दावों की सत्यता को समझने के लिए सबसे पहले यह जानना आवश्यक है कि वैज्ञानिक इस अदृश्य प्रक्रिया को मापते कैसे हैं। यह कोई अनुमान या कयास नहीं है, बल्कि अंतरिक्ष से की गई सटीक निगरानी का परिणाम है। इस अध्ययन के लिए शोधकर्ताओं ने यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी (ईएसए) के 'सेंटिनल-1' उपग्रहों द्वारा भेजे गए इनसार (इंटरफेरोमेट्रिक सिंथेटिक एपर्चर रडार) डेटा का उपयोग किया है। यह तकनीक रडार तरंगों के चरण परिवर्तन का उपयोग करके पृथ्वी की सतह में आए मिलीमीटर-स्तर के बदलाव को भी पकड़ सकती है। यह ठीक वैसा ही है जैसे अंतरिक्ष से जमीन पर रखे एक सिक्के की मोटाई में बदलाव को नाप लेना।

इसके साथ ही, भूजल की स्थिति को समझने के लिए नासा के जीआरएसीई-एफओ (ग्रेविटी रिकवरी एंड क्लाइमेट एक्सपेरिमेंट फॉलो-ऑन) उपग्रहों के डेटा का विश्लेषण किया गया। ये उपग्रह पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में होने वाले अत्यंत सूक्ष्म परिवर्तनों को मापते हैं, जो मुख्य रूप से जमीन के नीचे पानी के भंडार के घटने या बढ़ने से होते हैं। जब इन दोनों तकनीकों—इनसार द्वारा सतह की माप और जीआरएसीई द्वारा भूजल की माप—को मिलाया गया, तो एक स्पष्ट कोरिलेशन सामने आयाः जिन इलाकों में एक्विफर सबसे तेजी से खाली हो रहे हैं, ठीक उन्हीं इलाकों में जमीन सबसे तेजी से नीचे जा रही है। हालांकि, वैज्ञानिकों ने यह भी स्पष्ट किया है कि घने वनस्पति वाले क्षेत्रों या बहुत तेजी से बदलती सतहों पर इनसार की सटीकता की कुछ सीमाएं हैं, लेकिन शहरी कंक्रीट के जंगलों के लिए यह डेटा वर्तमान में नीति-निर्माताओं के लिए उपलब्ध सबसे ठोस प्रमाण है।

## दुनिया के डूबते शहर: उपग्रह क्या देख रहे हैं?

वैश्विक आंकड़े दिखाते हैं कि भूमि का धंसना अब एक बहु-महाद्वीपीय संकट है।

**जकार्ता (इंडोनेशिया): 25–30 सेमी/वर्ष**

(दुनिया का सबसे तेज़ डूबता शहर; बचाव असंभव होने पर राजधानी बदली जा रही है)

**मेक्सिको सिटी (मेक्सिको): 9 मीटर (कुल 1900–2023)**

(ऐतिहासिक शहर अपनी पुरानी झील की सतह में समा रहा है)

**हो ची मिन्ह सिटी (वियतनाम): 20–60 मिमी/वर्ष**

(नरम डेल्टा मिट्टी और भारी शहरीकरण का परिणाम)

**शंघाई (चीन): 10–30 मिमी/वर्ष**

(गगनचुंबी इमारतों के भार से दबा हुआ)

**निष्कर्ष:** एशिया वैश्विक 'हॉटस्पॉट' है। भारत, चीन और आसियान देश मिलकर दुनिया की सबसे बड़ी 'सब्सीडेंस प्रोन' आबादी का घर हैं।

(स्रोत: इनसार डेटासेट 2015-2023 और आईपीसीसी रिपोर्ट्स)

## विज्ञान का क्रूर गणित: जब धरती स्पंज की तरह सूख जाती है

इस आपदा की प्रक्रिया को समझना उतना ही डरावना है जितना इसके परिणाम। इसे समझने के लिए हमें अपने पैरों के नीचे की दुनिया की कल्पना करनी होगी। हमारे शहरों के नीचे की मिट्टी, रेत

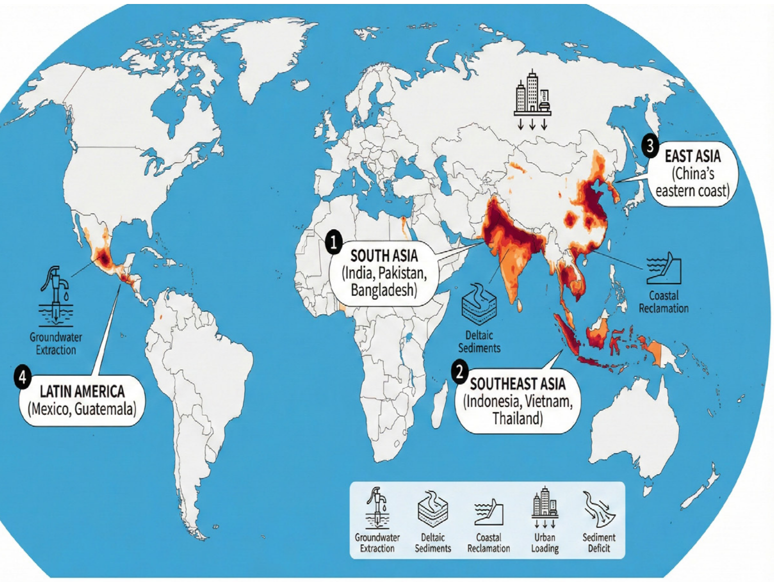


**'OVER 150 MAJOR CITIES WORLDWIDE LIE IN ACTIVE SUBSIDENCE ZONES.'**

और चट्टानें एक ठोस ब्लॉक नहीं हैं, बल्कि वे एक विशाल, जटिल 'स्पंज' की तरह हैं। लाखों वर्षों से, इन परतों के बीच मौजूद सूक्ष्म छिद्रों में पानी भरा हुआ था। यह पानी केवल प्यास बुझाने का साधन नहीं था; यह एक संरचनात्मक स्तंभ था। पानी का 'हाइड्रोलिक दबाव' मिट्टी के कणों को एक-दूसरे से दूर रखता था और ऊपर की जमीन के भारी वजन को थामे रहता था। यह प्रकृति की अपनी इंजीनियरिंग थी।

पिछले कुछ दशकों में, अनियंत्रित शहरीकरण और जनसंख्या विस्फोट की अंधी दौड़ में, हमने इस स्पंज को बेरहमी से निचोड़ दिया है। वैश्विक स्तर पर हुए अध्ययनों, विशेषकर 'साइंस, 2021' जर्नल में प्रकाशित शोध के अनुसार, दुनिया भर में होने वाले भूमि अवतलन के लगभग 59% मामलों के लिए सीधे तौर पर भूजल का अत्यधिक दोहन जिम्मेदार है। हम पानी को उस गति से निकाल रहे हैं, जिस गति से प्रकृति उसे दोबारा भरने में असमर्थ है। जैसे ही एक्विफर से पानी बाहर निकलता है, वह हाइड्रोलिक दबाव खत्म हो जाता है जो मिट्टी के ढांचे को सहारा दे रहा था। इसका परिणाम भौतिक विज्ञान के नियमों के अनुसार होता है—मिट्टी के कण एक-दूसरे के करीब आ जाते हैं, उनके बीच की हवा के बुलबुले खत्म हो जाते हैं, और जमीन 'कॉम्पैक्ट' या सघन हो जाती है। इसे भू-विज्ञान में 'कम्पेक्शन' कहते हैं।

सतह पर चलते हुए हमें कुछ महसूस नहीं होता। हमें कोई झटका नहीं लगता, कॉफी का कप मेज से नहीं गिरता। लेकिन हमारे पैरों के नीचे की भूगर्भिक संरचना हमेशा के लिए बदल चुकी होती है। सबसे चिंताजनक बात यह है कि यह प्रक्रिया अक्सर 'इनइलास्टिक' होती है, यानी अपरिवर्तनीय। एक बार जब मिट्टी की परतें दब जाती हैं और उनकी संरचना ढह जाती है, तो आप उनमें वापस पानी भरकर उन्हें पहले जैसा नहीं फुला सकते। यह एक 'वन-वे टिकट' है। दिल्ली और एनसीआर के कुछ हिस्सों में, विशेषकर कापसहेड़ा और बिजवासन जैसे क्षेत्रों में, जहां जमीन 51 मिलीमीटर प्रति वर्ष की अधिकतम दर से धंस रही है, वहां यही प्रक्रिया चल रही है।

यह दर सुनने में कम लग सकती है—महज एक क्रेडिट कार्ड की मोटाई जितनी। आम आदमी सोच सकता है कि 5 सेंटीमीटर सालाना धंसने से क्या फर्क पड़ता है? लेकिन जब आप इसे दशकों के पैमाने पर देखते हैं, तो इसका गणित भयावह हो जाता है। 50 मिलीमीटर प्रति वर्ष का मतलब है कि हर बीस साल में हम एक मीटर जमीन खो रहे हैं। और समस्या केवल नीचे जाने की नहीं है; समस्या 'असमानता' की है। जब यह गिरावट पूरे शहर में एक समान नहीं होती, बल्कि 'डिफरेंशियल' होती है, तो असली विनाश शुरू होता है। जब एक विशाल इमारत का बायां हिस्सा 10 मिलीमीटर धंसता है और दायां हिस्सा 40 मिलीमीटर, तो इमारत में तनाव पैदा होता है। कंक्रीट और स्टील लचीले नहीं होते; वे एक सीमा तक तनाव सहते हैं और फिर टूट जाते हैं। इंजीनियर इसे 'एंगुलर डिस्टॉर्शन' कहते हैं। यही वह बिंदु है जहां विज्ञान, आपदा में बदल जाता है।

### इन्फ्रास्ट्रक्चर वॉरफेयर:

लैंड सब्सिडेंस की समस्या को अब तक मुख्य रूप से पर्यावरणविदों, हाइड्रोलॉजिस्ट या शहरी योजनाकारों के चश्मे से देखा गया है। यह एक बड़ी भूल है। यदि हम अपना लेंस बदलें और इसे एक रक्षा विशेषज्ञ या राष्ट्रीय सुरक्षा विश्लेषक की नजर से देखें, तो तस्वीर बेहद चिंताजनक हो जाती है। इसे 'इन्फ्रास्ट्रक्चर वॉरफेयर' या बुनियादी ढांचे के युद्ध की संज्ञा देना कोई साहित्यिक अतिशयोक्ति नहीं होगी।

पारंपरिक युद्ध के सिद्धांतों में, दुश्मन देश का उद्देश्य आपके 'क्रिटिकल इन्फ्रास्ट्रक्चर' को नष्ट करना होता है। वे आपके हवाई अड्डों के रनवे, बंदरगाहों की डॉकिंग क्षमता, रेलवे लाइनों की समतलता, भूमिगत तेल-गैस पाइपलाइनों और संचार केबल को निशाना बनाते हैं ताकि आपकी रसद और प्रतिक्रिया क्षमता को पंगु बनाया जा सके। भारत के महानगरों में, हम भूजल का अत्यधिक और अवैज्ञानिक दोहन करके यही काम खुद अपने खिलाफ कर रहे हैं। यह एक ऐसा 'सेल्फ-साबोटेज' है जो किसी रडार पर दिखाई नहीं देता।

इसे अनुभवजन्य दृष्टिकोण से समझें: हवाई अड्डों के रनवे की अखंडता सर्वोच्च प्राथमिकता होती है। रनवे पेवमेंट विश्लेषण बताते हैं कि यदि जमीन असमान रूप से धंस रही है, तो रनवे की ढलान में सूक्ष्म बदलाव आ सकते हैं। शांति काल में, इनकी मरम्मत की जा सकती है, लेकिन एक राष्ट्रीय आपातकाल या

युद्ध की स्थिति में, भारी सैन्य परिवहन विमानों (जैसे C-17 ग्लोबमास्टर) या तेज गति वाले लड़ाकू विमानों की लैंडिंग और टेक-ऑफ के लिए यह एक घातक जोखिम बन सकता है। एक मिलीमीटर का उभार या धंसाव भी उच्च गति पर टायर फटने या लैंडिंग गियर टूटने का कारण बन सकता है।

इसी तरह, ऊर्जा सुरक्षा पर विचार करें। हमारे शहरों के नीचे उच्च दबाव वाली गैस पाइपलाइनों और तेल की लाइनों का जाल बिछा है। 'पाइप फ्रैक्चर मॉडलिंग' अध्ययन दिखाते हैं कि जब मिट्टी असमान रूप से नीचे खिसकती है, तो पाइपों के जोड़ों पर भारी 'शियर स्ट्रेस' पड़ता है। इससे लीकेज, विस्फोट या आपूर्ति में बाधा आ सकती है। मुंबई और चेन्नई जैसे तटीय शहरों में, जहां नौसेना के डॉकयार्ड, पनडुब्बी बेस और तटरक्षक बल के रणनीतिक प्रतिष्ठान हैं, वहां जमीन का धंसना और समुद्र के स्तर का बढ़ना एक दोहरी मार है। जेटी और डॉक का स्तर पानी के सापेक्ष बदल जाता है, जिससे जहाजों की लोडिंग-अनलोडिंग और रखरखाव प्रभावित हो सकता है।

इसके अलावा, आधुनिक शहर 'डेटा' पर चलते हैं। भूमिगत ऑप्टिकल फाइबर केबल्स शहर की तंत्रिका तंत्र हैं। जमीन के खिंचाव से ये नाजुक कांच के तार टूट सकते हैं। बैंकिंग नेटवर्क, स्टॉक एक्सचेंज और सैन्य संचार—सब कुछ इन तारों पर निर्भर है। एक महानगर का संचार ठप्प पड़ जाना या उसकी पाइपलाइनों का फटना केवल एक नागरिक असुविधा नहीं है; यह राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था पर सीधा हमला है और आंतरिक सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा है।

## आंतरिक विस्थापन एवं 'शहरी शरणार्थी':

उत्तराखंड के जोशीमठ की हालिया घटना ने पूरे देश को झकझोर दिया था। हमने देखा कि कैसे लोगों के घरों में दरारें आईं और उन्हें रातों-रात अपना सब कुछ छोड़कर रिलीफ कैंपों में जाना पड़ा। जोशीमठ ने हमें एक झलक दिखाई थी कि जब जमीन रहने लायक नहीं रहती, तो उसका मानवीय चेहरा क्या होता है। लेकिन जोशीमठ एक छोटा पहाड़ी कस्बा था। जब हम दिल्ली, मुंबई या कोलकाता जैसे मेगा-सिटीज के संदर्भ में बात करते हैं, तो पैमाना इतना विशाल हो जाता है कि कल्पना करना भी मुश्किल है। हम यहाँ हजारों नहीं, बल्कि लाखों लोगों के विस्थापन की संभावनाओं को देख रहे हैं।

वैश्विक आकलन बताते हैं कि भारत की 80 मिलियन से अधिक शहरी आबादी ऐसे इलाकों में रहती है जो संभावित रूप से धंसने वाले भूभाग पर स्थित हैं। नेचर सस्टेनेबिलिटी के शोध के अनुसार, दिल्ली के बिजवासन, फरीदाबाद, और मुंबई के धारावी, वडाला या ठाणे के कुछ हिस्से, और चेन्नई के टी. नगर जैसे घनी आबादी

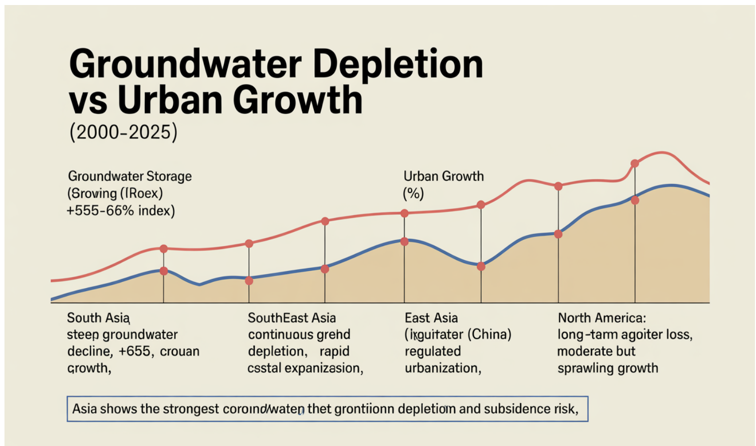


वाले इलाके सबसे अधिक जोखिम में हैं। इन क्षेत्रों में जनसंख्या का घनत्व दुनिया में सबसे अधिक है। यहाँ लाखों लोग रहते हैं। जब इन इलाकों की इमारतों में दरारें 'कॉस्मेटिक' (सतही) से बढ़कर 'स्ट्रक्चरल' (ढांचागत) हो जाएंगी, और नगर निगम के इंजीनियर उन्हें 'असुरक्षित' या 'रहने के अयोग्य' घोषित करेंगे, तो ये लोग कहां जाएंगे?

यह 'आंतरिक विस्थापन' का एक नया, जटिल और क्रूर रूप होगा। हम अक्सर 'क्लाइमेट रिफ्यूजी' या जलवायु शरणार्थी शब्द का प्रयोग करते हैं, जो बाढ़ या सूखे के कारण पलायन करते हैं। लेकिन यहाँ यह शब्द पूरी कहानी नहीं कहता। ये लोग किसी बाढ़ के पानी या सूखे खेत से नहीं भाग रहे होंगे; ये अपने ही पक्के घरों के नीचे से गायब होती जमीन से भाग रहे होंगे। यह विस्थापन वर्ग-भेद को और गहरा करेगा। अमीर वर्ग के पास संसाधनों की उपलब्धता है—वे अपनी

नींव को मजबूत कर सकते हैं ('रेट्रोफिटिंग'), पाइलिंग तकनीक का उपयोग कर सकते हैं, या शहर के सुरक्षित और महंगे इलाकों में जा सकते हैं। लेकिन निम्न और मध्यम वर्ग, जो अक्सर अनधिकृत कॉलोनियों, झुग्गी बस्तियों, चालों या पुरानी कमजोर इमारतों में रहता है, सबसे पहले और सबसे बुरी तरह इसकी चपेट में आएगा। मुंबई की पुरानी चालें या दिल्ली की अनियोजित कॉलोनियां, जो पहले से ही कमजोर बुनियादी ढांचे और खराब निर्माण सामग्री पर टिकी हैं, ताश के पत्तों की तरह ढह सकती हैं। यह एक ऐसी मानवीय त्रासदी होगी जिसका प्रबंधन किसी भी सरकार के लिए दुस्वप्न जैसा होगा।

## यह पानी किसका है?

इस पूरे संकट की जड़ में केवल तकनीकी विफलता नहीं, बल्कि एक गहरा कानूनी और नैतिक प्रश्न छिपा हैः आखिर जमीन के नीचे का पानी किसका है? भारत में, औपनिवेशिक काल के 'इजमेंट एक्ट, 1882' के तहत, यह माना जाता है कि जो व्यक्ति जमीन का मालिक है, उसका उस जमीन के नीचे मौजूद पानी पर भी पूर्ण अधिकार है। यह कानून 19वीं सदी के लिए उपयुक्त हो सकता था, लेकिन 21वीं सदी के मेगा-सिटीज के लिए यह विनाशकारी सिद्ध हो रहा है।

भूजल विज्ञान की दृष्टि से, पानी किसी एक की निजी संपत्ति नहीं है, बल्कि यह एक 'साझा संसाधन' है। एक्विफर सीमाओं को नहीं मानता। जब कोई व्यक्ति या उद्योग अपनी निजी जमीन पर गहरा बोरवेल लगाकर चौबीसों घंटे पानी खींचता है, तो वह केवल 'अपनी' जमीन के नीचे से पानी नहीं ले रहा होता। वह एक साझा कटोरे से पानी निकाल रहा होता है, जिसका असर पड़ोसी की जमीन, पूरे मोहल्ले की नींव और अंततः पूरे शहर की स्थिरता पर पड़ता है। यह अर्थशास्त्र के प्रसिद्ध सिद्धांत 'साझा संसाधनों की त्रासदी' का एक जीवंत और भयानक उदाहरण है, जहाँ व्यक्तिगत लाभ की अनियंत्रित होड़ सामूहिक विनाश का कारण बनती है।

नैतिक रूप से, क्या किसी एक व्यक्ति को यह अधिकार होना चाहिए कि वह अपने स्विमिंग पूल या कार धोने के लिए इतना पानी निकाल ले कि उसके पड़ोसी का घर धंसने लगे? वर्तमान कानूनी ढांचा इस प्रश्न का उत्तर देने में असमर्थ है। जब तक भूजल को निजी संपत्ति के बजाय एक 'राष्ट्रीय धरोहर' और 'सामुदायिक संसाधन' के रूप में परिभाषित नहीं किया जाता, और इसके दोहन को कड़े नियमन के तहत नहीं लाया जाता, तब तक सब्सिडेंस को रोकना असंभव होगा। यह लड़ाई केवल प्रकृति के खिलाफ नहीं, बल्कि हमारी पुरानी और अप्रासंगिक हो चुकी कानूनी मान्यताओं के खिलाफ भी है।

## भू-अर्थशास्त्र का बुलबुला:

रियल एस्टेट भारतीय अर्थव्यवस्था का एक बहुत बड़ा स्तंभ है और मध्यम वर्ग के लिए निवेश का सबसे सुरक्षित जरिया माना जाता है। हम अक्सर सुनते हैं कि अमुक क्षेत्र में जमीन के दाम आसमान छू रहे हैं। 'लोकेशन, लोकेशन, लोकेशन'—यही रियल एस्टेट का मूल मंत्र है। लेकिन क्या होगा जब बाजार को पता चलेगा कि वह 'कीमती जमीन' असल में डूब रही है? लैंड सब्सिडेंस का आर्थिक प्रभाव किसी भी शेयर बाजार के क्रैश से ज्यादा विनाशकारी और स्थायी हो सकता है।

यह घटना संपत्ति के मूल्यों को शून्य कर सकती है। आज जो अपार्टमेंट करोड़ों रुपये में बिक रहे हैं, अगर उन्हें भविष्य के 'हाई रिस्क ज़ोन' या उच्च जोखिम वाले क्षेत्र के रूप में वैज्ञानिक रूप से चिन्हित कर दिया गया, तो उनका बाजार मूल्य रातों-रात गिर जाएगा। यह ' स्ट्रैंडेड एसेट्स ' का क्लासिक मामला होगा—ऐसी संपत्ति जिसका कोई खरीदार नहीं। वैश्विक वित्त और बीमा क्षेत्र, जो जोखिम के गणित में माहिर होते हैं, इस खतरे को भांपने लगे हैं। अमेरिका और यूरोप में, बाढ़ और धंसाव वाले क्षेत्रों में बीमा कंपनियों ने या तो पॉलिसी देना बंद कर दिया है या प्रीमियम इतना बढ़ा दिया है कि वह आम आदमी की पहुंच से बाहर है। भारत में भी, भविष्य में 'सब्सिडेंस-प्रोन' क्षेत्रों में संपत्तियों का बीमा करना असंभव हो सकता है।

इसके दूरगामी परिणाम होंगे। यदि बैंक ऐसे क्षेत्रों में होम लोन देना बंद कर दें, क्योंकि गिरवी रखी गई संपत्ति का भविष्य अनिश्चित है, तो पूरा हाउसिंग मार्केट ध्वस्त हो सकता है। जिन लोगों ने 20 या 30 साल के लोन लिए हैं, वे पाएंगे कि वे एक ऐसी संपत्ति की ईएमआई भर रहे हैं जिसकी कीमत अब उनके लोन की राशि से भी कम है। इसके अलावा, नगर निगमों पर पड़ने वाले आर्थिक बोझ की कल्पना करें। बार-बार टूटती सड़कों

# द्वारका: डूबा शहर, जीवित चेतावनी

समुद्रों की स्मृति लंबी होती है। समुद्र में केवल लहरें नहीं उठाती— बल्कि सभ्यताओं की कहानियां भी उठती और हमारे सामने आती हैं। भारत के पश्चिमी तट से कुछ मील दूर, अरब सागर की शांत सतह के नीचे एक नगर सो रहा है—द्वारका। हां, वही द्वारका, जो कभी कृष्ण की राजधानी थी, अब समुद्र की गहराइयों में एक टूटे हुए अतीत की तरह बिखरा पड़ा है।

द्वारका का डूबना पौराणिक कथा नहीं; यह एक भूगर्भिक सच्चाई है। समुद्र तल के नीचे मिली दीवारें, पत्थर के बंदरगाह, एंकर, ग्रिडनुमा नगर विन्यास—ये सब इस बात के मौन सबूत हैं कि कभी यहां एक जीवंत, सुनियोजित, शक्तिशाली महानगर बसता था। नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी (एनआईओ) और नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी (एनआईओटी) के समुद्री पुरातत्व अभियानों ने 70 से 120 मीटर गहराई में जो कुछ पाया, वह इतना आधुनिक, इतना ज्यामितीय था कि विज्ञान को भी पौराणिकता की ओर झुकना पड़ा।

नासा के उपग्रहों ने भी समुद्र के नीचे फैली मानव निर्मित संरचनाओं जैसी आकृतियों की पुष्टि की—मानो स्वर्ग से उतरकर एक भूली हुई नगरी का नक्शा दोहराया जा रहा हो। लेकिन द्वारका इसलिए नहीं डूबी कि समुद्र अचानक क्रूर हो गया था। वह इसलिए डूबी क्योंकि समय, समुद्री-स्तर का बढ़ना और तटीय अस्थिरता—इन तीनों ने मिलकर उसके स्वर्णिम अहंकार को भंग कर दिया। आज जकार्ता, चेन्नई, मुंबई, कोलकाता, मेक्सिको सिटी, शंघाई—ये सभी वैश्विक महानगर उसी प्रश्न के सामने खड़े हैं जिस पर द्वारका हज़ारों साल पहले खड़ी थी- क्या कोई भी शहर इतना महान है कि प्रकृति के संतुलन को चुनौती दे सके? और क्या कोई भी सभ्यता अपनी ही कुप्रबंधन और लालच से बच पाती है?

द्वारका के डूबने और आज के महानगरों के धंसने के बीच एक सीधा-सा सूत्र छिपा है— एक सूत्र जो चेतावनी देता है कि सभ्यताएं बाहर से नष्ट नहीं होतीं; वे भीतर से खोखली होती हैं। द्वारका समुद्र में समा गई— और आज दिल्ली, चेन्नई, मुंबई, कोलकाता जमीन में धंस रहे हैं।

एक पौराणिक शहर समुद्र के नीचे सो रहा है, और आधुनिक महानगर भविष्य के समुद्र और भविष्य की जमीन के भार तले कराह रहे हैं। हमारी चुनौतियां नई हैं, लेकिन प्रकृति का संदेश वही है- अहंकार—चाहे वह पौराणिक हो या आधुनिक—समुद्र के सामने टिकता नहीं।

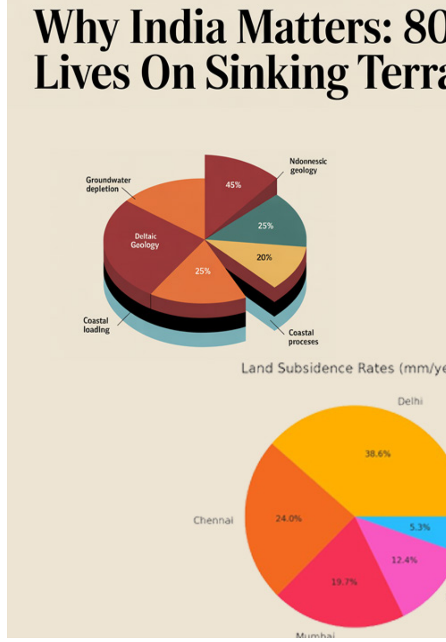


को भरना, भूमिगत सीवेज लाइनों को बदलना जो ढलान बिगड़ने से जाम हो गई हैं, मेट्रो के पिलर्स को जैक-अप करना—यह सब अरबों रुपये का खर्च मांगता है। यह एक 'अदृश्य कर' है जो शहर का हर नागरिक चुकाएगा, चाहे वह सीधे मरम्मत के लिए दे या बढ़े हुए टैक्स के माध्यम से।

## पांच शहरों की कहानी: अलग भूगोल, साझा पतन

भारत के पांच महानगरों की स्थिति का सूक्ष्म विश्लेषण करने पर हमें पता चलता है कि समस्या का मूल कारण एक ही है—पानी का लालच और कुप्रबंधन—लेकिन भौगोलिक परिस्थितियों के अनुसार इसके लक्षण और खतरे अलग-अलग हैं।

दिल्ली-एनसीआर का मामला शायद सबसे गंभीर और जटिल है। यहां की मिट्टी मुख्य रूप से 'एल्यूवियल' (जलोढ़) है, जो गंगा और यमुना नदियों द्वारा हजारों वर्षों में जमा की गई है। यह मिट्टी कृषि

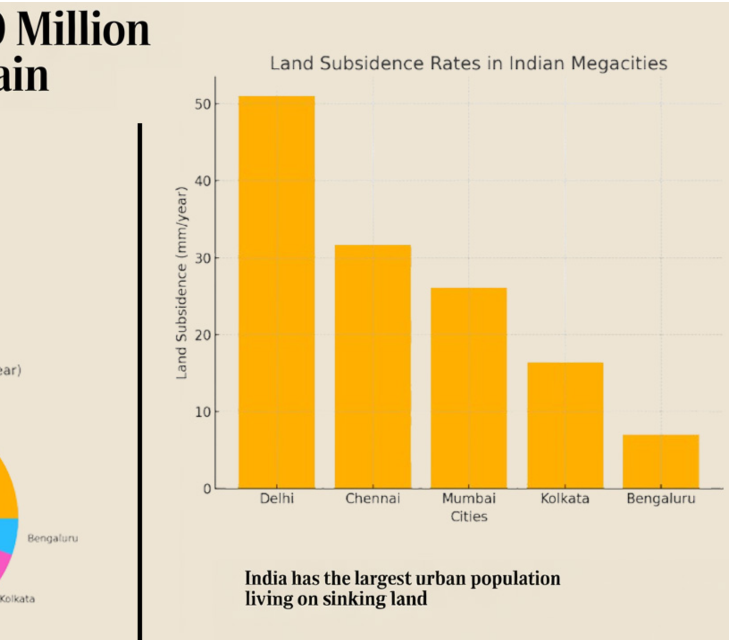


के लिए वरदान है, लेकिन इंजीनियरिंग के लिए चुनौती। इसमें गाद और क्ले की परतें होती हैं जो बहुत 'कंप्रेसिबल' (दबने योग्य) होती हैं। जब इसमें से पानी निकाला जाता है, तो यह तेजी से सिकुड़ती है। दिल्ली में भूजल का स्तर पाताल में जा रहा है। द्वारका, कापसहेड़ा और दक्षिणी दिल्ली के पॉश इलाकों में, जहां बड़े फार्महाउस और सोसायटियां हैं, वहां बोरवेल की मोटरें दिन-रात चलती हैं। यह एक विडंबना है कि यमुना के खादर, जिन्हें प्राकृतिक रूप से पानी सोखने और शहर को रिचार्ज करने के लिए छोड़ा जाना चाहिए था, वहां अब कंक्रीट के जंगल हैं। भारी निर्माण का भार ऊपर से और पानी की निकासी नीचे से—यह दिल्ली के लिए दोहरी मुसीबत है।

कोलकाता और चेन्नई की कहानी तटीय मिट्टी की संरचना से जुड़ी है। कोलकाता हुगली नदी के डेल्टा पर बसा है। यहाँ की मिट्टी में 'क्ले' (चिकनी मिट्टी) और कार्बनिक पदार्थों की मात्रा बहुत अधिक है। क्ले की विशेषता यह है कि पानी निकलने पर यह स्पंज की तरह बहुत ज्यादा सिकुड़ती है। कोलकाता की पुरानी, ऐतिहासिक इमारतें, जो उथली नींव पर बनी हैं, अब अपने ही वजन और नीचे की मिट्टी के बैठ जाने के कारण झुक रही हैं। चेन्नई में, टी. नगर और अडयार नदी के बाढ़ क्षेत्रों में हुआ अनियंत्रित निर्माण और तटीय रेत का स्वभाव इसे संवेदनशील बनाता है। यहां खतरा दोगुना है: जब जमीन नीचे जाएगी और जलवायु परिवर्तन के कारण समुद्र का स्तर बढ़ेगा, तो खारे पानी का प्रवेश होगा।

मुंबई का संकट मानव निर्मित भूमि का संकट है। यह शहर सात द्वीपों को जोड़कर बनाया गया था। शहर का एक बड़ा हिस्सा—नरीमन पॉइंट से लेकर बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स तक—समुद्र को पीछे

## भारत का 'रेड अलर्ट': जोखिम में पांच महानगर

भारत दुनिया का एकमात्र देश है जहाँ 5 मेगासिटीज़ एक साथ 'हाई रिस्क' में हैं।

**भू-धंसान की अधिकतम दरें:**

**दिल्ली (एनसार): 51 मिमी/वर्ष**

(कापसहेड़ा, बिजवासन – गंभीर एक्विफर गिरावट)

**चेन्नई: 31.7 मिमी/वर्ष**

(अडयार बेसिन – तटीय खारे पानी के घुसने का जोखिम)

**मुंबई: 26 .1 मिमी/वर्ष**

(रीक्लेम्ड लैंड – बाढ़ और जल निकासी की विफलता)

**कोलकाता: 16 .4 मिमी/वर्ष**

(चिकनी मिट्टी का सघनीकरण – ऐतिहासिक इमारतों को खतरा)

**बेंगलुरु: 6–7 मिमी/वर्ष**

(स्थानीय डिप्रेशन – अनियोजित बोरवेल्स का प्रभाव)

**वैश्विक संदर्भ में:** जीआरएसीई-एफओ उपग्रह डेटा के अनुसार, भारत भूजल ह्रास में दुनिया के शीर्ष 3 देशों में शामिल है।

(स्रोत: नेचर सस्टेनबिलिटी, 2024 एवं जीआरएसीई-एफओ का डेटा )

धकेल कर और दलदल को भरकर बनाया गया है। यह भराई वाली जमीन स्वाभाविक रूप से अस्थिर होती है और दशकों तक धीरे-धीरे बैठती रहती है । इस अस्थिर जमीन पर गगनचुंबी इमारतों का निर्माण एक जोखिम भरा जुआ है। धारावी जैसे इलाकों में, जहां जनसंख्या का घनत्व और निर्माण का भार चरम पर है, वहां जमीन का थोड़ा सा भी धंसना जल निकासी को बाधित कर देता है। यही कारण है कि मुंबई में अब हर साल बारिश में बाढ़ की स्थिति बदतर होती जा रही है।

बेंगलुरु के बारे में यह भ्रांति थी कि वह सुरक्षित है क्योंकि वह

## धरती क्यों धंसती है? क्या है वैज्ञानिक कारण?

**भूजल का अत्यधिक दोहन (59% मामलों का कारण):**

जब एक्विफर खाली होते हैं, तो पानी का दबाव घटता है और मिट्टी के कण आपस में चिपक जाते हैं। यह प्रक्रिया अक्सर अपरिवर्तनीय होती है।

**मुलायम तलछटी भूमि**

दुनिया के 70% डूबते शहर डेल्टा या बाढ़ के मैदानों पर बसे हैं। यह मिट्टी स्वाभाविक रूप से दबने योग्य होती है।

**शहरी भार:**

कंक्रीट के जंगल का वजन लाखों टन होता है, जो कमजोर जमीन को नीचे धकेलता है।

जलवायु परिवर्तन:

सूखा भूजल की मांग बढ़ाता है, और समुद्र के स्तर में वृद्धि तटीय शहरों पर दोहरी मार करती है।

(स्रोत: साइंस जर्नल, 2021 एवं यूएसजीएस)

डक्कन के पठार की कठोर ग्रेनाइट चट्टानों पर स्थित है। लेकिन आधुनिक डेटा ने इस भ्रम को तोड़ दिया है। हेब्बल, बेलांदूर और व्हाइटफील्ड जैसे नए विकसित आईटी हब, जहां कभी झीलें और तालाब हुआ करते थे, वहां अब विशाल ग्लास की इमारतें हैं। इन इलाकों में झीलों को पाट दिया गया है और पानी के लिए पूरी तरह से टैंकरों और हजारों फीट गहरे बोरवेल पर निर्भरता है। चट्टानों के ऊपर की जो मिट्टी की परत है, वह सूख रही है और धंस रही है। यह बताता है कि रॉक-बेड भी आपको पूरी तरह सुरक्षित नहीं रख सकता यदि आप पारिस्थितिकी के साथ खिलवाड़ करते हैं।

### इतिहास और वर्तमान के सबक

भारत इस लड़ाई में अकेला नहीं है। यह एक वैश्विक महामारी है जो मानव विकास के मॉडल पर प्रश्नचिह्न लगाती है। इंडोनेशिया का उदाहरण सबसे ज्वलंत है। वहां की सरकार ने अपनी राजधानी जकार्ता को छोड़ने का ऐतिहासिक और कड़वा फैसला किया है, मुख्य रूप से इसलिए क्योंकि उसका 40% हिस्सा समुद्र तल से नीचे जा चुका है और पंपिंग के बावजूद बाढ़ का पानी नहीं निकलता। वे अब बोर्नियो के जंगलों में 'नुसंतारा' नामक नई राजधानी बना रहे हैं, जिसकी लागत 30 अरब डॉलर से अधिक है। लेकिन क्या भारत अपनी राजधानियों को स्थानांतरित कर सकता है? क्या हम दिल्ली को छोड़कर कहीं और जा सकते हैं? नहीं। हमारे पास न तो वैसी भूमि है और न ही संसाधन। मेक्सिको सिटी, जो एक पुरानी झील की तलहटी पर बसा है, पिछले 100 वर्षों में 10 मीटर तक धंस चुका है। वहां ऐतिहासिक गिरजाघर टेढ़े हो चुके हैं। लेकिन दुनिया में उम्मीद की किरणें भी हैं। जापान की राजधानी टोक्यो ने हमें रास्ता दिखाया है। 1960 के दशक में टोक्यो भी तेजी से डूब रहा था। वहां की सरकार ने कड़े कदम उठाए। उन्होंने उद्योगों द्वारा भूजल के उपयोग पर सख्त प्रतिबंध लगाए और वैकल्पिक जल स्रोतों की व्यवस्था की। परिणाम यह हुआ कि दशक भर में धंसने की दर लगभग शून्य हो गई। यह साबित करता है कि यदि राजनीतिक इच्छाशक्ति और सही नीतियां हों, तो इस आपदा को रोका जा सकता है।

### नीतिगत हस्तक्षेप और सुधार

तो, क्या सब कुछ खत्म हो चुका है? क्या हम नियति के हाथों मजबूर हैं? वैज्ञानिक और नीति-विश्लेषक कहते हैं—नहीं, अभी पूरी तरह से देर नहीं हुई है। उपग्रह डेटा में एक आश्चर्यजनक और सकारात्मक संकेत भी मिला है। दिल्ली के ही द्वारका क्षेत्र के

कुछ हिस्सों में, जहां 2012 के बाद से वर्षा जल संचयन को कड़ाई से लागू किया गया और सोसायटियों ने सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के पानी का उपयोग पार्कों और झीलों को भरने के लिए किया, वहां जमीन के स्तर में मामूली 'उठान' या स्थिरता देखी गई है। यह प्रमाण है कि सही नीतियों से बदलाव संभव है। भारत को तत्काल प्रभाव से एक बहुआयामी कार्ययोजना लागू करनी होगीः

सबसे पहले, हमें एक 'राष्ट्रीय सब्सिडेंस निगरानी इकाई' की स्थापना करनी होगी। इनसार और जीआरएसीई-एफओ डेटा का उपयोग करके एक केंद्रीय रीयल-टाइम डैशबोर्ड बनाया जाना चाहिए, जो देश के हर नगर निगम और शहरी योजना विभाग को सुलभ हो। यह डैशबोर्ड बताएगा कि कौन सा इलाका 'रेड ज़ोन' में है। यह डेटा केवल वैज्ञानिकों तक सीमित न रहे, बल्कि इसे शहर के मास्टर प्लान का हिस्सा बनाया जाए।

दूसरा महत्वपूर्ण कदम है 'अनिवार्य सब्सिडेंस ऑडिट'। किसी भी बड़ी बुनियादी ढांचा परियोजना—चाहे वह मेट्रो हो, फ्लाईओवर हो, या गगनचुंबी इमारत—की अनुमति देने से पहले उस क्षेत्र की मिट्टी की स्थिरता और भविष्य के संभावित धंसाव का ऑडिट अनिवार्य होना चाहिए। बाढ़ के मैदानों को कानूनी रूप से 'नो-कंस्ट्रक्शन ज़ोन' घोषित किया जाना चाहिए, क्योंकि नदी किनारे की तलछट सबसे अधिक दबने योग्य होती है।

तीसरा, हमें भूजल दोहन के नियमन में आमूलचूल परिवर्तन करना होगा। निजी बोरवेल पर लाइसेंसिंग और डिजिटल मीटरिंग अनिवार्य होनी चाहिए। उद्योगों और बड़ी हाउसिंग सोसायटियों के लिए 'पानी का बजट' तय किया जाना चाहिए। साथ ही, कृषि में पानी के उपयोग को कम करने के लिए ड्रिप इरिगेशन जैसी तकनीकों को आक्रामक रूप से बढ़ावा देना होगा, क्योंकि परिधि क्षेत्रों में कृषि के लिए निकाला गया पानी भी शहरी जल स्तर को प्रभावित करता है। चौथा, केवल रेनवाटर हार्वेस्टिंग काफी नहीं है; हमें 'प्रबंधित एक्विफर रिचार्ज' की दिशा में बढ़ना होगा। शहरों को 'स्पंज सिटी' के कांसेप्ट में बदलना होगा। इसका अर्थ है कंक्रीट की सतहों को कम करना और पार्कों, झीलों और वेटलैंड्स को पुनर्जीवित करना ताकि बारिश का पानी नालों में बहने के बजाय जमीन में जाए। दिल्ली के द्वारका का उदाहरण दिखाता है कि यह रणनीति काम करती है।

अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण, हमें 'विभेदित भवन संहिता' अपनानी होगी। जिन क्षेत्रों को 'हाई रिस्क' के रूप में पहचाना गया है (जैसे मुंबई का रिक्लेम्ड लैंड या कोलकाता का क्ले क्षेत्र), वहां निर्माण के मानक सामान्य क्षेत्रों से अलग और सख्त होने चाहिए। वहां हल्की निर्माण सामग्री, गहरी नींव और लचीली पाइपलाइनों का उपयोग अनिवार्य होना चाहिए।

## शांति काल की अंतिम चेतावनी

इतिहास गवाह है कि दुनिया की महान सभ्यताओं का अंत अक्सर बाहरी आक्रमणों से नहीं, बल्कि उनके अपने संसाधनों के कुप्रबंधन और पारिस्थितिक आत्महत्या से हुआ है। सिंधु घाटी की हड़प्पा सभ्यता के पतन का एक प्रमुख कारण नदियों के मार्ग का बदलना और जल प्रबंधन की विफलता माना जाता है। माया सभ्यता का अंत भी भयंकर सूखे और जल संकट के कारण हुआ। आज, 21वीं सदी में, हम आधुनिक तकनीक, उपग्रहों और सुपरकंप्यूटरों के साथ वही गलती दोहरा रहे हैं, लेकिन बहुत बड़े और विनाशकारी पैमाने पर।

लैंड सब्सिडेंस या जमीन का धंसना प्रकृति का हमें भेजा गया अंतिम 'कारण बताओ' नोटिस है। यह एक 'शांति काल की चेतावनी' है। हमारे पास अभी भी संभलने का, अपनी नीतियों को सुधारने का और पानी के साथ अपने रिश्ते को फिर से परिभाषित करने का एक छोटा, लेकिन महत्वपूर्ण अवसर है। यह अवसर खिड़की की तरह है जो धीरे-धीरे बंद हो रहा है।

सवाल यह नहीं है कि क्या हमारे शहर डूब रहे हैं—वैज्ञानिक डेटा ने यह संदेह से परे साबित कर दिया है कि वे डूब रहे हैं। असली सवाल यह है कि क्या हम, एक सभ्यता और एक राष्ट्र के रूप में, इस मौन आपदा की आवाज को सुनने की क्षमता रखते हैं? क्या हम अपने 'विकास' की परिभाषा को बदल सकते हैं? क्या हम अपनी आज की प्यास को नियंत्रित कर सकते हैं ताकि हमारे बच्चों को कल पैर रखने के लिए ठोस जमीन मिल सके?

या फिर हम भविष्य की पीढ़ियों को टूटी हुई नींव, झुकी हुई इमारतें, बेकार पड़ी पाइपलाइनें और खारे पानी में डूबे हुए स्मारक विरासत में देंगे? ठीक वैसे ही जैसे जकार्ता की वह वालादुना मस्जिद आज खड़ी है—मौन, वीरान, काई से ढकी और आधी डूबी हुई। वह मस्जिद हमसे कुछ कह रही है। वह कह रही है कि धरती का धैर्य अनंत नहीं है। चुनाव हमारा है, लेकिन समय, हमारे पैरों के नीचे की उस धंसती हुई रेत की तरह, मुट्ठी से फिसलता जा रहा है।

# हाल-ए-पाकिस्तान
# वर्दी में लोकतंत्र

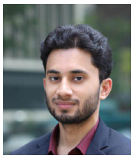

राजीव सिन्हा

सरल शर्मा

**पाकिस्तान में सत्ता की परतों के नीचे एक 'साइलेंट तख़्तापलट' आकार ले चुका है, जिसने नागरिक शासन को हाशिए पर धकेलते हुए सैन्य प्रतिष्ठान की पकड़ को और कड़ा कर दिया है। क्षेत्रीय अस्थिरता, आर्थिक अव्यवस्था और आंतरिक दमन के बीच जनरल की यह जकड़ पाकिस्तान के भविष्य को निर्णायक मोड़ पर ला खड़ा करती है।**

पाकिस्तानी संसद में हाल ही में पारित 27वां संविधान संशोधन देश के नाज़ुक लोकतंत्र पर सेना के प्रभुत्व को और ज़्यादा मज़बूत करेगा। संविधान में ये नवीनतम संशोधन फील्ड मार्शल और सेनाध्यक्ष सैयद आसिम मुनीर को अभूतपूर्व शक्ति और कानूनी छूट प्रदान करता है। हकीक़त तो ये है कि इस संविधान संशोधन के पारित होने के बाद ये स्पष्ट हो गया

है कि सेना ने एक बार फिर राष्ट्र और नागरिक नेतृत्व को मात दे दी है। सरकार को ही नहीं, इस संशोधन ने न्यायपालिका सहित प्रमुख लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमज़ोर कर दिया है। ये संशोधन 1973 के संविधान को पलटने और सत्ता के संतुलन को सेना के पक्ष में मोड़ने की एक और कोशिश है। इससे नागरिक नेतृत्व की भूमिका और कमज़ोर होगी जबकि पहले से ही मज़बूत सेना के पास असीमित शक्तियां आ जाएंगी। इस संशोधन के बाद सत्ता परिवर्तन की सूरत में भी मुनीर की शक्तियों में कोई कमी नहीं आएगी। आसिम मुनीर को अब कोई भी कानून छू नहीं सकता, उन्हें आधिकारिक तौर पर दूसरी सभी सैन्य शाखाओं यानी पाकिस्तानी नेवी और एयरफोर्स के प्रमुखों से ऊपर रख दिया गया है।

## बिना तख्तापलट किए ही सत्ता पर कब्ज़ा

पाकिस्तान के संविधान के अनुच्छेद 243 को फिर से लिखकर एक नया सर्वोच्च सैन्य पद सृजित किया गया है। ये पद है चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज़ (सीडीएफ) का। खास बात ये है कि मौजूदा सेनाध्यक्ष यानी आसिम मुनीर खुद ही इस पद पर आसीन हो जाएंगे। संविधान संशोधन के मुताबिक इस नए पद की स्थापना के बाद, चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी (सीजेसीएससी) के अध्यक्ष का पद ख़त्म माना जाएगा। इस पद का उद्देश्य तीनों सेनाओं के बीच समन्वय स्थापित करना था। 27 नवंबर 2025 को, जब मौजूदा वर्तमान सीजेसीएससी रिटायर होंगे, तब फील्ड मार्शल मुनीर, सेना प्रमुख के रूप में, सीडीएफ की भूमिका भी संभालेंगे और औपचारिक रूप से सभी सेवा शाखाओं को अपने अधीन कर लेंगे। इसका अर्थ ये होगा कि सेना अब पूरे सैन्य ढांचे पर उस तरह से हावी हो जाएगी, जैसा पाकिस्तान के इतिहास में पहले कभी नहीं देखा गया। इस बदलाव के बाद पाकिस्तानी वायुसेना और नौसेना के थल सेना प्रमुख के अधीन होने का खतरा है। हालांकि, इससे असंतोष भड़क सकता है और तीनों सेनाओं के बीच प्रतिद्वंद्विता बढ़ सकती है।

अगर ये संविधान संशोधन सिर्फ सैन्य कमान श्रृंखला में बदलाव तक ही सीमित रहता, तब भी गनीमत रहती लेकिन ये देश के परमाणु हथियारों पर नागरिक नेतृत्व की निगरानी को भी कमज़ोर करेगा। पाकिस्तान के परमाणु बलों की निगरानी के लिए राष्ट्रीय सामरिक कमान के कमांडर (सीएनएससी) का एक नया पद सृजित किया जाएगा। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, सेना प्रमुख/सीडीएफ की सलाह से सेना के जनरलों में से किसी एक को सीएनएससी नियुक्त करेंगे। सैद्धांतिक तौर पर भले ही ये लगे कि, इसमें प्रधानमंत्री की भी भूमिका रहेगी, लेकिन अगर व्यावहारिक अर्थ में बात करें तो आसिम मुनीर और भावी सेना प्रमुख ही पाकिस्तान के परमाणु बलों के प्रभारी अधिकारी का चयन स्वयं करेंगे। ये कमांडर फिर सेना की कमान श्रृंखला के माध्यम से मुनीर को ही रिपोर्ट करेगा। इससे राष्ट्रीय कमान प्राधिकरण (एनसीए) का नियंत्रण कमज़ोर हो सकता है। एनसीए का गठन परमाणु कार्यक्रम संबंधी निर्णय लेने में असैन्य नेताओं और सभी सेना प्रमुखों को शामिल करने के लिए किया गया था। वर्तमान एनसीए प्रणाली में, रणनीतिक निर्णय, विशेष रूप से परमाणु हथियारों के उपयोग से संबंधित फैसले लेने के लिए, सामूहिक सुझाव की ज़रूरत होती है और ये सब काम प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में होता है। हालिया संविधान संशोधन परमाणु कमान को सेना द्वारा चुने गए एक जनरल के अधीन कर देगा, जिससे रावलपिंडी स्थित सेना के जनरल हेडक्वार्टर (जीएचक्यू) पर कड़ा नियंत्रण स्थापित हो जाएगा।

## कानून से भी ऊपर हो गए मुनीर

इसके अलावा, चिंताजनक बात ये है कि एक अभूतपूर्व कदम के तहत, एक 'लोकतांत्रिक' देश में नेताओं और अधिकारियों को जवाबदेह ना ठहराने से शीर्ष सैन्य अफसरों को व्यापक व्यक्तिगत विशेषाधिकार मिल गए हैं। अब वो कानून से ऊपर हो गए हैं, किसी कोर्ट में उनपर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। ये संशोधन पांच सितारा रैंक तक पहुंचे किसी भी अफसर को आजीवन संवैधानिक संरक्षण प्रदान करता है। पांच सितारा रैंक में फील्ड मार्शल (थल सेना), मार्शल ऑफ द एयर फोर्स (वायुसेना), या एडमिरल ऑफ द फ्लीट (नौसेना) जैसे पद आते हैं। पाकिस्तान में इन रैंकों का इस्तेमाल कम ही होता रहा है, लेकिन मई 2025 में भारत के साथ एक सैन्य संघर्ष के बाद आसिम मुनीर का जल्दबाजी में फील्ड मार्शल के पद पर प्रमोशन कर दिया गया। अनुच्छेद 243 में किया गया नवीनतम संशोधन संविधान में मुनीर की पदोन्नति को सुनिश्चित करने और उनका का दर्जा आजीवन सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया कदम है। नए संशोधन के प्रावधानों के तहत, एक पांच सितारा रैंक का अधिकारी 'जीवन भर पद, विशेषाधिकार और वर्दी धारण करेगा'। उस पर सिर्फ महाभियोग के तहत ही कार्रवाई की जा सकती है। आसान शब्दों में कहें तो, कानूनी तौर पर, आसिम मुनीर दोषमुक्त और कोर्ट की पहुंच से दूर होंगे। इसकी वजह ये है कि कोई भी अदालत या भविष्य की नागरिक सरकार संसद में दो-तिहाई बहुमत के बिना पांच सितारा रैंक के अफसर पर किसी अपराध का आरोप नहीं लगा सकती या उसे पद से नहीं हटा सकती। इसी तरह, नौसेना और वायु सेना प्रमुखों को भी, फील्ड मार्शल मुनीर की तरह, मई 2025 में चलाए गए ऑपरेशन बनयान अल मार्सूस में उनकी भूमिका के लिए एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिजर(एसओपी) दी गई है। वे भी चार सितारा जनरलों के रूप में आजीवन खाकी वर्दी पहनेंगे और उन्हें भी किसी भी तरह की कानूनी कार्रवाई से छूट हासिल होगी।

इस संविधान संशोधन को लेकर एक चिंताजनक बात ये भी है कि, इससे पाकिस्तान में न्यायपालिका की स्वतंत्रता और कमज़ोर होगी। शाहबाज़ शरीफ सरकार के कार्यकाल की शुरुआत से ही अदालतों की स्वायत्तता को कमज़ोर करने की कोशिश की गई और ये सिलसिला अब तक जारी है। ये संशोधन संवैधानिक मामलों को निपटाने के लिए

एक नए संघीय संवैधानिक न्यायालय (FCC) की स्थापना करता है, जिससे संविधान की सबसे बड़ी कानूनी संस्था के रूप में सर्वोच्च न्यायालय की भूमिका कमज़ोर हो जाती है। पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का दर्जा नई संघीय संवैधानिक अदालत के चीफ जस्टिस से जूनियर का होगा। संघीय संवैधानिक अदालत के मुख्य न्यायाधीश 68 साल की उम्र तक अपने पद पर रह सकेंगे, जबकि पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस की रिटायरमेंट की उम्र 65 साल है। न्यायपालिका की आज़ादी को धीरे-धीरे कम कर देना आसिम मुनीर और इस्लामाबाद में शहबाज़ शरीफ के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार की एक उल्लेखनीय उपलब्धि रही है। हालांकि, ये हो सकता है कि भविष्य में इस उपलब्धि को लोकतंत्र के लिए एक बड़ी नाकामी माना जाएगा।

पाकिस्तान में अदालतों के अधिकार कम करने का सिलसिला 2024 में शुरू हुआ, तब संसद ने विवादास्पद 26वां संशोधन पारित किया। इस संशोधन के ज़रिए न्यायिक नियुक्तियों की प्रक्रिया में बदलाव किया और सुप्रीम कोर्ट की किसी भी मामले में स्वतः संज्ञान लेकर सुनवाई करने की शक्ति को ख़त्म कर दिया गया। एक समय ऐसा भी था, जब 2008 में जनरल मुशर्रफ को सत्ता से हटाने में अदालतों ने सबसे बड़ी भूमिका निभाई थी, लेकिन प्रस्तावित बदलावों के बाद पाकिस्तान की न्यायपालिका पूरी तरह से राजनीतिक हो जाएगी और कार्यपालिका के नियंत्रण में आ जाएगी। परोक्ष रूप से न्यायपालिका अब सैन्य प्रतिष्ठान के नियंत्रण में होगी। पाकिस्तान का सर्वोच्च न्यायालय अब अपने पहले के शक्तिशाली रूप की कमज़ोर छाया मात्र रह गया है। फिलहाल पाकिस्तानी की खुशकिस्मती ये है कि मुनीर और शाहबाज़ शरीफ ने मुख्य न्यायाधीश याह्या अफरीदी को अपने तय कार्यकाल तक पाकिस्तान के मुख्य न्यायाधीश के पद पर बनाए रखने का फैसला किया है। उसके बाद, पाकिस्तान के मुख्य न्यायाधीश का पद वो जस्टिस संभालेंगे, जो संघीय संवैधानिक न्यायालय और पाकिस्तान के सर्वोच्च न्यायालय में से वरिष्ठ होंगे।

## नाना और मां के 'बलिदान' को भूले बिलावल

सबसे दुखद बात ये है कि पाकिस्तान के राजनीतिक नेतृत्व ने सेना और आसिम मुनीर को मज़बूत करने वाले इन संवैधानिक संशोधनों पर सहमति जताकर झुकने का काम किया है। ये इस बात का स्पष्ट संकेत है कि, पिछले तीन साल में पाकिस्तान की लोकतांत्रिक संस्थाएं कितनी कमज़ोर और शक्तिहीन हो गई हैं। शाहबाज़ सरकार ने प्रमुख राजनीतिक दलों की लगभग चुप्पी के माहौल में सीनेट में ये संशोधन पेश किया। सीनेट में सांकेतिक विरोध और थोड़े बहुत हंगामे और नाराज़गी के बीच ये संशोधन दो-तिहाई बहुमत से पारित भी हो गया। मुस्लिम लीग-(नवाज़) और पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी (पीपीपी) सत्तारूढ़ गठबंधन के हिस्से के रूप में इस संशोधन के सूत्रधार थे। हैरानी की बात ये है कि पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी ऐतिहासिक

रूप से अलग-अलग समयों पर सैन्य प्रभुत्व के आलोचक रही है। ज़ुल्फिकार अली भुट्टो और उनकी बेटी बेनज़ीर भुट्टो ने इस विरोध की कीमत अपनी जान देकर चुकाई। वही पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी आज तकनीकी दलीलों और राष्ट्रवादी बयानबाज़ी के ज़रिए सेना को मज़बूत करने वाले इस संविधान संशोधन को सही ठहरा रही है। ऐसा लगता है पीपीपी के नेता बिलावल भुट्टो इस संशोधन की वजह से पाकिस्तान को होने वाले दीर्घकालिक नुकसान पर विचार करने के बजाय मुनीर की कृपादृष्टि बनाए रखने पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। पाकिस्तान की 'हाइब्रिड' व्यवस्था अब इस हद तक बिगड़ चुकी है कि नागरिक सरकार के दख़ल का पता भी नहीं चलता।

आसिम मुनीर की सत्ता की जो भूख दिख रही है, उस प्रवृत्ति की तुलना 1980 के दशक में जनरल ज़िया-उल-हक़ और 2000 के दशक के शुरुआती वर्षों में जनरल परवेज़ मुशर्रफ़ जैसे सैन्य शासकों से की जा सकती है। तीनों में कई स्पष्ट समानताएं हैं। ज़िया-उल-हक़ और मुशर्रफ़, दोनों ने संसद और अदालतों को दरकिनार कर दिया, अपना हुक्मनामा चलाया और फिर अपने प्रभुत्व को संस्थागत बनाने के लिए संवैधानिक संशोधनों का सहारा लिया। ज़िया के शासनकाल के दौरान आठवां संशोधन हुआ, जबकि मुशर्रफ़ के समय सत्रहवें संशोधन को अंजाम दिया। मुनीर की तरह ही, उन्होंने कई साल तक सत्ता अपने हाथों में केंद्रित रखी। इन सब समानताओं के बावजूद, मुनीर के दृष्टिकोण में कुछ बड़े अंतर भी हैं। अपने पूर्ववर्तियों यानी ज़िया-उल-हक़ और परवेज़ मुशर्रफ़ की तरह मुनीर ने ना तो पूरी तरह से मार्शल लॉ लागू किया है, और ना ही उन्होंने अब तक राष्ट्रपति पद जैसे किसी औपचारिक नागरिक पद को ग्रहण किया है। इसकी

बजाए, मुनीर पर्दे के पीछे से सत्ता को अपने हिसाब से चला रहे हैं, और दुनिया को दिखाने के लिए नागरिक नेतृत्व वाली व्यवस्था को काम करने दे रहे हैं।

## मुनीर को देश में सत्ता मिली, विदेश में सम्मान

मुनीर ने एक आज्ञाकारी सरकार का फ़ायदा उठाकर सेना को मज़बूत बनाने वाले कानून पारित किए हैं। इससे उन्हें दो प्रत्यक्ष फायदे मिलते हैं। पहला फायदा तो ये है कि मुनीर तख़्तापलट से होने वाली अंतर्राष्ट्रीय बदनामी से बच जाते हैं, और दूसरा लाभ ये है कि रोज़मर्रा के शासन की थकान का सामना किए बिना वो अपने लक्ष्यों को आसानी से हासिल कर ले रहे हैं। दिखावे के लिए ही सही, लेकिन मुनीर कम से कम नाममात्र के लिए ही एक संवैधानिक ढांचे के अधीन रहते हुए काम कर रहे हैं। हालांकि, वो जब चाहें, नीतियों को अपने हिसाब से बदल रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि मुनीर ना अपना दर्जा ऐसा बना लिया है, जो उन्हें भविष्य में कई तरीके से फायदा पहुंचाएगा। फील्ड मार्शल के तौर पर हालिया संवैधानिक संशोधन के बाद अब कानून भी उन्हें नहीं छू सकता। ऐसा दर्जा ना तो ज़िया-उल-हक़ को मिला और ना ही मुशर्रफ़ को। कम से कम इतने स्पष्ट रूप से उन्हें ये विशेषाधिकार नहीं मिले। पिछले तीन सालों में, मुनीर ने अपनी सत्ता मज़बूत करने के लिए साम-दाम-दंड-भेद का हर हथकंडा अपनाया। जहां ज़रूरत हुई, वहां चालाकी से काम लिया। कई मौकों पर वो सरकार के लिए काम करते दिखे। इमरान ख़ान की पार्टी पीटीआई के नेतृत्व वाले राजनीतिक विपक्ष को बेअसर करने में सेना ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सरकार ने भी बदले में मुनीर को तोहफा दिया। न्यायिक स्वतंत्रता पर अंकुश लगा दिया गया है। विधायिका को भी एक तरह से सेना के अधीन कर दिया गया है। मुनीर को अपने कार्यकाल और विरासत की गारंटी दे दी गई है। ये सैन्य प्रतिष्ठान द्वारा किया गया एक ऐसा तख़्तापलट है, जो इस्लामाबाद की सड़कों पर टैंक तैनात किए बिना या कुख्यात 111वीं इन्फैंट्री ब्रिगेड को सक्रिय किए बिना ही हासिल किया गया है।

पिछले तीन साल में, पाकिस्तान में लोकतांत्रिक पतन अभूतपूर्व स्तर पर पहुंच गया है। विवादास्पद संवैधानिक संशोधनों के पारित होने, न्यायपालिका के कमज़ोर होने, मानवाधिकारों के व्यापक उल्लंघन, राष्ट्रीय चुनावों में धांधली, नागरिकों और राजनीतिक विपक्ष के ख़िलाफ़ अत्यधिक बल प्रयोग ने पाकिस्तान में लोकतंत्र को बहुत कमज़ोर कर दिया है। फिर भी, दिलचस्प बात ये है कि पाकिस्तान में लोकतंत्र के ख़ात्मे पर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया उदासीन रही है। पश्चिमी देश पाकिस्तान के मामले में हल्की-फुल्की कूटनीतिक फुसफुसाहट तक ही सीमित रह गए हैं। आमतौर पर ये पश्चिमी देश लोकतांत्रिक मानदंडों के समर्थन में मुखर रहते हैं। हैरानी की बात ये है कि पाकिस्तान में लोकतंत्र को कमज़ोर करने वाली सेना की स्वीकृति पश्चिमी देशों की राजधानियों में बढ़ रही है, खासकर वॉशिंगटन से तो पाकिस्तानी सेना और आसिम मुनीर को समर्थन मिल रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मुनीर की खुलकर प्रशंसा की है, उन्हें अपना 'पसंदीदा फील्ड मार्शल' बताया, और आधिकारिक तौर पर व्हाइट हाउस में उनका स्वागत किया। हालांकि, एक वास्तविकता ये भी रही है कि पाकिस्तान में सैन्य शासन को अमेरिका हमेशा से बढ़ावा देता रहा है। इसकी एक बड़ी वजह ये है कि सैन्य शासक से डील करने में अमेरिका को आसानी होती है। सैन्य शासकों से

**पाकिस्तान में सेना के सामने नागरिक संस्थाओं का सरेंडर हैरान नहीं करता, लेकिन एक व्यक्ति और एक संस्था में सत्ता का अति-केंद्रीकरण देश को दीर्घकालिक अस्थिरता की ओर धकेलता है। वैसे भी, पाकिस्तान के इतिहास में इस बात के पर्याप्त प्रमाण हैं कि जब संस्थागत संतुलन बिगड़ता है, तो आखिरकार किसी न किसी रूप में प्रतिक्रिया भड़कती है। फिर चाहे वो सेना के भीतर से हो, सड़कों पर हो, या अनपेक्षित संकटों के माध्यम से हो।**

अमेरिका अपने मनमुताबिक नीतियां बनवा लेता है। अमेरिका की इस स्वीकृति ने मुनीर के आत्मविश्वास को और मज़बूत किया है। माना जा रहा है कि अमेरिका द्वारा पीठ थपथपाने के बाद मुनीर साहसिक घरेलू कदम उठाएंगे। आस-पड़ोस में, विशेषकर भारत और अफगानिस्तान के प्रति, और ज़्यादा आक्रामक रुख़ अपनाएंगे।

मुनीर को मज़बूत करने वाला ये संविधान संशोधन पाकिस्तान की लोकतांत्रिक साख पर एक गंभीर चोट है। पाकिस्तान में मुनीर का गज़ब का दबदबा बना हुई है, क्योंकि वे अभी भी एपॉलेट पहने हुए हैं। एपॉलेट यानी सेना की वर्दी में लगी वो पट्टी, जिसमें रैंक दिखाने वाले स्टार लगे होते हैं। एक ज़माने में न्यायपालिका पाकिस्तान में प्रतिरोध का प्रतीक थी, उसे भी कानूनों में बदलाव के ज़रिए चुप करा दिया गया है। पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट के पास संविधान के मूल ढांचे के उल्लंघन की स्थिति में संविधान की अंतिम व्याख्याकार के रूप काम करने की ताक़त थी, लेकिन अब इस शक्ति को भी कमज़ोर कर दिया गया है। खास बात ये है कि, संविधान में संशोधन करने का संसद को पूर्ण अधिकार नहीं है। संसद ने सेना के दबाव में अपनी ईमानदारी से समझौता किया है, संसदीय सत्ता का मज़ाक उड़ाया है, जबकि मुख्यधारा के राजनीतिक दलों ने या तो स्वेच्छा से मौन स्वीकृति देकर या खुद को शक्तिहीन होने देकर अपरिपक्वता का सबूत दिया है। सत्ता प्रतिष्ठान ने अपनी विशेषाधिकार प्राप्त स्थिति को नियंत्रित और संरक्षित करने के लिए लोकतंत्र की बुनियाद को कमज़ोर किया है। उसने राजनीतिक और सैन्य अभिजात वर्ग के बीच सहजीवी संरक्षक-ग्राहक संबंध का इस्तेमाल, दबाव और प्रोत्साहन के ज़रिए किया है।

## पाकिस्तान में सेना के सामने सरेंडर क्यों करते हैं सियासतदान?

हालांकि, पाकिस्तान में सेना के सामने नागरिक संस्थाओं का सरेंडर हैरान नहीं करता, लेकिन एक व्यक्ति और एक संस्था में सत्ता का अति-केंद्रीकरण देश को दीर्घकालिक अस्थिरता की ओर धकेलता है। वैसे भी, पाकिस्तान के इतिहास में इस बात के पर्याप्त प्रमाण हैं कि जब संस्थागत संतुलन बिगड़ता है, तो आखिरकार किसी न किसी रूप में प्रतिक्रिया भड़कती है। फिर चाहे वो सेना के भीतर से हो, सड़कों पर हो, या अनपेक्षित संकटों के माध्यम से हो। हालांकि, पारदर्शिता और समावेशिता के अभाव वाले माहौल में मुनीर के प्रभुत्व को फिलहाल कोई चुनौती मिलती नहीं दिखती।

कुल मिलाकर, एक तरफ पाकिस्तान के आम लोग संविधान की खाल ओढ़े मार्शल लॉ में अपने लोकतांत्रिक अधिकारों में कटौती होते देख रहे हैं, वहीं पाकिस्तान मुस्लिम लीन ने सेना से समझौता कर लाहौर में मरियम नवाज़ और इस्लामाबाद में शाहबाज़ शरीफ के नेतृत्व वाली अपनी सरकारों की निरंतरता सुनिश्चित की है। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी ने भी भ्रष्टाचार के अनगिनत मामलों में घिरे आसिफ अली ज़रदारी के लिए छूट हासिल की है। हालांकि, इमरान खान पाकिस्तान की राजनीति में एक लोकप्रिय शख़्सियत बने हुए हैं, फिर भी उन्हें और पीटीआई को अभी भी बहुत कम रियायत मिली हुई है। मुनीर द्वारा खुद को सत्ता में लाना अब कोई नई बात नहीं है, लेकिन विश्लेषकों के मुताबिक, ऑपरेशन बनयान अल मरसूस के बाद मुनीर को आम जनता से जो सद्भावना और समर्थन मिला था, वो कम हो गया है। वैसे भी पाकिस्तानी जनता का एक बड़ा तबका असीम मुनीर से नाराज़ है, विशेषरूप से इमरान खान के समर्थकों को लगता है कि उनके नेता को सेना के कहने पर ही जेल भेजा गया।

भारतीय दृष्टिकोण से भी देखें तो, पाकिस्तानी राजनीति, विदेश नीति और रणनीतिक हितों पर सैन्य प्रतिष्ठान के मज़बूत होने से नुकसान ही होगा। मई 2025 में भारत-पाकिस्तान के बीच हुए संघर्ष के बाद से ही दोनों देशों के संबंध तनावपूर्ण बने हुए हैं। सत्ता पर सेना की पकड़ से तनाव और बढ़ेगा। वॉशिंगटन और रावलपिंडी के बीच बढ़ते सुधरते संबंधों के साथ ही, पाकिस्तानी सेना में राष्ट्रवाद का उत्साह चरम पर है। इसके अलावा, भारत भी पाकिस्तान के प्रति अपने सख्त रुख़ को बरकरार रखेगा। पाकिस्तान की सैन्य सत्ता के साथ भारत किसी तरह का संबंध नहीं रखना चाहता। 12 नवंबर 2025 को दिल्ली में हुए लाल किले पर हुए हालिया आतंकी हमले ने रिश्तों में अविश्वास को और गहरा कर दिया है। इस हमले को कश्मीरी कट्टरपंथी तत्वों ने अंजाम दिया, और भारत का मानना है कि इसमें पाकिस्तान का भी हाथ है। इस हमले के बाद पहले से ही तनावपूर्ण भारत-पाकिस्तान के संबंध और भी अस्थिर हो गए हैं। इनमें किसी तरह के सुधार की गुंजाइश नहीं दिखती।

**राजीव सिन्हा कैबिनेट सचिवालय में पूर्व विशेष सचिव और ऑब्जर्वर रिसर्च फ़ाउंडेशन में डिस्टिंग्विश्ड फेलो हैं। वे भारत के पड़ोसी देशों और सुरक्षा मुद्दों के एक्सपर्ट हैं। साथ ही सरल शर्मा पहले एनएससीएस में काम करते थे। वो अभी जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, दिल्ली में सिक्योरिटी स्टडीज़ में पीएचडी कर रहे हैं। हम यह आलेख ऑब्जर्वर रिसर्च फ़ाउंडेशन का आभार व्यक्त करते हुए पुनः प्रकाशित कर रहे हैं।**

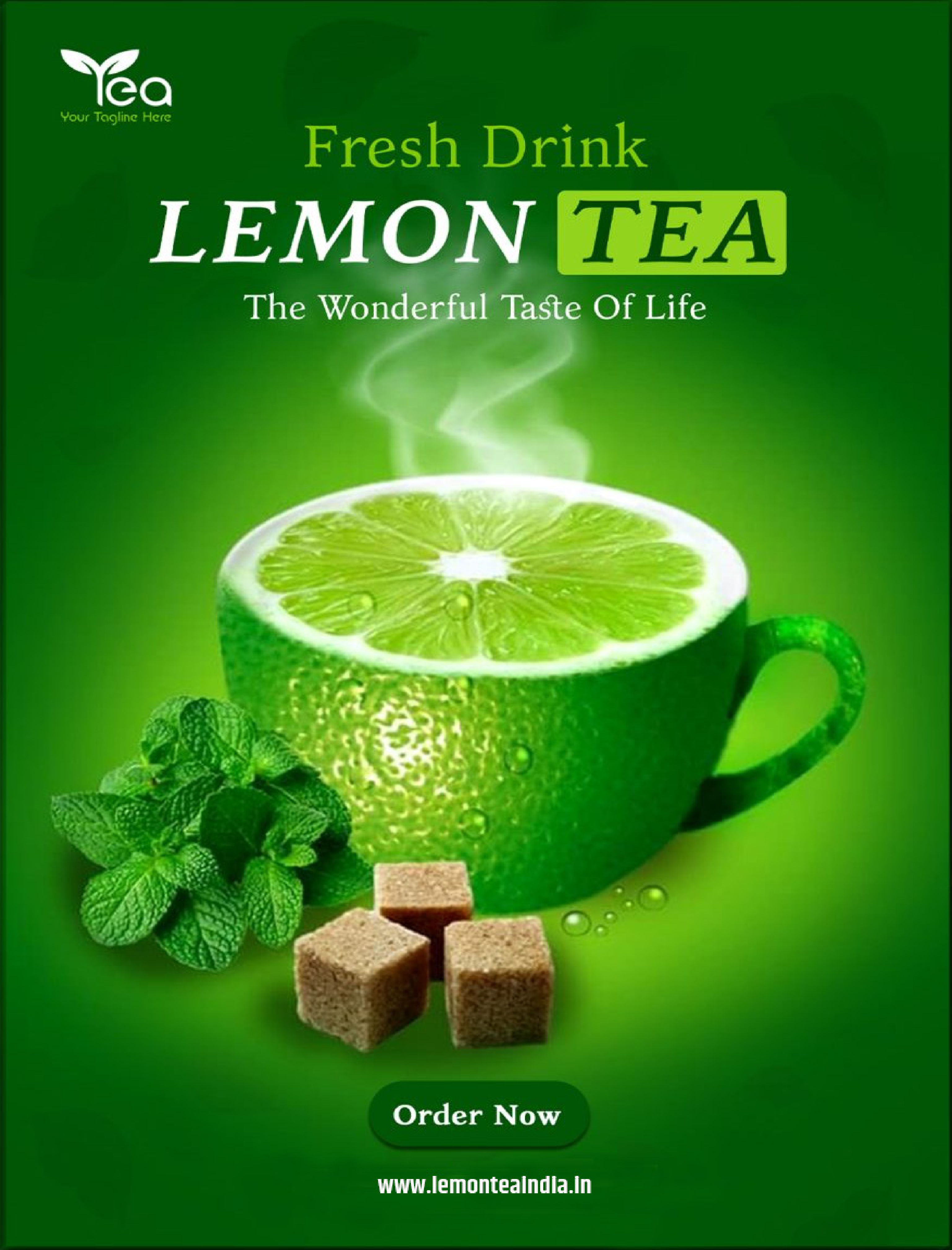

Your Tagline Here
Fresh Drink
LEMON TEA
The Wonderful Taste Of Life
Order Now
www.lemontealndia.in

# भारत-पाक-अफगानिस्तान

# उभरता त्रिकोण

संतु दास

भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के त्रिकोण में भू-राजनीतिक हलचलों की गति अप्रत्याशित रूप से तेज हो गई है। सीमा-बंदियों, एयर-स्ट्राइक और कूटनीतिक दौरों के बीच दक्षिण एशिया एक नए शक्ति-संतुलन की ओर बढ़ रहा है। बदलता यह त्रिकोण आने वाले महीनों में क्षेत्रीय स्थिरता की दिशा तय करेगा।

इतिहास के पन्नों में अक्सर ऐसे मोड़ आते हैं जब भू-राजनीतिक समीकरण अपनी ही धुरी पर पूरी तरह से घूम जाते हैं, और दक्षिण एशिया इस समय ठीक उसी निर्णायक और विडंबनापूर्ण क्षण का गवाह बन रहा है। नवंबर 2025 का यह महीना अंतरराष्ट्रीय कूटनीति में एक विरोधाभास की उत्कृष्ट मिसाल बनकर उभरा है। एक तरफ जहां पाकिस्तान और अफगानिस्तान की 2600 किलोमीटर लंबी डूरंड लाइन बारूद के धुएं, हवाई हमलों और मासूम बच्चों की चीखों से गूंज रही है, वहीं दूसरी तरफ नई दिल्ली के शांत और सुरक्षित गलियारों में तालिबान प्रशासन के उद्योग और वाणिज्य मंत्री अल्हाज नूरुद्दीन अजीजी का स्वागत किया जा रहा था। यह महज एक यात्रा नहीं थी, बल्कि यह रावलपिंडी के उन जनरलों के लिए एक कड़वा यथार्थ था, जिन्होंने 2021 में काबुल पर तालिबान के कब्जे को अपनी रणनीतिक जीत बताया था। आज, वही काबुल अपनी आर्थिक और सामरिक सांसें

बहाल करने के लिए इस्लामाबाद की ओर नहीं, बल्कि नई दिल्ली की ओर देख रहा है।

पाकिस्तान के लिए यह स्थिति किसी दुःस्वप्न से कम नहीं है। 2021 में जब अमेरिकी सेना अफगानिस्तान छोड़कर जा रही थी, तब तत्कालीन पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान ने इसे 'गुलामी की जंजीरें तोड़ने' वाला क्षण बताया था। पाकिस्तानी प्रतिष्ठान को लगा था कि उन्होंने अपनी पश्चिमी सीमा पर हमेशा के लिए 'स्ट्रैटेजिक डेप्थ' (रणनीतिक गहराई) हासिल कर ली है और अब अफगानिस्तान भारत के प्रभाव से मुक्त होकर पाकिस्तान का एक सेटेलाइट स्टेट बन जाएगा। लेकिन, चार साल बाद की तस्वीर बिल्कुल उलट है। आज पाकिस्तान अपनी उसी पश्चिमी सीमा पर अपने इतिहास के सबसे भीषण अस्तित्वगत संकट से जूझ रहा है। तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (टीटीपी) के हमले, जिन्हें इस्लामाबाद 'फितना अल-खवारिज' कहता है, पाकिस्तानी सुरक्षा बलों का खून बहा रहे हैं। पेशावर, इस्लामाबाद और दक्षिण वजीरिस्तान में हो रहे आत्मघाती हमले इस बात का प्रमाण हैं कि पाकिस्तान ने जिस सांप को अपनी आस्तीन में पाला था, वह अब उसी को डस रहा है।

इस खूनी संघर्ष के बीच, अफगानिस्तान का भारत की ओर मुड़ना एक सामान्य कूटनीतिक घटनाक्रम नहीं, बल्कि एक गहरा रणनीतिक बदलाव है। 19 नवंबर को जब मंत्री अजीजी पांच दिवसीय यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचे, तो यह संदेश स्पष्ट था कि काबुल अब पाकिस्तान के 'ब्लैकमेल' से थक चुका है। पाकिस्तान द्वारा बार-बार सीमा बंद करने, अफगान व्यापारियों के फलों और सब्जियों को ट्रकों में सड़ाने और राजनीतिक दबाव बनाने की रणनीति ने अफगान नेतृत्व को विकल्पों की तलाश करने पर मजबूर कर दिया है। और वह विकल्प भारत के रूप में सामने आया है। भारत ने भी पुरानी झिझक को त्यागते हुए यथार्थवादी कूटनीति का परिचय दिया है। विदेश मंत्रालय के संयुक्त सचिव आनंद प्रकाश द्वारा अजीजी का स्वागत करना और उन्हें इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर (आईआईटीएफ) में प्रमुखता देना, भारत की बदली हुई अफगान नीति का संकेत है। भारत ने अक्टूबर 2025 में काबुल में अपने मिशन को पूर्ण दूतावास का दर्जा देकर यह साफ कर दिया है कि वह वहां की सत्ता के स्वरूप

से परे जाकर, अफगान जनता और अपने रणनीतिक हितों के साथ जुड़ा रहेगा।

इस नए रिश्ते की धुरी 'कनेक्टिविटी' है, जो पाकिस्तान को दरकिनार करती है। अजीजी की यात्रा का मुख्य उद्देश्य उन वैकल्पिक मार्गों को सुदृढ़ करना था जो पाकिस्तान पर अफगानिस्तान की निर्भरता को खत्म कर सकें। भारत और अफगानिस्तान अब दो समर्पित कार्गो फ्लाइट रूट्स के जरिए हवाई व्यापार को पूरी क्षमता से शुरू करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। दिल्ली और अमृतसर के लिए काबुल से सीधी उड़ानें केवल व्यापारिक मार्ग नहीं हैं, बल्कि ये एक 'हवाई सेतु' हैं जो पाकिस्तान की भौगोलिक नाकेबंदी को तोड़ते हैं। सूखे मेवे, हींग, कालीन और कीमती पत्थर, जो पहले वाघा बॉर्डर पर पाकिस्तान की मनमानी का शिकार होते थे, अब सीधे भारतीय बाजारों में पहुंच रहे हैं। इसके साथ ही, चाबहार बंदरगाह का रणनीतिक महत्व फिर से केंद्र में आ गया है। यद्यपि अमेरिकी प्रतिबंधों के कारण ईरान के रास्ते व्यापार में चुनौतियां हैं, लेकिन काबुल और नई दिल्ली दोनों ही इस 'मल्टीमॉडल कॉरिडोर' को सक्रिय रखने के लिए प्रतिबद्ध हैं। यह पाकिस्तान के लिए एक बड़ा आर्थिक झटका है, क्योंकि अफगान नेतृत्व ने अपने व्यापारियों को स्पष्ट निर्देश दे दिया है कि वे पाकिस्तानी रास्तों का उपयोग कम करें और भारत तथा मध्य एशिया के विकल्पों पर ध्यान दें।

दूसरी ओर, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच तनाव 'हॉट वॉर' में तब्दील हो चुका है। खोस्त और कुनार प्रांतों में पाकिस्तानी वायुसेना द्वारा किए गए हवाई हमलों में महिलाओं और बच्चों की मौत ने अफगान जनमानस में पाकिस्तान के प्रति नफरत को चरम पर पहुंचा दिया है। तालिबान, जो कभी पाकिस्तान का सहयोगी माना जाता था, अब पाकिस्तान पर अपनी संप्रभुता के उल्लंघन का आरोप लगा रहा है। तालिबान के प्रवक्ता जबीउल्लाह मुजाहिद का बयान कि 'पाकिस्तानी हमलावर ताकतों ने नागरिकों को निशाना बनाया,' दोनों देशों के बीच की खाई को पाटने की किसी भी संभावना को खत्म करता दिखता है। दोहा और इस्तांबुल में कतर और तुर्की की मध्यस्थता में हुए संघर्ष विराम के प्रयास विफल हो चुके हैं क्योंकि बुनियादी मुद्दा अनसुलझा है। पाकिस्तान चाहता है कि तालिबान टीटीपी के खिलाफ कार्रवाई करे, जबकि तालिबान का कहना है कि टीटीपी पाकिस्तान की आंतरिक समस्या है और वह अपनी ही पश्तून बिरादरी के खिलाफ हथियार नहीं उठाएगा। यह गतिरोध एक स्ट्रक्चरल फॉल्ट लाइन बन चुका है जिसे भरना अब असंभव प्रतीत

**पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच तनाव 'हॉट वॉर' में तब्दील हो चुका है। खोस्त और कुनार प्रांतों में पाकिस्तानी वायुसेना द्वारा किए गए हवाई हमलों में महिलाओं और बच्चों की मौत ने अफगान जनमानस में पाकिस्तान के प्रति नफरत को चरम पर पहुंचा दिया है।**

होता है।

इस परिदृश्य में भारत की भूमिका एक 'स्टेबलाइजर' और भरोसेमंद साझेदार की है। भारत ने 2021 के बाद से अफगान जनता को 50,000 मीट्रिक टन गेहूं, दवाइयां और मानवीय सहायता भेजकर जो 'सॉफ्ट पावर' अर्जित की है, वह अब रणनीतिक लाभ में बदल रही है। अफगान मंत्री का भारतीय व्यापारियों को खनन, पनबिजली और कृषि में निवेश के लिए आमंत्रित करना और करों में छूट का प्रस्ताव देना यह बताता है कि तालिबान प्रशासन भी यह समझ चुका है कि बंदूकों से सत्ता पाई जा सकती है, लेकिन देश चलाने के लिए अर्थव्यवस्था की जरूरत होती है, और वह अर्थव्यवस्था पाकिस्तान के साथ जुड़कर डूब रही है, जबकि भारत के साथ जुड़कर तैर सकती है। कूटनीतिक दृष्टिकोण से देखें तो भारत ने अत्यंत चतुराई से 'वेट एंड वॉच' की नीति को 'एक्टिव एंगेजमेंट' में बदल दिया है। भारत ने तालिबान को औपचारिक मान्यता दिए बिना भी उनके साथ कार्यात्मक संबंध स्थापित कर लिए हैं। यह भारत की सुरक्षा के लिए अनिवार्य है। एक शत्रुतापूर्ण पाकिस्तान और एक अस्थिर अफगानिस्तान का संयोजन भारत के लिए खतरनाक हो सकता था। लेकिन पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की शत्रुता ने भारत को एक अवसर दिया है कि वह काबुल में अपने प्रभाव को पुनर्जीवित करे और यह सुनिश्चित करे कि अफगान धरती का इस्तेमाल भारत विरोधी गतिविधियों (विशेषकर कश्मीर में) के लिए न हो। पाकिस्तान का यह आरोप कि भारत टीटीपी और बलूच विद्रोहियों को समर्थन दे रहा है, उसकी अपनी बौखलाहट और विफलता का परिचायक है। सच्चाई यह है कि पाकिस्तान अपनी ही नीतियों के जाल में फंस गया है। उसने 'गुड तालिबान' और 'बैड तालिबान' के बीच जो फर्क किया था, वह अब मिट चुका है।

भविष्य की ओर देखें तो यह क्षेत्र एक बड़े भू-राजनीतिक पुनर्गठन की ओर बढ़ रहा है। यदि भारत-अफगानिस्तान हवाई गलियारा और चाबहार रूट सफल होता है, तो पाकिस्तान दक्षिण एशिया के व्यापारिक मानचित्र पर अप्रासंगिक हो जाएगा। अफगानिस्तान, जो 'एशिया का दिल' कहा जाता है, अगर पाकिस्तान के बजाय भारत और मध्य एशिया की ओर झुकता है, तो यह पाकिस्तान के 'कनेक्टिविटी हब' बनने के सपने का अंत होगा। अजीजी की भारत यात्रा के दौरान अफगान सिखों और हिंदुओं को वापस बुलाने और उन्हें सुरक्षा का आश्वासन देने की बात भी कही गई, जो भारत के सांस्कृतिक और मानवीय हितों के अनुरूप है।

निष्कर्षतः, दिल्ली में अफगान प्रतिनिधिमंडल की गर्मजोशी और डूरंड रेखा पर जलती आग इस बात का गवाह है कि 'ग्रेट गेम' का एक नया अध्याय लिखा जा रहा है। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को अपनी रणनीतिक गहराई बनाने की कोशिश की थी, लेकिन आज अफगानिस्तान पाकिस्तान के लिए एक रणनीतिक दलदल बन गया है। वहीं भारत, जिसने 2021 में काबुल से अपने राजनयिकों को वापस बुला लिया था, आज बिना एक भी गोली चलाए काबुल के दरबार में सबसे महत्वपूर्ण आर्थिक भागीदार बनकर उभरा है। यह भारतीय कूटनीति की धैर्यवान और दूरदर्शी विजय है। आने वाले दिनों में, जैसे-जैसे पाकिस्तान अपनी आंतरिक हिंसा और आर्थिक दिवालियेपन से जूझेगा, नई दिल्ली और काबुल के बीच का रिश्ता दक्षिण एशिया की सुरक्षा और स्थिरता का एक नया ध्रुव बनकर उभरेगा। यह स्पष्ट है कि जब काबुल को उम्मीद की तलाश होती है, तो वह अब रावलपिंडी के जनरल हेडक्वार्टर्स की ओर नहीं, बल्कि नई दिल्ली के रायसीना हिल्स की ओर देखता है।

माइकल फ्रोमैन

# वाशिंगटन-रियाद नई करवट

सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की वाशिंगटन की 'हाई-स्टेक' (अत्यधिक महत्वपूर्ण) यात्रा ने अमेरिका-सऊदी संबंधों की रूपरेखा बदल दी है। रक्षा समझौतों और एआई सहयोग से लेकर परमाणु ढांचे और खरबों डॉलर के निवेश के वादों तक, यह सप्ताह आठ दशक पहले यूएसएस क्विंसी पर एफडीआर और इब्न सऊद की ऐतिहासिक मुलाकात के बाद से इस साझेदारी का सबसे महत्वाकांक्षी 'रीबूट' (नया अध्याय) था।

सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान इस सप्ताह वाशिंगटन में थे ताकि हालिया स्मृति में अमेरिका-सऊदी रणनीतिक संबंधों के सबसे महत्वपूर्ण विस्तार को औपचारिक रूप दिया जा सके। ओवल ऑफिस में मीडिया की उल्लेखनीय उपस्थिति से लेकर पूरे सप्ताह व्यापार और निवेश मंचों पर देखे गए 'सौदा-बुखार' तक, इस यात्रा के बारे में कहने के लिए बहुत कुछ है।

मैंने सोचा कि मैं दोनों देशों के बीच चर्चा किए गए प्रमुख मुद्दों, संपन्न हुए समझौतों (और जो अभी अटके हुए हैं) पर ध्यान केंद्रित करूँ, और कुछ ऐतिहासिक संदर्भ प्रदान करने का प्रयास करूँ।

लगभग अस्सी साल पहले, द्वितीय विश्व युद्ध के अंतिम चरण में और याल्टा सम्मेलन के ठीक बाद, राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी. रूज़वेल्ट ने पहली बार सऊदी अरब के संस्थापक शासक, राजा अब्दुल अजीज अल सऊद के साथ एक बड़ा समझौता करने का प्रयास किया था। एफडीआर और इब्न सऊद (जैसा कि उन्हें जाना जाता था) अमेरिकी क्रूजर यूएसएस क्विंसी पर मिले थे, जो स्वेज नहर की ग्रेट बिटर लेक में खड़ा था। यह इब्न सऊद की समुद्र में पहली यात्रा थी और अपने नवजात राष्ट्र से बाहर निकलने का उनका पहला अनुभव था।

तब से बहुत कुछ बदल गया है—और बहुत कुछ नहीं बदला है।

रात्रिभोज निश्चित रूप से अलग था। एफडीआर के सऊदी दूत विलियम ए. एड्डी के वृत्तांत के अनुसार, इब्न सऊद को 'अपने देश में प्रशीतन का कोई अनुभव नहीं था' और वे इस्लामी खान-पान के नियमों का सख्ती से पालन करते थे। इसलिए उन्होंने क्विंसी के कमोडोर से आग्रह किया कि—नौसेना के नियमों के खिलाफ—उनकी व्यक्तिगत रेवड़ से सात 'सबसे अच्छी और सबसे मोटी भेड़ें' जहाज पर लाई जाएं और उनके दल और क्रू के आनंद के लिए प्रतिदिन हलाल की जाएं। यह राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प द्वारा व्हाइट हाउस के ईस्ट रूम में दिए गए उस भव्य रात्रिभोज से बहुत अलग था, जिसमें एलन मस्क और क्रिस्टियानो रोनाल्डो शामिल थे।

हालाँकि, मुझे क्विंसी के डेक पर लगे तंबू में हुई बातचीत के बारे में सबसे आश्चर्यजनक बात यह लगती है कि मुख्य एजेंडा इस सप्ताह व्हाइट हाउस में चर्चा किए गए एजेंडे के लगभग समान था।

क्विंसी पर स्वेज से गुजरते हुए, एफडीआर ने इब्न सऊद के सामने तीन प्रस्ताव रखेः यहूदी लोगों को पवित्र भूमि में एक राज्य बनाने की अनुमति दें; सऊदी तेल को स्वतंत्र रूप से बहने दें, जिसमें—और विशेष रूप से—संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए शामिल हो; और अंत में, संयुक्त राज्य अमेरिका को किंगडम (सऊदी अरब) के प्रमुख रणनीतिक भागीदार के रूप में अपनाएं। इब्न सऊद दूसरे और तीसरे बिंदुओं पर मोटे तौर पर सहमत हुए, लेकिन इज़राइल के मुद्दे पर असहमत थे। उन्होंने सुझाव दिया कि चूंकि जर्मनी द्वितीय विश्व युद्ध हार गया था, इसलिए यहूदी शरणार्थियों को हर्जाने के रूप में बवेरिया को अपनी मातृभूमि के रूप में प्राप्त करना चाहिए।

इस सप्ताह, ट्रम्प और एमबीएस ने अमेरिका और सऊदी अरब को रणनीतिक साझेदारी के लिए एफडीआर के विजन को साकार करने के पहले से कहीं अधिक करीब ला दिया है। ट्रम्प को तेल उत्पादन पर भी अस्पष्ट आश्वासन मिले। लेकिन, हालांकि एमबीएस ने भविष्य में अब्राहम समझौते में शामिल होने में सामान्य रुचि व्यक्त की, लेकिन दो-राज्य समाधान की ओर स्पष्ट रास्ता न होने के कारण इज़राइल के साथ सामान्यीकरण 'अधूरा काम' बना हुआ है।

इसके बावजूद, ट्रम्प ने सऊदी अरब को 'प्रमुख गैर-नाटो सहयोगी' का दर्जा दिया, और दोनों पक्षों ने एक नए रणनीतिक रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए। यह समझौता अमेरिकी सेना की पहुंच का विस्तार करता है, किंगडम की रक्षा से जुड़ी अमेरिकी लागतों को साझा करने की सऊदी प्रतिबद्धताओं को औपचारिक रूप देता है, और भविष्य की एफ-35 डिलीवरी और लगभग तीन सौ अमेरिकी टैंकों सहित प्रमुख हथियारों के हस्तांतरण का रास्ता साफ करता है। अमेरिका और सऊदी अरब ने एक नागरिक परमाणु सहयोग घोषणा पर भी हस्ताक्षर किए, जिससे अमेरिका—और अमेरिकी कंपनियां—किंगडम के बढ़ते नागरिक परमाणु कार्यक्रम के लिए रियाद की पसंदीदा भागीदार बन गईं।

अमेरिकी आपूर्ति-श्रृंखला परियोजनाओं में सऊदी पूंजी लगाने के लिए एक महत्वपूर्ण खनिज ढांचा तैयार किया गया, और एक ऐतिहासिक एआई समझौता ज्ञापन ने किंगडम को उन्नत अमेरिकी सिस्टम और हार्डवेयर—जिसमें एनवीडिया और एएमडी जैसी कंपनियों के अत्याधुनिक चिप्स शामिल हैं—तक संरचित पहुंच प्रदान की, जबकि चिंता वाले देशों (जैसे, चीन) को अमेरिकी तकनीक के डायवर्जन या रिसाव को रोकने के लिए सुरक्षा उपाय लागू किए गए। एआई बुनियादी ढांचे के तेजी से निर्माण के साथ यह व्यवस्था अमेरिकी कंपनियों को किंगडम के मॉडल-प्रशिक्षण और उच्च-प्रदर्शन कंप्यूटिंग पारिस्थितिकी तंत्र में केंद्रीय भूमिका निभाने की स्थिति में रखती है। बदले में, एमबीएस ने संयुक्त राज्य अमेरिका में निवेश करने की सऊदी अरब की प्रतिबद्धता को मई में किए गए 600 बिलियन डॉलर के वादे से बढ़ाकर लगभग 1 ट्रिलियन डॉलर कर दिया, हालाँकि इस वादे की प्रकृति, समय और व्यवहार्यता अस्पष्ट रही।

सीधे शब्दों में कहें तो, सऊदियों को वह सब कुछ मिल गया जो वे चाहते थे, सिवाय अमेरिका के साथ आपसी रक्षा संधि के—जो हर तरह से सऊदी-इज़राइल सामान्यीकरण पर निर्भर है और जिसके लिए सीनेट के अनुसमर्थन की आवश्यकता होगी। द्विपक्षीय

संबंध 2021 के अपने सबसे निचले स्तर से स्थिर हो गए हैं, जब अमेरिकी खुफिया समुदाय द्वारा वाशिंगटन पोस्ट के स्तंभकार जमाल खशोग्गी की नृशंस हत्या में क्राउन प्रिंस को फंसाए जाने के बाद राष्ट्रपति जो बिडेन ने एमबीएस को बहिष्कृत घोषित कर दिया था।

क्या अमेरिका को वह मिला जो वह चाहता था? कमोबेश, हाँ। किंगडम ने सैन्य और तकनीकी क्षेत्रों में अपने रणनीतिक भागीदार के रूप में अमेरिका पर भरोसा दोगुना कर दिया है। सऊदियों ने अमेरिका में पर्याप्त पूंजी निवेश करने का वादा किया है। और इज़राइल के साथ संबंधों को सामान्य करने का मुद्दा मेज पर बना हुआ है, भले ही निकट भविष्य में इसकी संभावना कम हो। लेकिन एक बात स्पष्ट है: सौदे की घोषणा करना उसे पूरी तरह से लागू करने की तुलना में आसान है। आइए हम प्रत्येक का उसकी अपनी खूबियों पर आकलन करें।

हथियार सौदे के पूरी तरह लागू होने की संभावना पर सवालिया निशान है। परंपरागत रूप से, सऊदी अरब (और अन्य अरब देशों) को अमेरिकी हथियारों की बिक्री इज़राइल की 'गुणात्मक सैन्य बढ़त' द्वारा बाधित रही है—यह एक वास्तविक अमेरिकी नीति है जिसे बाद में 2008 में कानून का रूप दिया गया, जो यह निर्धारित करता है कि अमेरिका को यह सुनिश्चित करना होगा कि इज़राइल मध्य पूर्व में अपने पड़ोसियों की तुलना में श्रेष्ठ सैन्य क्षमता बनाए रखे। जब ट्रम्प से सीधे क्यूएमई के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने कहा: 'जहां तक मेरा सवाल है, मुझे लगता है कि वे दोनों [इज़राइल और सऊदी अरब] उस स्तर पर हैं जहां उन्हें सर्वोत्तम मिलना चाहिए।' क्या अमेरिका अंततः सऊदी अरब को अत्याधुनिक एफ-35 बेचेगा? और, यदि नहीं, तो क्या बिक्री वास्तव में होगी? चाहे ऐसा हो या न हो (यूएई के साथ इसी तरह का एक सौदा आंशिक रूप से एफ-35 के निर्यात पर अमेरिकी प्रतिबंधों के कारण विफल हो गया था), वास्तविकता यह है कि सऊदियों की असली जीत पहले ही हो चुकी है: एक मौजूदा अमेरिकी राष्ट्रपति की यह सार्वजनिक घोषणा कि वे एफ-35 खरीद सकते हैं, अपने आप में प्रतिष्ठा की बात है। ट्रम्प सऊदी अरब को अमेरिका के रणनीतिक भागीदार के रूप में इज़राइल के बराबर रखते हुए प्रतीत होते हैं।

एआई सौदा इन सबमें सबसे अधिक व्यावहारिक हो सकता है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि क्या अमेरिका सऊदियों पर भरोसा करता है कि वे अमेरिकी उन्नत तकनीक को अपने प्रतिस्पर्धी और संभावित विरोधी के हाथों में जाने से बचाएंगे। अमेरिकी निर्यात नियंत्रणों से बचने की फिराक में बैठी चीनी कंपनियों के लिए एक माध्यम बनकर सऊदियों का बहुत कुछ खोने का जोखिम है। आखिरकार, किंगडम का पूरा आर्थिक परिवर्तन पश्चिमी तकनीक, पूंजी और प्रतिभा तक निर्बाध पहुंच पर निर्भर है। हालांकि कुछ जोखिम है कि सऊदी विकसित किए गए एआई अनुप्रयोगों का दुरुपयोग कर

**जैसे-जैसे वॉशिंगटन रूसी तेल पर अपने प्रतिबंध कड़े कर रहा है, भारत की आर्थिक संतुलन-रेखा और नाज़ुक होती जा रही है। अमेरिका की रिझाने और दबाव डालने की दोहरी नीति नई दिल्ली की इस क्षमता की परीक्षा ले रही है कि वह अपनी रणनीतिक स्वायत्तता से समझौता किए बिना अपने ऊर्जा हितों की रक्षा कैसे करे।**

सकते हैं, लेकिन राष्ट्रपति इस समझौते के साथ सहज दिखाई देते हैं। यह समझौता अमेरिकी बाजार हिस्सेदारी को अधिकतम करने और अमेरिकी-डिज़ाइन किए गए एआई सिस्टम के प्रसार की ओर अमेरिका की अंतरराष्ट्रीय एआई नीति में व्यापक रणनीतिक बदलाव के साथ भी पूरी तरह फिट बैठता है। निष्पादन का असली जोखिम यह है कि क्या किंगडम हजारों (या उससे अधिक) अत्याधुनिक जीपीयू को उत्पादक रूप से तैनात करने के लिए आवश्यक भौतिक बुनियादी ढांचे, कार्यबल और घरेलू एप्लिकेशन पारिस्थितिकी तंत्र को खड़ा कर सकता है या नहीं।

अंत में, निवेश की प्रतिज्ञा इस सप्ताह के समझौतों में सबसे कम विश्वसनीय है। इसका गणित बैठता नहीं है। बुधवार को, मुझे माइकल रैटनी से बात करने का मौका मिला, जो सीएफआर सदस्य हैं और 2023 से 2025 तक सऊदी अरब में राजदूत के रूप में कार्य कर चुके हैं। उन्होंने अभी एमबीएस की प्राथमिकताओं के नए सेट पर न्यूयॉर्क टाइम्स के लिए एक लेख प्रकाशित किया है। हमारी बातचीत में, उन्होंने एक स्पष्ट लेकिन अक्सर नजरअंदाज की जाने वाली बात की ओर इशारा किया: दोनों पक्ष प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को आकर्षित करने पर बहुत अधिक ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, न कि इसे बांटने पर।

सऊदी पक्ष की बात करें तो, विभिन्न सरकारी निवेश माध्यमों द्वारा वर्षों तक भारी मात्रा में विदेशी निवेश करने के बाद, एमबीएस अब अपने देश के संसाधनों को घरेलू स्तर पर केंद्रित करने और विजन 2030 (उनकी अर्थव्यवस्था के रणनीतिक परिवर्तन) को वित्तपोषित करने के लिए पश्चिमी पूंजी को आकर्षित करने के लिए दृढ़ हैं। और जबकि किंगडम तेल संपदा में समृद्ध है (प्रति दिन लगभग $500 मिलियन पंप करता है), तेल की कीमतें गिर रही हैं और उत्पादन ओपेक द्वारा सहमत आउटपुट कैप से बाधित है। किंगडम का मुख्य संप्रभु धन कोष, पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड, के पास भी नकदी की कमी है, क्योंकि इसने इसे विदेशों में निवेश किया है, और हाल ही में, निओम और अन्य खराब किस्मत वाली घरेलू मेगा-परियोजनाओं में दसियों अरबों डॉलर डाले हैं। कुल मिलाकर, यह संभावना नहीं है कि किंगडम ट्रम्प के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को पूरा कर पाएगा और अपने घरेलू आर्थिक एजेंडे से समझौता किए बिना अगले कई वर्षों तक हर साल सीधे संयुक्त राज्य अमेरिका में सैकड़ों अरबों डॉलर निवेश कर पाएगा—ऐसा कुछ जिसे करने के लिए एमबीएस न तो इच्छुक हैं और न ही राजनीतिक रूप से सक्षम। कहीं अधिक संभावित परिणाम 'रचनात्मक लेखांकन', पुराने वादों को नया रूप देना, या हेडलाइन नंबर के मुकाबले कमी हो सकता है जो शायद राष्ट्रपति ट्रम्प के पद छोड़ने के बाद ही स्पष्ट हो।

इनमें से कुछ सौदे एक साल से अधिक समय से चल रहे थे, जब बिडेन प्रशासन के उत्तरार्ध में अमेरिका-सऊदी संबंध स्थिर हो गए थे। फिर भी, स्पष्ट रूप से राष्ट्रपति ट्रम्प और क्राउन प्रिंस के बीच व्यक्तिगत संबंधों ने इस सप्ताह उनकी प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस रणनीतिक संबंध में स्थायी स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए, सऊदी अरब को यह सलाह दी जाएगी कि वह अमेरिका-सऊदी संबंधों को पक्षपातपूर्ण रेखाओं के साथ परिभाषित होने से रोकने के लिए काम करे और रिपब्लिकन के साथ-साथ डेमोक्रेट के बीच भी मजबूत समर्थन बनाए। अन्यथा, जिसे आज रणनीतिक माना जा रहा है, उसे बाद में केवल लेन-देन के रूप में देखा जा सकता है।

**(माइकल फ्रोमैन काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस के अध्यक्ष हैं। वे पहले मास्टरकार्ड में वाइस चेयरमैन और प्रेसिडेंट (स्ट्रैटेजिक ग्रोथ), मास्टरकार्ड सेंटर फॉर इनक्लूसिव ग्रोथ के चेयरमैन और में प्रतिष्ठित फेलो के रूप में कार्य कर चुके हैं।)**

# नया तेल, नया खेल

जलवायु परिवर्तन की बहस अब कार्बन से आगे बढ़कर 'दुर्लभ खनिजों' तक पहुँच गई है। लिथियम और कोबाल्ट भविष्य की ऊर्जा की चाबी हैं। कॉप-30 के मंच पर भारत ने साफ कर दिया है कि वह इस 'नए खेल' में महज खरीदार नहीं, बल्कि बाजीगर बनकर उभरेगा। अब लड़ाई 'काले सोने' की नहीं, भविष्य की ऊर्जा की है।

मनीष वैध

बेलेम, ब्राजील में चल रहे कॉप-30 के मंच पर जब दुनिया भर के नीति-निर्माता इस गुणा-भाग में उलझे थे कि ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए किसकी जेब से कितना पैसा निकलेगा, तब भारत ने एक बेबाक हुंकार भरी। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने स्पष्ट शब्दों में विकसित देशों को आईना दिखाते हुए कहा— 'वादे पूरे करने का वक्त आ गया है।' उन्होंने दो टूक कहा कि विकसित देशों को अपने 'नेट ज़ीरो' लक्ष्यों को मौजूदा समय-सीमा से बहुत पहले हासिल करना होगा और जलवायु वित्तपोषण के नाम पर अरबों नहीं, बल्कि खरबों डॉलर की मदद देनी होगी।

यही नहीं, भारत ने साफ कर दिया कि जलवायु तकनीक सस्ती और सुलभ होनी चाहिए, जिस पर बौद्धिक संपदा की बेड़ियाँ न जकड़ी हों। भारत की यह आक्रामकता अकारण नहीं है। नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में भारत ने 500 गीगावाट की स्थापित बिजली क्षमता को पार कर लिया है, जिसमें आधे से अधिक हिस्सा स्वच्छ ऊर्जा का है।

हालांकि, जलवायु परिवर्तन की यह वैश्विक चर्चा अब केवल कार्बन उत्सर्जन और वित्त पोषण तक सीमित नहीं रही है। अब सबका ध्यान उस अदृश्य मगर निर्णायक पहलू की ओर मुड़ गया है जो इस स्वच्छ ऊर्जा क्रांति की धड़कन है—वे खनिज, जिनसे भविष्य की ऊर्जा चलनी है। भारत के लिए, जो अभी भी लिथियम, कोबाल्ट, निकल और 'रेयर अर्थ एलिमेंट्स' के लिए आयात पर भारी निर्भरता रखता है, यह एक रणनीतिक और निर्णायक मोड़ है।

इसी साल, यानी 2025 में, नई दिल्ली ने 'राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन' का आगाज किया है। इसका तर्क सीधा और सरल हैः अगर आपके पास बैटरी, सोलर पैनल, विंड टर्बाइन और हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर बनाने के बुनियादी 'ब्लॉक' ही नहीं होंगे, तो भारत की कम कार्बन उत्सर्जन वाली महत्वाकांक्षाएं आपूर्ति की असुरक्षा में दम तोड़ देंगी। दांव बहुत बड़ा है। विश्व व्यापार संगठन के आंकड़े बताते हैं कि ऊर्जा से जुड़े महत्वपूर्ण खनिजों का व्यापार जो वर्ष 2000 में 53 अरब डॉलर था, वह 2022

में बढ़कर 378 अरब डॉलर हो गया है।

विडंबना यह है कि भारत अभी भी कम से कम दस आवश्यक खनिजों के लिए शत-प्रतिशत आयात पर निर्भर है, जिनमें लिथियम और कोबाल्ट जैसे महत्वपूर्ण तत्व शामिल हैं। इस परिदृश्य में, कॉप-30 ने भारत को एक कूटनीतिक अवसर प्रदान किया है कि वह घरेलू औद्योगीकरण को खनिजों की बहुपक्षीय आपूर्ति श्रृंखला से जोड़े, और केवल एक खरीदार की भूमिका से ऊपर उठकर वैश्विक नियमों का सह-निर्माता बने।

घरेलू स्तर पर भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने अपने कदम तेज कर दिए हैं और महत्वपूर्ण खनिजों की खोज परियोजनाओं की संख्या 118 से बढ़ाकर 196 कर दी है। लेकिन असली खेल सीमाओं के बाहर हो रहा है। भारत अब अपने पारंपरिक आपूर्तिकर्ताओं से आगे बढ़कर ब्राजील, अर्जेंटीना, नामीबिया, जिम्बाब्वे और ऑस्ट्रेलिया के साथ नए रिश्ते जोड़ रहा है। 'ऑल्टमिन-ब्राजील' परियोजना इसका एक सटीक उदाहरण है, जो स्पोड्यूमीन अयस्क को रिफाइन कर सालाना 32,000 टन लिथियम कार्बोनेट में बदलेगी। यह 'मिनरल्स सिक्योरिटी पार्टनरशिप' के तहत सूचीबद्ध होने वाला पहला भारतीय प्रोजेक्ट है, जो दर्शाता है कि भारत अब केवल 'कमोडिटी' खरीदने में नहीं, बल्कि साझा औद्योगिक क्षमता विकसित करने में विश्वास रखता है।

काउंसिल ऑन एनर्जी, एनवायरनमेंट एंड वॉटर के विश्लेषकों का मानना है कि चूंकि भारत के पास प्रमुख लिथियम-आयन बैटरी खनिजों के भंडार सीमित हैं, इसलिए स्थानीय प्रसंस्करण क्षमता का निर्माण करना समय की मांग है। नीतिगत स्तर पर, भारत सरकार 1,200 अन्वेषण परियोजनाओं को फास्ट-ट्रैक करने और 'ग्रीन मैन्युफैक्चरिंग' के लिए पीएलआई योजनाओं से जुड़े खनिज-प्रसंस्करण पार्क बनाने की दिशा में काम कर रही है। जलवायु नीति का यह 'खनिज आयाम' अब आर्थिक प्रतिस्पर्धा की कसौटी बन रहा है। जैसे-जैसे स्वच्छ ऊर्जा की ओर संक्रमण तेज हो रहा है, देश लिथियम, कोबाल्ट और निकल के भंडारों को सुरक्षित करने की होड़ में हैं। विश्लेषक चेतावनी दे रहे हैं कि ये खनिज 'नया तेल' बन सकते हैं। इसलिए नहीं कि इनके दाम अस्थिर हैं, बल्कि इसलिए कि अगर इनकी सप्लाई चेन पर पकड़ नहीं बनाई गई, तो दुनिया में फिर से वैसी ही भू-राजनीतिक असमानता पैदा हो सकती है।

भू-आर्थिक दृष्टि से देखें तो भारत के पास बाजार का आकार और सही समय, दोनों का संयोजन है। 2030 तक ऊर्जा की मांग में सालाना 3% की वृद्धि और 500 गीगावाट गैर-जीवाश्म क्षमता का लक्ष्य—इन दोनों को साधने के लिए खनिजों की आपूर्ति अनिवार्य है। चीन अभी भी इस बाजार का बेताज बादशाह है, जिसके पास दुर्लभ खनिजों की प्रोसेसिंग का 90 प्रतिशत हिस्सा है। ऐसे में भारत द्वारा ब्राजील, अफ्रीका और इंडो-पैसिफिक में पैर पसारना लंबी अवधि की 'डी-रिस्किंग' रणनीति है।

आंकड़े बताते हैं कि भारत की खनिज कूटनीति अब धीमी गति से नहीं चल सकती। 2025 से 2030 के बीच, देश में लिथियम और कोबाल्ट की मांग दो सौ गुना से अधिक बढ़ने वाली है, जबकि निकल का उपयोग लगभग छह गुना हो जाएगा। यह रुझान खनिजों को उसी स्थान पर खड़ा कर रहा है जहाँ कभी तेल हुआ करता था—शक्ति की एक रणनीतिक मुद्रा।

ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका जैसे ग्लोबल साउथ के अन्य देशों से सीखते हुए, भारत को भी केवल कच्चे माल के निर्यात से आगे बढ़कर स्थानीय स्तर पर मूल्य संवर्धन पर जोर देना होगा। हालांकि, संरचनात्मक बाधाएं अभी भी मौजूद हैं। भारत की घरेलू रिफाइनिंग क्षमता सीमित है, और तकनीकी साझेदारी को तेज करने की जरूरत है। इंस्टीट्यूट फॉर एनर्जी इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंशियल एनालिसिस का सुझाव है कि 'मिड-स्ट्रीम' निर्भरता से बचने के लिए भारत को संयुक्त अनुसंधान और तकनीकी लाइसेंस हासिल करने होंगे।

साथ ही, आगामी 'राष्ट्रीय खनिज नीति 2025' में यह सुनिश्चित करना होगा कि स्वायत्तता की यह दौड़ पर्यावरण की कीमत पर न हो। कॉप-30 में 'ग्लोबल मिनरल्स इक्विटी' की वकालत करते हुए पारदर्शिता और श्रम अधिकारों को शामिल करना भारत को नैतिक बढ़त दिला सकता है।

अंततः, कॉप-30 में भारत की सक्रियता केवल संसाधन जुटाने के लिए नहीं है, बल्कि यह मूल्य-श्रृंखलाओं को फिर से परिभाषित करने की कवायद है। भारत अब एक मूक खरीदार या 'नीति प्रतिभागी' बनकर नहीं रहना चाहता, बल्कि वह तकनीकी साझेदारी और निवेश के माध्यम से उभरती हुई वैश्विक खनिज व्यवस्था का 'नियम-निर्माता' और वास्तुकार बनना चाहता है। ऊर्जा के नए विश्व क्रम में भारत की यह करवट अपरिहार्य भी है और आवश्यक भी।

**मनीष वैद, ऑब्जर्वर रिसर्च फ़ाउंडेशन में जूनियर फ़ेलो हैं, जिनकी शोध रुचियां रणनीतिक ऊर्जा विषयों और हरित (ग्रीन) ऊर्जा से संबंधित हैं। उनका यह आलेख, जो मूलतः RT में प्रकाशित हुआ था, साभार प्रस्तुत है।**

A platform dedicated to geopolitical and global affairs, as well as analysis related to India and Indianness

CULT CURRENT

WE MAKE VIEWS

Join the YouTube channel ›

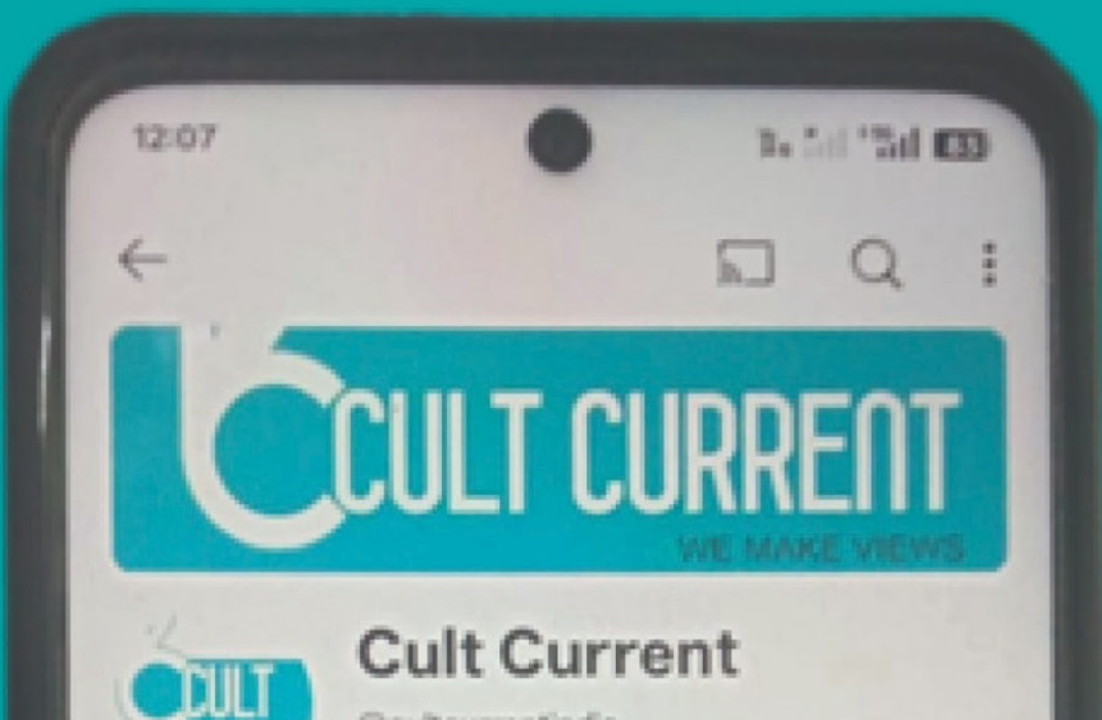

सेर्गेई स्त्रोकिन

# रूसी दांव, अमेरिकी चाल भारत से दोस्ती की 'अग्निपरीक्षा'

स र्दियों की दस्तक के साथ ही मॉस्को की फिजाओं में एक अलग तरह की कूटनीतिक सरगर्मी महसूस की जा रही है। 17 नवंबर को जब रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने अपने भारतीय समकक्ष डॉ. एस. जयशंकर का स्वागत किया, तो वह मुलाकात महज एक औपचारिक रस्म अदायगी नहीं थी, और न ही यह शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) की बैठक के हाशिए पर हुई कोई सामान्य बातचीत थी। कूटनीतिक गलियारों में इस बात की सुगबुगाहट बहुत स्पष्ट है कि दोनों दिग्गज दरअसल उस विशाल शतरंज की बिसात बिछा रहे थे, जिस पर अगले महीने दुनिया के दो सबसे ताकतवर नेताओं में से एक, व्लादिमीर पुतिन और भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात होनी है। यह बैठक दिसंबर के पहले हफ्ते में नई दिल्ली में होने वाले उस महा-आयोजन की प्रस्तावना है, जिस पर न केवल एशिया, बल्कि पूरी पश्चिमी दुनिया की बाज जैसी निगाहें टिकी हुई हैं।

शीत हवाओं के साथ सत्ता की साँसें भी ठंडी-गरम चलने लगी हैं। मॉस्को और दिल्ली की मेजों पर शतरंज सजा है, मोहरें खामोश हैं मगर कदम इशारे दे रहे हैं। दिसंबर की इस मुलाकात में तय होना है—भारत पुरानी दोस्ती निभाएगा या अमेरिकी दबाव के आगे झुकेगा?

यह दौर सामान्य नहीं है। यह वह दौर है जब भू-राजनीतिक समीकरण हर रोज अपनी केंचुली बदल रहे हैं। एक तरफ मॉस्को है, जो पश्चिमी प्रतिबंधों के अभूतपूर्व किलेबंदी को भेदकर अपने पुराने मित्र के साथ रिश्तों को नया आयाम देना चाहता है, और दूसरी तरफ वाशिंगटन डीसी में सत्ता परिवर्तन के बाद एक नया और आक्रामक अमेरिका खड़ा है। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का आगामी भारत दौरा कई मायनों में ऐतिहासिक और संवेदनशील है। यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद से यह पहला मौका होगा जब पुतिन भारतीय सरजमीं पर कदम रखेंगे। यह यात्रा एक ऐसे नाजुक मोड़ पर हो रही है, जब सात समंदर पार व्हाइट हाउस में बैठे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत की 'रणनीतिक स्वायत्तता' को अपनी शर्तों पर तोड़ने के लिए आमादा नजर आ रहे हैं। बाहरी दबावों के इस बवंडर के बीच, मॉस्को और नई दिल्ली का यह मिलन केवल द्विपक्षीय वार्ता नहीं, बल्कि एक भू-राजनीतिक घोषणापत्र है कि पुरानी दोस्ती को अमेरिका की दखलअंदाजी या धमकियों से डिगाया नहीं जा सकता।

दिसंबर के इस कूटनीतिक महाकुंभ की पटकथा 7 नवंबर को ही लिखी जाने लगी थी,

जब जयशंकर ने नई दिल्ली में रूस के उप-विदेश मंत्री आंद्रेई रुडेनको के साथ मैराथन बैठक की थी। कूटनीति में संकेतों का बड़ा महत्व होता है। उस बैठक के बाद रूसी विदेश मंत्रालय द्वारा जारी बयान और बाद में क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव की टिप्पणी कि 'हम पुतिन की यात्रा की सक्रिय तैयारी कर रहे हैं', इस बात का परिचायक है कि मॉस्को इस यात्रा को लेकर किस हद तक गंभीर है। पेस्कोव का यह रहस्यमयी अंदाज में कहना कि 'समझौतों की घोषणा उचित समय पर की जाएगी', यह इशारा करता है कि पर्दे के पीछे कुछ बड़े समझौतों की इबारत लिखी जा चुकी है, जो दुनिया को चौंका सकती है।

आगामी 4 और 5 दिसंबर 2025 को नई दिल्ली में होने वाला 'रूस-इंडिया फोरम' और 23वाँ शिखर सम्मेलन केवल हाथ मिलाने और फोटो खिंचवाने का मंच नहीं होगा। इसके एजेंडे की गहराई को समझना आवश्यक है। रॉसकांग्रेस और रूस के उद्योग एवं वाणिज्य उपमंत्री अलेक्सी ग्रूज़देव के बयानों का विश्लेषण करें तो साफ पता चलता है कि रूस अब केवल हथियारों और कच्चे तेल का विक्रेता बनकर नहीं रहना चाहता। पश्चिमी बाजारों के दरवाजे बंद होने के बाद, रूस भारत को एक दीर्घकालिक आर्थिक साझेदार के रूप में देख रहा है। वे भारतीय बाज़ार में अपनी भारी मशीनरी, तकनीकी उत्पाद और यहाँ तक कि कृषि उत्पादों को उतारना चाहते हैं। बदले में, वे भारत से केवल पैसा नहीं, बल्कि डिजिटल सेवाएँ, फार्मास्युटिकल्स और सबसे महत्वपूर्ण—मानव संसाधन चाहते हैं।

इस शिखर सम्मेलन का सबसे दिलचस्प और दूरगामी पहलू 'श्रम गतिशीलता समझौता' (लेबर मोबिलिटी एग्रीमेंट) हो सकता है। रूस जनसांख्यिकीय संकट से जूझ रहा है और उसे अपने उद्योगों को चलाने के लिए कामगारों की सख्त जरूरत है, जबकि भारत के पास विश्व का सबसे बड़ा युवा कार्यबल है। यदि यह समझौता परवान चढ़ता है, तो आने वाले वर्षों में बड़ी संख्या में भारतीय पेशेवर और श्रमिक रूस के निर्माण, ऊर्जा और सेवा क्षेत्रों में अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे। यह संबंध को खरीदार-विक्रेता से बदलकर एक गहरे सामाजिक-आर्थिक एकीकरण की ओर ले जाने वाला कदम होगा।

हालाँकि, भारत और रूस के इस गुलाबी भविष्य की तस्वीर में अमेरिका का अड़ंगा किसी काले अध्याय की तरह जुड़ा हुआ है। जनवरी में डोनाल्ड ट्रंप के सत्ता संभालने के बाद से ही वाशिंगटन का रुख नई दिल्ली के प्रति आक्रामक और ट्रांजेक्शनल हो गया है। ट्रंप प्रशासन ने कूटनीतिक शिष्टाचारों को दरकिनार करते हुए सीधे तौर पर आर्थिक युद्ध की भाषा बोलनी शुरू कर दी है। ट्रंप का यह स्पष्ट कथन कि वे भारत को रूसी तेल खरीदने से रोकने के लिए विवश करेंगे, केवल कोरी धमकी नहीं थी। 6 अगस्त को अमेरिका द्वारा रूसी तेल खरीद पर भारत पर 25 फीसदी अतिरिक्त शुल्क लगाना और 22 अक्टूबर को रोसनेफ्ट और लुकोइल जैसी 34 दिग्गज रूसी कंपनियों पर नए प्रतिबंध थोपना यह साबित करता है कि अमेरिका अपने 'दुश्मनों' के साथ व्यापार करने वाले मित्रों को भी बख्शने के मूड में नहीं है।

इसका सीधा असर भारतीय अर्थव्यवस्था और ऊर्जा सुरक्षा पर पड़ना शुरू हो गया है। भारतीय तेल कंपनियाँ, जो अब तक रूस से सस्ता तेल खरीदकर भारी मुनाफा कमा रही थीं और देश में ईंधन की कीमतों को नियंत्रित रख पा रही थीं, अब अमेरिकी प्रतिबंधों के डर से सहमी हुई हैं। स्पॉट मार्केट से तेल के विकल्प खोजना न केवल महंगा है, बल्कि यह भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए भी एक चुनौती है। स्थिति की गंभीरता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि ऑयल इंडिया कॉर्पोरेशन जैसी नवरत्न कंपनी का लगभग 300 मिलियन डॉलर का लाभांश रूसी बैंकों में फँस कर रह गया है, जिसे अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंधों के कारण भारत लाना असंभव हो रहा है। ये कंपनियाँ अब आगामी शिखर बैठक की ओर उम्मीद भरी नजरों से देख रही हैं कि शायद पुतिन और मोदी कोई ऐसा वित्तीय रास्ता निकालें जो डॉलर के वर्चस्व और अमेरिकी प्रतिबंधों की काट बन सके।

वलदाई चर्चा मंच से पुतिन का यह तर्क बेहद वजनदार और आर्थिक यथार्थ के करीब है कि यदि भारत अमेरिकी दबाव में आकर रूसी ऊर्जा उत्पादों से मुँह मोड़ता है, तो उसे 9 से 10 अरब डॉलर तक का सीधा नुकसान होगा। और विडंबना यह है कि यदि वह अमेरिकी आदेश को मान भी ले, तो भी उस नुकसान की भरपाई अमेरिका नहीं करेगा, बल्कि उल्टा शुल्क के रूप में और धन वसूलेगा। पुतिन का यह प्रश्न कि 'फिर ऐसा करने का औचित्य क्या है?', भारतीय नीति निर्माताओं के मन में भी गूँज रहा है। दूसरी ओर, डोनाल्ड ट्रंप और उनकी टीम दबाव को चरम सीमा तक ले जाने की रणनीति पर काम कर रही है। ट्रंप द्वारा अमेरिकी कांग्रेस के उस विधेयक का समर्थन करना, जिसमें 'सेकेंडरी सैनक्शंस' का प्रावधान है, भारत के लिए खतरे की घंटी है। 500 फीसदी तक के आयात शुल्क का डर दिखाकर अमेरिका भारत को घुटने टेकने पर मजबूर करना चाहता है। यह केवल तेल की बात नहीं है; यह भारत की संप्रभुता और स्वतंत्र विदेश नीति पर सीधा हमला है। अमेरिका चाहता है कि भारत अपनी गुटनिरपेक्षता की पुरानी नीति को छोड़कर पूरी तरह से उसके पाले में खड़ा हो जाए, भले ही इसके लिए उसे अपने पुराने और विश्वसनीय मित्र रूस की बलि क्यों न चढ़ानी पड़े।

इतिहास के पन्नों को पलटें तो ठीक पच्चीस साल पहले, अक्टूबर 2000 में जब अटल बिहारी वाजपेयी और व्लादिमीर पुतिन ने रणनीतिक साझेदारी की घोषणा पर हस्ताक्षर किए थे, तब भी दुनिया बदल रही थी, लेकिन भारत और रूस एक-दूसरे के साथ खड़े थे। उस समझौते ने तय किया था कि शीर्ष नेताओं की वार्षिक बैठकें बिना किसी बाधा के होंगी। पिछले पाँच वर्षों में, विशेषकर यूक्रेन युद्ध और कोविड के बाद, यह परंपरा बाधित जरूर हुई है। 2021 में पुतिन की आखिरी भारत यात्रा के बाद से दुनिया बहुत बदल चुकी है। 2023 में G20 के दौरान पुतिन का न आना और लावरोव का प्रतिनिधित्व करना, कहीं न कहीं रिश्तों में आई व्यावहारिक जटिलताओं का संकेत था। लेकिन अब, जब पुतिन खुद दिल्ली आ रहे हैं, तो यह उस 'अंतराल' को भरने की कोशिश है।

आगामी शिखर सम्मेलन में लॉजिस्टिक्स, भुगतान व्यवस्था और व्यापार असंतुलन जैसे नीरस लगने वाले मुद्दे दरअसल इस रिश्ते की जीवनरेखा हैं। जब तक दोनों देश डॉलर से इतर भुगतान का कोई ठोस तंत्र (जैसे डिजिटल मुद्रा या विशेष रुपया-रूबल व्यवस्था का नया संस्करण) विकसित नहीं कर लेते, तब तक उनकी रणनीतिक साझेदारी अमेरिकी प्रतिबंधों की तलवार के नीचे लटकी रहेगी। विशाखापट्टनम में रूसी उपमंत्री का आना और चेन्नई-व्लादिवोस्तोक समुद्री गलियारे पर जोर देना इसी रणनीति का हिस्सा है कि व्यापार के लिए ऐसे रास्ते खोले जाएं जो पश्चिमी निगरानी से दूर हों।

निष्कर्षतः, दिसंबर में होने वाला यह शिखर सम्मेलन भारत के लिए एक कठिन कूटनीतिक परीक्षा साबित होगा। एक तरफ रूस के साथ दशकों पुराने विश्वास और भविष्य की ऊर्जा जरूरतों का सवाल है, तो दूसरी तरफ अमेरिका के साथ बढ़ते व्यापारिक रिश्ते और उसकी नाराजगी का डर। प्रधानमंत्री मोदी और उनकी टीम को एक ऐसी बारीक लकीर पर चलना होगा जहाँ वे रूस के साथ अपने संबंधों को गहरा भी कर सकें और अमेरिका के आर्थिक प्रतिबंधों के जाल में फँसने से भी बच सकें। मॉस्को से लेकर दिल्ली तक बिछी यह बिसात और वाशिंगटन की टेढ़ी नज़र यह बता रही है कि आने वाला महीना भारतीय विदेश नीति की दशा और दिशा तय करने वाला है। क्या भारत अपनी रणनीतिक स्वायत्तता को बचा पाएगा या उसे महाशक्तियों के टकराव में कोई एक पक्ष चुनने के लिए विवश होना पड़ेगा? उत्तर भविष्य के गर्भ में है, लेकिन इतना तय है कि इस बार की सर्दियाँ कूटनीतिक तापमान को बहुत बढ़ा देंगी।

---

**यह लेख रूसी समाचारपत्र कोमर्सांट के वरिष्ठ स्तंभकार सेर्गेई स्त्रोकिन द्वारा लिखित मूल आलेख के तथ्यों एवं संदर्भों पर आधारित है। उनके अध्यवसाय एवं शोध के प्रति कल्ट करंट आभार व्यक्त करते हुए पुनः प्रकाशित कर रहा है।**

कामयार कायवानफ़ार

ईरान इन दिनों पानी की किल्लत से जूझ रहा है. उसकी यह स्थिति सिर्फ़ सूखे की वजह से नहीं बल्कि उसकी पुरानी नीतियों और सोच का नतीजा है. शाह के दौर में खेती को छोड़कर उद्योग पर ध्यान दिया गया और क्रांति के बाद पानी को अधिकार बनाकर खूब इस्तेमाल बढ़ा दिया गया. यही फैसले मिलकर आज देश को ऐसी प्यास तक ले आए हैं, जिसे सिर्फ़ नई नीतियां नहीं, नई सोच ही दूर कर सकती है.

# सूख रहा ईरान

आज ईरान में पानी का जो संकट है, उसके बीज उसकी राजनीतिक यात्रा में छिपे हुए हैं। पहलवी के शासन-काल में, इस देश ने पूरा ज़ोर औद्योगीकरण और आधुनिकीकरण पर लगाया। श्वेत क्रांति (1963) के जरिये, शाह ने ईरान को एक ऐसा आधुनिक और औद्योगिक देश बनाने का प्रयास किया जो पश्चिम की अर्थव्यवस्था को मज़बूती से टक्कर दे सके। उस समय खेती को न सिर्फ़ जानबूझकर नज़रंदाज़ किया गया बल्कि उसे प्राथमिकता से बाहर रखा गया। यह एक सोचा-समझा फ़ैसला था जिसमें पूंजी, श्रम और बुनियादी ढांचे का इस्तेमाल फैक्टरियों, तेल और भारी उद्योग में किया गया।

भूमि सुधार ने बड़ी जागीरों को छोटे-छोटे हिस्सों में बांट दिया और जमींदार-किसान के पारंपरिक रिश्ते ख़त्म कर दिए। समानता के उद्देश्य से किए गए इस सुधार ने खेती-किसानी के कामों को प्रभावित किया और ग्रामीण कुलीन वर्ग को अलग-थलग कर दिया। चूंकि पूंजी और सिंचाई के बुनियादी ढांचों का अभाव हो गया इसलिए कई छोटे किसानों ने शाह के आधुनिकीकरण को ईरान की पारंपरिक कृषि-व्यवस्था के ख़िलाफ़ माना।

यह नाराज़गी राजनीतिक विद्रोह के लिए महत्वपूर्ण साबित हुई। ऐसे ही नाराज़ गांव वालों और छोटे शहरों के लोगों ने 1979 की इस्लामी क्रांति का शुरुआती समर्थन किया। धार्मिक नेताओं ने इस नाराज़गी का फ़ायदा उठाया जिनमें अयातुल्ला खुमैनी भी शामिल थे जो एक मामूली ग्रामीण पृष्ठभूमि से आए थे। इस क्रांति के बाद, नीतियों में एक बड़ा बदलाव यह आया कि खेती सिर्फ़ आर्थिकी नहीं रही बल्कि राष्ट्रीय सच्चाई और क्रांतिकारी न्याय का वैचारिक प्रतीक बन गई।

ईरान-इराक युद्ध (1980-1988) ने इस बदलाव को और पुख़्ता कर दिया। युद्ध के समय आत्मनिर्भरता ने 'खोदकाफ़ाई' की सोच को आगे बढ़ाया, जिसका अर्थ है आत्मनिर्भरता। खाद्यान्न का उत्पादन विदेशी निर्भरता के ख़िलाफ़ मज़बूती का प्रतीक बन गया। सरकार ने खेती को बड़े पैमाने पर बढ़ाने का फ़ैसला किया। बांध वगैरह बनाए गए और गेहूं, चावल व गन्ने जैसी पानी की अधिक खपत करने वाली फ़सलों को सब्सिडी दी गई, यहां तक कि सूखाग्रस्त इलाकों में भी।

शिया परंपरा में बताया जाता है कि कर्बला की लड़ाई के दौरान इमाम हुसैन और उनके परिवार व समर्थकों तक पानी की आपूर्ति रोक दी गई थी। उन्हें पानी तक पहुंचने न देना यहां का एक मज़बूत नैतिक प्रतीक है। क्रांति के बाद इसी प्रतीक ने कल्याणकारी नीति का आकार लिया और मुल्क ने यह एलान कर दिया कि किसी को भी पानी से रोका नहीं जाएगा। घरों तक पानी पहुंचाने में आने वाली बाधाएं कम की गईं और यह सुनिश्चित किया गया कि पानी कोई वस्तु नहीं रहे बल्कि लोगों का अधिकार बने। हालांकि, इस मज़हबी प्रतिबद्धता ने पानी के ज़्यादा इस्तेमाल को बढ़ावा दिया और जल संरक्षण के प्रति लोगों को उदासीन बना दिया। इस कारण यहां पानी की लंबे समय तक कमी रहने वाली परिस्थितियां पैदा हो गईं।

## सांस्कृतिक और वैचारिक पहलू

ईरान में पानी सिर्फ़ कुदरती चीज़ नहीं हैं बल्कि एक वैचारिक रचना है जो उसकी क्रांति की पहचान है। इस्लामी गणराज्य सभी तक पानी और रोटी पहुंचाने को ईश्वर का इंसाफ़ और हुकूमत की करुणा मानता है। इस कारण ख़ास तौर से गांवों में खेती के लिए मिलने वाली सब्सिडी राजनीतिक समावेश और वफ़ादारी का ज़रिया बन गई। किसान को लंबे समय से 'क्रांति का रखवाला' माना जाता रहा है, वे अब सस्ती बिजली और सिंचाई के पानी से बेहिसाब लाभ उठाने लगे।

यह सिर्फ़ लोगों के लुभाने का रास्ता नहीं है बल्कि यह बताता है कि सरकार की गांवों में कितनी गहरी जड़ें हैं। शुरुआती नेतृत्व ने खेती-किसानी को एक पवित्र काम और एक क्रांतिकारी फ़र्ज़ माना। वे आत्मनिर्भरता को नैतिक गुण मानते थे। वे उद्योग को सामाजिक समानता से कम महत्व देते थे और काम करने की क्षमता के बजाय वफ़ादारी को अहमियत देते थे।

इस तरह रोटी यहां एक वैचारिक मुद्दा बन गई है। इसका पता अनगिनत फ़ारसी मुहावरों से भी चलता है, जो सम्मान, रोजी-रोटी और ईश्वरीय आशीर्वाद का आधार बनाकर तैयार किए गए हैं। इसलिए यह सुझाव देना कि रोटी या उसे बनाने वाले पानी को एक क़ीमती चीज़ मानना चाहिए, राजनीतिक रूप से अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारने जैसा है। यही कारण है कि पानी की कीमतों में सुधार के प्रस्तावों को आमतौर पर 'इस्लामी विरोधी' या 'कुलीनवादी' कहकर नकार दिया जाता है।

फ़ारसी और इस्लामी संस्कृति में रोटी का जो प्रतीकात्मक महत्व है, उसने इस प्रतिबद्धता को और बढ़ा दिया है। यह सुनिश्चित करना कि 'रोटी हमेशा मेज़ पर रहे' और 'किसी दूसरे देश से न आए' एक सामाजिक अनुबंध और धार्मिक ज़िम्मेदारी, दोनों बन चुकी है।

इसी सोच ने नीतिगत गतिरोध भी बढ़ाए हैं। फ़ैसले लेने वाले, जिनमें से कई लोग नौकरशाही के बजाय क्रांति व युद्ध के समय की संस्थाओं से उभरे हैं, जल संकट को युद्ध के समय के नज़रिये से देखते हैं, और इस तरह वहां इसको सहना पड़ता था, जल का संरक्षण नहीं किया जाता। पानी की कमी तनाव की एक और वज़ह है, जिसके लिए भी नागरिकों को धैर्य का परिचय देना होता है। इस तरह की सोच सुधार-प्रक्रिया को कमज़ोर करती

है। नतीजतन, सब्सिडी बनी रहती है, खपत भी जारी रहती है और वह कहानी, जो कभी देश व समाज को जोड़ती थी, आज स्थिरता के लिए ज़रूरी रणनीतिक योजना में बाधक बन रही है।

## मौजूदा चुनौतियां

इन सबका नकारात्मक असर पड़ता है। ईरान का जल संकट अब ढांचागत, प्रशासनिक और सामाजिक पहलुओं को भी प्रभावित कर रहा है।

**ढांचागत और औद्योगिक संघर्ष:** क्रांति के बाद शुरुआत में जो सरकारें यहां बनीं, उन्होंने बांधों व नहरों पर काफ़ी ख़र्च किया, लेकिन 'जल माफिया' ने ऐसे बांध बनाए, जो शायद ही कभी पूरी तरह भरे गए। इसके कारण 1990 के दशक के बाद से मैदानी इलाकों में भूजल का स्तर गिरता गया और कभी उपजाऊ रही ज़मीनें धूल में बदलने लगीं। इससे भी गंभीर बात यह है कि अब राज्य नियामक भी है और प्रतिस्पर्धी भी। जल की भारी खपत करने वाले ईरान के कई उद्योग, जिनमें स्टील, पेट्रोकेमिकल और ऊर्जा क्षेत्र शामिल हैं, पूरी तरह सरकारी हैं या अर्ध-सैन्य प्रतिष्ठान। इस तरह सरकार को उन्हीं कमियों से फ़ायदा मिलता है, जिनको ठीक करने का ज़िम्मा उसके कंधों पर है। औद्योगिक जल के इस्तेमाल को रोकने वाले किसी भी सुधार से सरकार के राजस्व पर भी ख़तरा पैदा होगा।

**भ्रष्टाचार और गैर-कानूनी तरीके से पानी निकालना:** कुओं की बड़े पैमाने पर गैर-कानूनी खुदाई से पानी की कमी और बढ़ गई है। हजारों गैर-कानूनी कुओं से बिना रोक-टोक पानी निकाला जा रहा है। इनको अक्सर राजनेताओं का संरक्षण भी मिलता है। भ्रष्टाचार और कानून को मज़बूती से लागू न करने का मतलब है कि जहां कानून है, वहां भी वे मनमाने ढंग से लागू किए जा रहे हैं। यहां के अधिकारियों को जुर्माना लगाने पर कोई ख़ास प्रोत्साहन नहीं दिया जाता और वे इस गठजोड़ से फ़ायदा उठाने लगते हैं।

**तकनीकी ख़ामियां और नीतिगत जड़ता:** ईरान-इराक युद्ध के बाद, कई पूर्व सैनिक सिविल सेवा में शामिल हुए। क्रांति करने के कारण उनको वफ़ादार ज़रूर माना गया, लेकिन उनके पास कोई तकनीकी नज़रिया नहीं है। यहां पानी संबंधी नीति तय करने का काम जल-विज्ञानी या अर्थशास्त्री का नहीं, बल्कि सैन्य और समान विचार रखने वाली हस्तियों के पास है। इसीलिए, जल संकट का समाधान युद्ध के समय की परिस्थितियों में ढूंढा जाता है- प्रतिक्रियाशील, कम समय वाला और सुधार के बजाय प्रतिरोध के रूप में।

**आपातकालीन शासन:** ईरान की व्यापक राजनीतिक संस्कृति इस उदासीनता को और मज़बूत बनाती है, क्योंकि वहां की सरकार लगातार आपातकालीन परिस्थितियों से मुकाबला करती रहती है। उसे प्रतिबंध, महंगाई, ऊर्जा की कमी और सामाजिक अशांति, सब पर एक साथ काम करना पड़ता है। इस कारण जल संकट को ठीक करने के उपायों को ज़्यादा महत्व नहीं मिल पाता। यहां निवेश रणनीति को लेकर भी एकराय नहीं है और लंबे समय के लिए जलग्रहण क्षेत्र का प्रबंधन करने के बजाय बांध बनाने जैसी परियोजनाओं को अहमियत दी जाती है, क्योंकि ये लोगों की सीधी नज़रों में होते हैं और तेज़ी से पूरे भी हो जाते हैं।

**सामाजिक और सुरक्षा पर असर:** ग्रामीण इलाके, जो कभी क्रांति का नेतृत्व कर

रहे थे, आज असंतोष के केंद्र बन गए हैं। इस्फ़हान में ज़ायंद रूद जैसी नदियों के सूखने को लेकर किसानों ने बार-बार विरोध-प्रदर्शन किया है और सरकार से जवाबदेही तय करने की मांग की है। ख़ूज़स्तान में, जहां गलत तरीके से बांध-निर्माण और उद्योगों के लिए नदियों को मोड़ने का काम होने के कारण खेती बर्बाद हो गई, इसी तरह के प्रदर्शन हिंसक हो गए थे। सूखे की समस्या गांवों से लोगों का पलायन शहरी इलाकों में बढ़ा रही है, जिससे बेरोज़गारी, घरों की कमी और लोगों की नाराज़गी बढ़ रही है।

## आगे का रास्ता

ईरान के पास अपने जल संसाधनों को ज़्यादा टिकाऊ बनाने की वैज्ञानिक क्षमता है, लेकिन उसका राजनीतिक और वैचारिक ढांचा सुधार के कामों में रुकावट डालता है।

**अलग-अलग फ़सलों की खेती और आयात:** चावल और गन्ने जैसी जल का ज़्यादा खपत करने वाली फ़सलों का आयात करके और सूखा झेलने वाली किस्मों पर ध्यान देकर ईरान अपने जल संसाधनों पर दबाव कम कर सकता है। हालांकि, यह आत्मनिर्भरता के सिद्धांत के विपरीत है, जो उसकी क्रांति की पहचान रही है। राजनेताओं को डर है कि आयात को आगे बढ़ाने से क्रांति के वायदे के साथ प्रतीकात्मक रूप से छल करना होगा। अलग-अलग तरह की फ़सलों की खेती के अलावा, ईरान बाढ़ से सिंचाई की जगह कुशल ड्रिप सिंचाई तंत्रों का उपयोग कर सकता है और अपनी सिंचाई व्यवस्था को आधुनिक बना सकता है। इससे खेती के पानी का अधिक से अधिक उपयोग हो सकेगा। भूजल को रिचार्ज करने वाले छोटी-छोटी योजनाएं और मिट्टी की नमी की निगरानी करने वाली व्यवस्था यदि साथ-साथ आगे बढ़ाई जाएंगी, तो नए बांधों पर भारी-भरकम ख़र्च किए बिना ग्रामीण आजीविका को टिकाऊ बनाने में मदद मिल सकेगी।

**सब्सिडी और शासन में सुधार:** मूल्य निर्धारण का अच्छा तंत्र बनाकर भी पानी की बर्बादी रोकी जा सकती है, लेकिन सब्सिडी हटाने से सरकार के अपने सबसे वफ़ादार आधार, यानी ग्रामीण किसानों में नाराज़गी फैलने का ख़तरा हो सकता है। 2019 का अनुभव हमारे सामने है, जब ईंधन की कीमतें बढ़ने से पूरे देश में अशांति फैल गई थी। असल में दिक्कत यह है कि राज्य खुद पानी खूब ख़र्च करता है, इसलिए किसी नियम को प्रभावी बनाने के लिए उसको पहले अपने उद्योगों पर प्रतिबंध लगाना होगा, जिसका उसने लगातार विरोध ही किया है। कीमतों में सुधार के साथ-साथ शहरी गंदे पानी की रीसाइक्लिंग और औद्योगिक पानी के पुनर्चक्रण में भी निवेश आवश्यक है, जिससे स्वच्छ जल का उपभोग कम हो सकेगा। विलवणीकरण (खारे पानी से लवण निकालकर इस्तेमाल के लायक बनाना) बंदर-अब्बास और बुशहर जैसे तटीय शहरों के लिए रणनीतिक भंडार बना सकता है, जिससे स्थानीय जल संसाधनों पर दबाव कम होगा।

**तकनीकी सशक्तिकरण:** सैन्य और धार्मिक लोगों के बजाय फ़ैसले लेने वाली जगहों पर तकनीकी रूप से प्रशिक्षित प्रशासकों को लाना होगा, जिससे जल प्रबंधन में अधिक स्थायी व्यवस्था बन सकेगी। हालांकि, इस तरह के बदलाव के लिए सत्ता में भी बदलाव आवश्यक है, जिसका इस्लामी गणराज्य शायद ही समर्थन करेगा। जब तक ज़रूरी फ़ैसले 'प्रतिकूल सोच' के लोग तय करते रहेंगे, तब तक नीतिगत प्रक्रियाएं बड़े ढांचागत सुधारों को आगे बढ़ाने के बजाय कम समय के लिए नियंत्रित व्यवस्था बनाने और विरोध-प्रदर्शनों पर सख़्ती बरतने पर ज़ोर देती रहेंगी।

**कामयार कायवानफ़ार एक मूल फ़ारसी और अंग्रेज़ी भाषी संचार एवं जन–संपर्क विशेषज्ञ हैं, यह आलेख मूल रूप से ओआरएफ के मध्यपूर्व संस्करण में प्रकाशित हुआ है, हम साभार इसे पुनः प्रकाशित कर रहे हैं।**

# नौसेनाओं का नव जागरण काल

दक्षिण एशियाई देशों, ग्लोबल साउथ में नौसेना के नव जागरण की लहर चल रही है। चीन एक बड़ी लहर के तौर पर सामने आ रहा है, उसके पीछे पाकिस्तान और बांग्लादेश भी लेकिन हमारी खामोश और ठोस तैयारियां भी इनसे पीछे नहीं

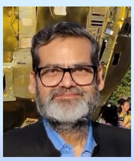

संजय श्रीवास्तव

ग्लोबल साउथ के समुद्री सीमा रखने वाले देशों में एक नयी प्रवृत्ति परिलक्षित हो रही है। ऐसे देशों की नौसेनाएं जैसे नवजागरण युग में प्रवेश कर चुकी हैं। ये देश अपनी नौसेना के साज संवार, आधुनिकीकरण के प्रति इतने उद्धत दिखते हैं कि यह भी नहीं देख रहे कि उनकी समुद्री सीमाओं पर खतरे के अनुपात में यह कवायदें कहीं अतिरेकी तो नहीं। ज्यादातर की कोशिश नौसेना क्षमताओं के विकास से समुद्री शक्ति को एक नए स्तर पर ले जाने का है। दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील, ईरान, थाईलैंड आदि भी अपने बेड़े में अत्याधुनिक फ्रिगेट, पनडुब्बी और मल्टी रोल युधपोत जोड़े जा रहे हैं, इससे हिंद महासागर और दक्षिणी समुद्री क्षेत्र की जियो-सामरिक प्रतिस्पर्धा बढ़ रही है। इस नौसेना नव-जागरण के परिदृश्य में चीनी नौसेना का लगातार विस्तार, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी नौसेना में आपसी सहकार तथा इन दोनों के लिए चीन जिस तरह बन रहा है मददगार, वह काबिले ग़ौर है। भारत को दक्षिण एशिया में मुख्यतः चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश की नौसानिक तैयारियों पर गहरी नजर रखनी ही होगी और उसके मद्देनजर तैयारियां भी। उसे वैश्विक परिदृश्य में नौसैनिक विस्तार को देखते हुए इस क्षेत्र में श्रीलंका, मालदीव वगैरह से भी बाखबर रहना होगा। पाकिस्तान का जो युद्धपोत 54 साल बाद पहली बार बंगाल की खाड़ी से होता हुआ रक्षा सहयोग को मजबूत करने के मकसद से गुडविल विजिट पर बांग्लादेश पहुंचा था वह 12 नवंबर को भारत के लिए यह सवाल छोड़ते हुए विदा हो गया कि दोनों देशों के बीच नौसेना के सुदृढीकरण के लिए कोई खिचड़ी क्यों और कैसे पक रही है?

चटगांव बंदरगाह बंगाल की खाड़ी में देश के पूर्वी तट के करीब है, चीन यहां अपना अड्डा बनाना चाहता है, इसलिए पाकिस्तानी और चीनी जहाजों की आवाजाही से भारत की समुद्री सुरक्षा पर खतरा बढेगा। फोर्सेस गोल-2030 के अंतर्गत बांग्लादेश नौसेना नए युद्धपोत खरीदने के अलावा पनडुब्बी, आईएसआर यानी इंटेलिजेंस, सर्विलांस, रिकॉन तथा स्वदेशी निर्माण क्षमताएँ बढ़ा रही है। पनडुब्बी और समुद्री विमान संचालन की सुविधाओं में वृद्धि के लिए राबनाबाद में देश का सबसे बड़ा नौसैनिक अड्डा बन रहा है। पाकिस्तान चीन तथा तुर्की के बने कई युद्धपोत खरीदने के साथ उनके सहयोग से युद्धपोतों व पनडुब्बियों के 9-वर्षीय आधुनिकीकरण कार्यक्रम में लगा है। चीन के सहयोग से विकसित उसकी पहली हांगोर-क्लास पनडुब्बी अगले साल उसकी नौसेना में शामिल हो जाएगी और इसकी संख्या 2028 तक आठ पहुंचाने का उसका इरादा है। तुर्की में बना अत्याधुनिक हथियार व स्टील्थ खूबियों से लैस बाबर-क्लास फ्रिगेट इसी साल शामिल होने की खबर है।

पाकिस्तान नौसेना तुर्की द्वारा दान की गई डोगन-क्लास फास्ट अटैक

क्राफ्ट को अपनी नौसेना में शामिल करने वाले मालदीव के साथ संयुक्त अभ्यास कर रही है। इन कवायदों के पीछे पाकिस्तान का मकसद समुद्री संसाधनों और रणनीतिक समुद्री मार्गों की सुरक्षा के अलावा शक्ति प्रदर्शन भी है। श्रीलंका नौसेना भी चीनी, रूसी और पश्चिमी साझेदारों के साथ मिलकर ताकत बढाने की जुगत में है। चीन ने हाल-ही में अपना तीसरा अत्याधुनिक तकनीक संपन्न एयरक्राफ्ट कैरियर फुजियान उतारा और चौथे की घोषणा करने के साथ हिंद-महासागर, बंगाल की खाड़ी और हिन्द-ओमान जलडमरूमध्य में चीन अपनी समुद्री महत्वाकांक्षा तथा शक्ति प्रदर्शन का ड़ंका बजा दिया। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैटापल्ट सिस्टम वाले फुजियान के आने पर चीन की नौसेना अमेरिका के बाद दुनिया का दूसरी ऐसी नौसेना बन गई जिसके पास इतनी आधुनिक तकनीक से संपन्न कैरियर फ्लीट है। फुजियान जैसे बड़े जहाज पर जे-35 स्टेल्थ फाइटर, केजे-600 वॉर्निंग विमान और जे-15 जैसे आधुनिक विमान तैनात हो सकते हैं, छोटे रनवे से भी उडान भर और उतर सकते हैं। इससे उसकी नौसेना की लंबी दूरी की मारक क्षमता को कई दिनों तक अबाध जारी रखने की उसकी क्षमता बढ़ेगी। वह एक साथ रक्षा या बचाव तथा हमले और निगरानी संबंधी ऑपरेशंस को लंबे समय तक चला सकता है। वह इसके चलते चीन ताइवान, दक्षिण चीन सागर और हिंद महासागर में अपनी ताकत दिखा सकता है। अब चीन अपने तीनों कैरियर्स रूस की डिजाइन पर बने लियाओनिंग, शानडोंग और स्वदेशी फुजियान को एक साथ कर के एक कैरियर स्ट्राइक ग्रुप बना सकता है जिससे प्रभावित होने वाला इस क्षेत्र में महज भरत ही होगा। भारत की मुसीबत यह है कि उसके ईंधन आपूर्ति और व्यापार मार्ग यहीं से गुजरते हैं। हालांकि फुजियान कितनी जल्दी वार रेडी होगा यह अभी देखना है फिर भी इसके आने के बाद भारतीय नौसेना पर दबाव बढ़ेगा कि वह भी अपने जहाजों, विमानों और रडार सिस्टम को आधुनिक बनाए। भारत के पास फिलहाल आईएनएस विक्रमादित्य और आईनएस विक्रांत दो एयरक्राफ्ट कैरियर हैं। दोनों स्की-जंप रैंप तकनीक वाले हैं, के पास इससे बहुत आगे की तकनीक है जो नौसेना को जंग के दौरान दुश्मन से मीलों आगे ले जाते हैं, हालांकि भारत अगली पीढ़ी के ऐसे युद्धपोत बनाने पर विचार कर रहा है जिसमें इक्ट्रोमैग्नेटिक कैटापल्ट सिस्टम हो। अज की रफ्तार से अनुमान लगाएं तो उसे लक्ष्य प्राप्ति में कई बरस लगेंगे।

आईनएस विक्रमादित्य को साल 2035 में रिटायर्ड किया जा सकता है। हिंद महासागर में सामरिक संतुलन बनाए रखने के लिए तीसरे विमानवाहक पोत की ज़रूरत है जिसकी तैयारी तेज़ है, इसके अलावा दो अन्य युद्धपोत की तैनाती की भी योजना हैं। पर सवाल यह है कि क्या वे फुजियान जितने आधुनिक होंगे? बांग्लादेश का चीन-सहयोग और नेवल बेस के माध्यम से चीन का विस्तार भारत के लिए चिंता का विषय है तो पाकिस्तान-चीन गठबंधन, बंगाल की खाड़ी में चीन-बांग्लादेश समुद्री घुसपैठ तथा अफ्रीका-अरब सागर में चीन की नज़र भारत को रणनीतिक रूप से दबाव में लाता है। हमारे प्रतिस्पर्धियों ने तय समय-सीमा वाले कार्यक्रम अपनाए हैं, हमने इसके क्वाब में इतनी तीव्र प्रक्रिया अपनाई है कि हमारा पिछड़ना नामुमकिन है। हालांकि पड़ोसी और ग्लोबल साउथ के देशों की नई नौसैनिक तैयारियां भविष्य में सीधे तौर पर भारत की सामरिक और नीतिगत कार्रवाइयों को प्रभावित करेंगी, जिससे हमारे लिए सतर्क, उन्नत और सहयोग आधारित अप्रोच जरूरी हो जाती है। हमको बंगाल की खाड़ी, अरब सागर एवं हिंद महासागर में मल्टी-डोमेन सतर्कता, निगरानी और नौसैनिक शक्ति प्रदर्शन को बढ़ाना होगा। प्रतिस्पर्धात्मक नौसेना विस्तार से शक्ति प्रदर्शन का खेल के बढने से सागरीय संपर्क, संसाधनों की रक्षा, समुद्री आपूर्ति श्रृंखला एवं मल्टी-लैटरल समन्वय अगे बहुत आवश्यक हो जाएगा। इसलिए हमें टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन, अंतरराष्ट्रीय सहयोग, बीस्पोक शक्ति संतुलन बनाए रखने के लिए रणनीतिक व कूटनीतिक सक्रियता और बढ़ानी होगी। हमें क्षमताओं का विस्तार करने के लिए जहाज, पनडुब्बी, विमान व बेस इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण समय-सीमा के भीतर सुनिश्चित करने के साथ समुद्री खुफिया नेटवर्किंग बढाने के साथ मित्र देशों के साथ आधार व अभ्यास बढ़ाना होगा। अमेरिका,ऑस्ट्रेलिया,जापान व फ्रांस के साथ साझा नौसैनिक मिशनों और प्रशिक्षण प्रतिष्ठानों पर साझेदारी करनी होगी। हालांकि ग्लोबल साउथ में नौसैनिक नव-जागरण का दौर भारत के लिए चुनौती के साथ अवसर भी प्रस्तुत कर रहा है। यदि भारत ने समय पर आत्मनिर्भर, स्वदेशी नव-नौसैनिक क्षमताओं को स्थिरता व विस्तार के साथ लागू किया, तो वह भारतीय-महासागर क्षेत्र में अपना नेतृत्व सुनिश्चित कर सकता है। सरकार और नौसेना यह बात जानती है कि क्षमता विकास से अपने समुद्री हितों को वास्तविक शक्ति में तब्दील करना होगा। इस दिशा में पीछे रहना जोखिम भरा हो सकता है। उसने इस ओर महत्वपूर्ण ठोस कदम उठा भी लिए हैं। बेशक समुद्र में भारत की शक्ति बढ़ेगी, वहाँ भू-राजनीतिक समीकरण जल्द पलटेंगे।

# वर्चस्व का नया रणनीतिक गलियारा

यूरेशिया में खामोशी से एक बड़ी क्रांति आकार ले रही है। आईएनएसटीसी (**INSTC**) का पूर्वी गलियारा अब नक्शे पर खिंची महज एक लकीर भर नहीं है—यह मध्य एशिया, रेयर-अर्थ (दुर्लभ) खनिजों की संपदा और स्वेज नहर से परे वैकल्पिक व्यापार मार्गों तक पहुँचने के लिए भारत के सबसे रणनीतिक द्वार के रूप में तेजी से उभर रहा है। मॉस्को से तेहरान तक 12 दिनों की कार्गो यात्रा एक नई व्यावसायिक व्यवस्था की शुरुआत का प्रतीक है।

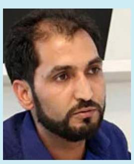

एजाज वानी

इंटरनेशनल नॉर्थ-साउथ ट्रांजिट कॉरिडोर (आईएनएसटीसी) के पूर्वी गलियारे ने 8 नवंबर 2025 को एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर हासिल किया, जब मॉस्को के उत्तर से चली एक मालगाड़ी 62 चालीस-फुटे कंटेनरों को लेकर मध्य एशिया होते हुए ईरान पहुंची। तेहरान के अप्रिन (Aprin) ड्राई पोर्ट तक की यह 900 किलोमीटर की यात्रा 12 दिनों में पूरी हुई, जो ईरान में इंच-बोरुन (Incheh Borun) से प्रवेश करने से पहले कजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान से होकर गुजरी।

मार्च 2025 से, नई दिल्ली गुजरात के मुंद्रा बंदरगाह से ईरान

के बंदर अब्बास बंदरगाह के रास्ते मध्य एशिया तक कार्गो भेजने के लिए इसी मार्ग का उपयोग कर रहा है। भारत के लिए, आईएनएसटीसी का पूर्वी गलियारा न केवल स्वेज नहर का एक विकल्प प्रदान करता है, बल्कि 2030 तक 2 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के निर्यात लक्ष्य को हासिल करने के लिए भी महत्वपूर्ण है। इसके अतिरिक्त, विशिष्ट रेयर-अर्थ खनिजों पर बीजिंग के निर्यात प्रतिबंधों को देखते हुए, यह पूर्वी गलियारा भारत के लिए मध्य एशियाई बाजारों की निर्यात क्षमता का दोहन करने और वहां मौजूद विशाल भंडार का उपयोग करके महत्वपूर्ण खनिजों के लिए चीन पर अपनी निर्भरता कम करने का एक बड़ा अवसर प्रस्तुत करता है।

## आईएनएसटीसी का पूर्वी गलियारा

वर्ष 2000 में हस्ताक्षरित, आईएनएसटीसी एक मल्टीमॉडल परिवहन गलियारा है जो स्वेज नहर को बायपास करते हुए भारत को यूरेशिया से जोड़ता है, जिसमें रूस, ईरान और भारत शामिल हैं। हालाँकि, परस्पर विरोधी हितों और बुनियादी ढांचे की चुनौतियों के कारण इस गलियारे की प्रगति धीमी रही है, जिसके परिणामस्वरूप कार्गो की मात्रा कम रही। लेकिन, इसकी 928 किलोमीटर लंबी रेलवे लाइन, जिसे ईस्टर्न रूट या कजाकिस्तान-तुर्कमेनिस्तान-ईरान (KTI) रूट के रूप में भी जाना जाता है, इस मार्ग के व्यापारिक वॉल्यूम को बढ़ावा देने के लिए तैयार है। 2007 में कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और ईरान के बीच हुए त्रिपक्षीय समझौते के बाद 2009 में केटीआई (KTI) का निर्माण शुरू हुआ था। केटीआई की लगभग 1.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर की कुल लागत में इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक ने 370 मिलियन अमेरिकी डॉलर का योगदान दिया। 2014 में शुरू हुए केटीआई ने मध्य एशियाई देशों, ईरानी बंदरगाहों और भारत के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी प्रदान की। मॉस्को-अप्रिन रेलवे लाइन (जो सरख्स के रास्ते जाने वाले दूसरे पूर्वी मार्ग से लगभग 600 किमी छोटी है) ने केटीआई की कनेक्टिविटी को और बढ़ाया है।

**आईएनएसटीसी एक मल्टीमॉडल परिवहन गलियारा है जो स्वेज नहर को बायपास करते हुए भारत को यूरेशिया से जोड़ता है, जिसमें रूस, ईरान और भारत शामिल हैं। हालाँकि, परस्पर विरोधी हितों और बुनियादी ढांचे की चुनौतियों के कारण इस गलियारे की प्रगति धीमी रही है, जिसके परिणामस्वरूप कार्गो की मात्रा कम रही। लेकिन, इसकी 928 किलोमीटर लंबी रेलवे लाइन, जिसे ईस्टर्न रूट या कजाकिस्तान-तुर्कमेनिस्तान-ईरान रूट के रूप में भी जाना जाता है।**

आईएनएसटीसी का 5,100 किलोमीटर लंबा पश्चिमी गलियारा, जो रूसी-फिनिश सीमा से बंदर अब्बास बंदरगाह तक सबसे घनी आबादी वाले क्षेत्रों को जोड़ता है, सबसे छोटा मार्ग है। हालाँकि, ईरान पर प्रतिबंधों और अन्य भू-राजनीतिक मुद्दों ने इसकी प्रगति को धीमा कर दिया है, और महत्वपूर्ण रश्त-अस्तारा रेलवे लाइन अभी भी अधूरी है। पूर्वी गलियारे को आधिकारिक तौर पर 2022 में लॉन्च किया गया था, जब पहली ट्रेन ने कजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान को पार करते हुए रूस और ईरान के बीच सीधा संपर्क स्थापित किया था। 2023-2024 में, इस गलियारे ने ईरान को लगभग 1.8 से 2 मिलियन टन माल पहुँचाया, जो पिछले वर्ष की मात्रा का लगभग तीन गुना है। 2023 में, रूस, तुर्कमेनिस्तान

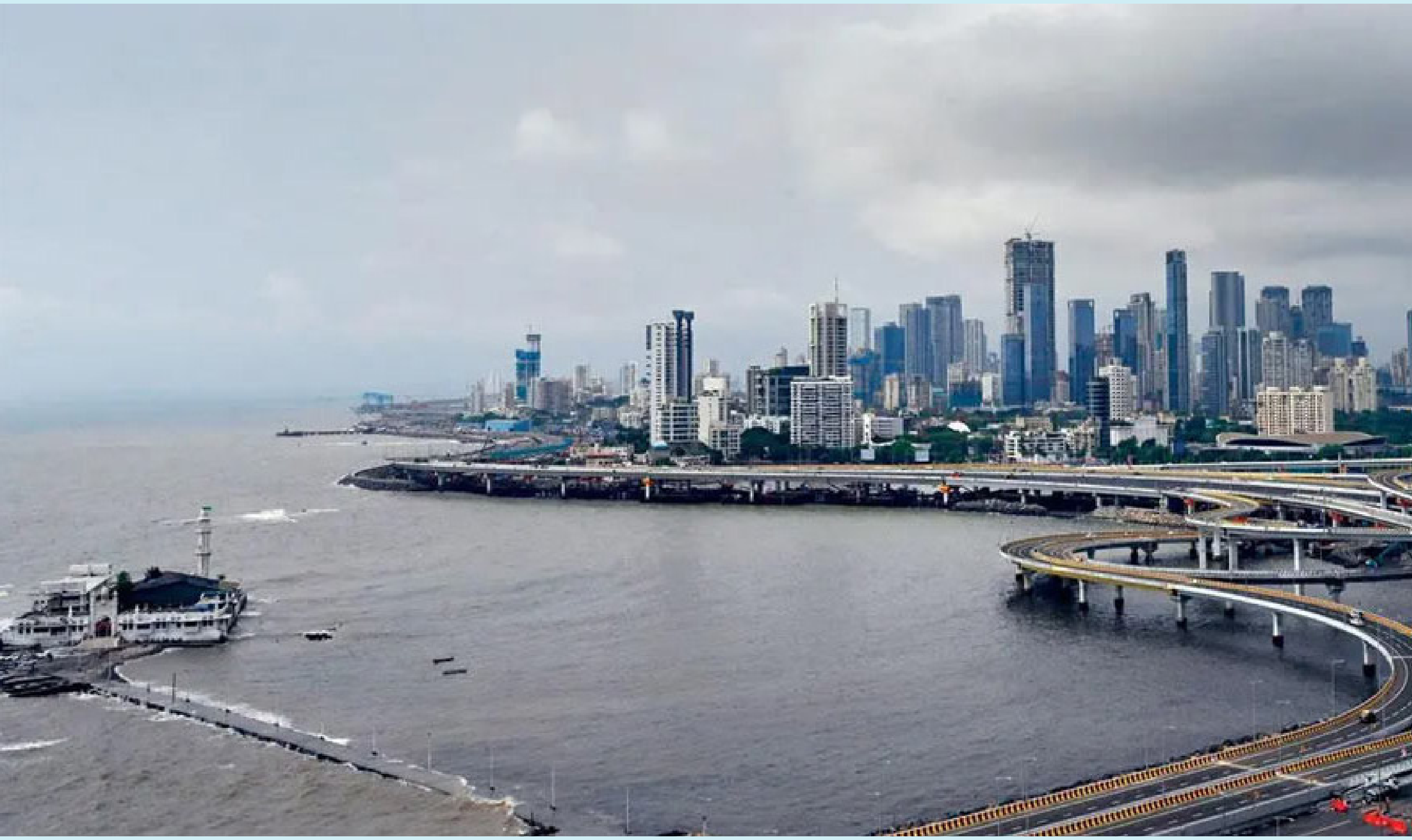

और कजाकिस्तान ने इस गलियारे पर परिचालन के लिए एक नया संयुक्त उद्यम स्थापित किया, जिसमें माल के प्रकार और रूट के आधार पर 20-40 प्रतिशत तक की पारगमन शुल्क (टैरिफ) छूट दी गई। यह मार्ग ज़ार-कालीन ट्रांस-कैस्पियन रेलवे से भी जुड़ता है, जो उज्बेकिस्तान और ताजिकिस्तान तक पहुँच प्रदान करता है।

## भारत के लिए आईएनएसटीसी के पूर्वी रूट की प्रासंगिकता

मार्च 2025 में, भारत ने आईएनएसटीसी के पूर्वी रूट के माध्यम से गुजरात के मुंद्रा बंदरगाह से कजाकिस्तान के लिए एक कार्गो खेप भेजी, जो बंदर अब्बास बंदरगाह से मध्य एशिया तक गई। इस खेप ने 'लैंडलक्ड' (चारों ओर जमीन से घिरे) मध्य एशिया के साथ भारत की कनेक्टिविटी और व्यापार को बढ़ावा दिया। भारत के पास मध्य एशिया के साथ पहले से ही कई समझौते हैं, जिनमें 2018 में 'अशगाबात समझौते' में नई दिल्ली का शामिल होना—जिसका उद्देश्य फारस की खाड़ी और मध्य एशिया के बीच एक ट्रांजिट कॉरिडोर स्थापित करना है—और 'टीआईआर कन्वेंशन, 1975' शामिल है, जो एक ही दस्तावेज के साथ कई अंतरराष्ट्रीय सीमाओं पर कार्गो परिवहन की अनुमति देता है।

इसके अलावा, मध्य एशियाई देशों ने भारत के साथ बेहतर कनेक्टिविटी और व्यापार को लगातार बढ़ावा दिया है और क्षेत्रीय कनेक्टिविटी परियोजनाओं का नेतृत्व करने के भारत के प्रयासों का समर्थन किया है। दोनों क्षेत्रों ने व्यापार और कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए द्विपक्षीय और बहुपक्षीय मंचों के माध्यम से एक-दूसरे के साथ जुड़ाव रखा है। 2019 से, विदेश मंत्री स्तर की भारत-मध्य एशिया वार्ता मुख्य रूप से सीधी कनेक्टिविटी पर केंद्रित रही है। 2020 में, नई दिल्ली ने इस क्षेत्र में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर की 'क्रेडिट लाइन' शुरू की। चाबहार बंदरगाह के माध्यम से कनेक्टिविटी को मजबूत करने के लिए 2023 में एक संयुक्त कार्य समूह की स्थापना की गई थी। मध्य एशिया ने इस बंदरगाह को आईएनएसटीसी ढांचे के भीतर शामिल करने का भी समर्थन किया है। 2024 में, नई दिल्ली ने चाबहार बंदरगाह की सुविधाओं को अपग्रेड करने के लिए ईरान के साथ दस साल के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए, जिससे 'बंदरगाह में बड़े निवेश किए जाने' के रास्ते बने। भारत और मध्य एशिया के बीच क्षेत्रीय कनेक्टिविटी और व्यापार को तब और गति मिलेगी

जब 2026 में चाबहार और जाहेदान को जोड़ने वाला रेल लिंक चालू हो जाएगा।

चाबहार बंदरगाह के माध्यम से अफगानिस्तान के साथ भारत का व्यापार अब लगभग 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया है, जो हिंद महासागर और यूरेशिया में बीजिंग के बढ़ते प्रभाव का मुकाबला करने में मदद कर रहा है। आंतरिक आर्थिक बदलावों और रूस-यूक्रेन संघर्ष के कारण मध्य एशिया भारत के लिए सामरिक रूप से और अधिक महत्वपूर्ण हो गया है। नतीजतन, इस क्षेत्र ने यूरोपीय संघ (ईयू), तुर्किये, भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका (यूएस) के साथ निकटता बढ़ाई है।

रेयर-अर्थ और महत्वपूर्ण खनिज संसाधनों के विशाल भंडार के कारण इस क्षेत्र में वैश्विक प्रतिस्पर्धा भी बढ़ी है। मध्य एशिया में रेयर-अर्थ खनिजों के मल्टी-ट्रिलियन-डॉलर के भंडार हैं और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं (सप्लाई चेन) में विविधता लाने के लिए रणनीतिक संपत्ति मौजूद है; अकेले कजाकिस्तान में लगभग 46 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर मूल्य के 5,000 भंडार हैं। वर्तमान में अधिकांश महत्वपूर्ण खनिज प्रसंस्करण (प्रोसेसिंग) के लिए चीन को निर्यात किए जाते हैं, जो इस क्षेत्र के लिए एक रणनीतिक कमज़ोरी पैदा करता है। मध्य एशिया ने पहले ही तकनीकी सहायता, अन्वेषण और प्रसंस्करण के माध्यम से यूरोपीय संघ और अमेरिका के साथ रेयर-अर्थ पर साझेदारी शुरू कर दी है, जिसका उद्देश्य संतुलित भू-आर्थिक और राजनीतिक संबंध बनाना है।

ऐसी परिस्थितियों में, नई दिल्ली को लचीली, विश्वसनीय और विविध आपूर्ति श्रृंखलाओं के साथ-साथ टिकाऊ परिवहन लिंक के लिए आईएनएसटीसी के पूर्वी रूट के साथ अधिक निकटता से जुड़ना चाहिए। यह मार्ग एक 'गेम-चेंजर' हो सकता है, क्योंकि भारत ने 2025 में रेयर-अर्थ आपूर्ति पर चीनी प्रभुत्व को कम करने के लिए रेयर-अर्थ और महत्वपूर्ण खनिजों पर ध्यान केंद्रित करते हुए मध्य एशियाई देशों के साथ एक रणनीतिक साझेदारी में प्रवेश किया है। पूर्वी मार्ग नई दिल्ली के व्यापार विविधीकरण को बढ़ावा दे सकता है, खनिजों की आपूर्ति सुरक्षित कर सकता है, और आईएनएसटीसी में एक प्रमुख लॉजिस्टिक्स हब के रूप में चाबहार बंदरगाह के साथ यूरेशिया में चीन के प्रभाव को संतुलित करने में मदद कर सकता है।

---

**एजाज वानी ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के स्ट्रैटेजिक स्टडीज प्रोग्राम में फेलो हैं और यह आलेख ओआरएफ के पोर्टल से साभार लेकर पुनर्प्रकाशित किया जा रहा है।**

जलज श्रीवास्तव

# धर्मेंद्र

# सिनेमाई सूरज ढला

मुंबई की सुबह उस दिन कुछ और ही थी। हवा में एक अनकही विवशता थी—जैसे शहर खुद किसी बड़े विदाई समारोह के लिए ठहर गया हो। बांद्रा, जुहू, खार कहीं भी देखिए, चेहरों पर एक ही सवाल तैर रहा था—क्या सचमुच धर्मेंद्र चले गए?

89 वर्ष की उम्र में, छह दशक की चमकदार, किंवदंतियों जैसी यात्रा पूरी कर, ही-मैन ने अंतिम सांस ली—और भारत ने अपना एक ऐसा बेटा खो दिया जो सिर्फ पर्दे पर नहीं, दिलों में बसा था।

धर्मेंद्र—यह नाम सिर्फ एक अभिनेता का नाम नहीं, बल्कि भारतीय मानस का वह हिस्सा है जिसे समय कभी मिटा नहीं पाया।

जब यह खबर बाहर आई, लोग अचानक अपनी-अपनी जगह जम गए। किसी के हाथ रिमोट पर ठहर गए, किसी की आंखों में 'शोले' के वीरू का चेहरा तैर गया, कोई 'हमने तुमको दिल ये दे दिया' की धुन में खो गया। जैसे देश का हर घर एक ही फ्रेम में तब्दील हो गया हो—एक बड़े, सामूहिक शोक के फ्रेम में।

धर्मेंद्र, जिनका असली नाम धर्म सिंह देओल, उस पीढ़ी के प्रतीक थे, जिसमें सपने कपड़ों की जेबों में नहीं, दिलों की धड़कनों में रखे जाते थे। पंजाब के एक छोटे-से गांव का साधारण-सा लड़का—जिसके पिता स्कूल टीचर थे—1958 में एक टैलेंट कॉन्टेस्ट जीतकर मुंबई आया।

वह मुंबई, जिसकी गलियां उम्मीद से ज्यादा निराशा देती थीं लेकिन इस नौजवान की आंखों में ऐसा सूरज उग रहा था, जिसे कोई ढलने नहीं दे सकता- 1960 में 'दिल भी तेरा हम भी तेरे' आई—और भारत को उसका नया हैंडसम हीरो मिल गया।

फिर तो बीते समय ने बस गवाही दी कि कैसे उनका चेहरा लाखों दिलों की सुबह और नौकरी वाले जवानों की कैंटीन पोस्टर बन गया।

धर्मेंद्र को 'ही-मैन' कहा जाता था—सिर्फ इसलिए नहीं कि उनकी कद-काठी फिल्मों में भूकम्प लाती थी—बल्कि इसलिए कि वह भूमिका जो भी हो, उसमें वह दृढ़ता और संवेदनशीलता दोनों साथ लेकर आते थे। एक तरफ 'शोले' का वीरू जो टंकी पर चढ़कर प्रेम का इज़हार कर सकता था, वहीं दूसरी तरफ 'चुपके चुपके' का वह नर्म–मिज़ाज प्रोफेसर जो अपनी बेगुनाह मुस्कान से दिल जीत लेता था।

उनके भीतर एक किसान की सहजता और एक सितारे की चमक साथ रहती थी। यही कारण था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रद्धांजलि देते हुए कहा— 'उनका जाना भारतीय सिनेमा के एक युग का अंत है।'

1975 की 'शोले' सिर्फ एक फिल्म नहीं थी; वह भारतीय भावनाओं का ग्रामोफोन थी, जो आज भी सीधे दिल में बजती है। धर्मेंद्र और अमिताभ बच्चन की दोस्ती—जय और वीरू—आज भी सबसे प्यारी सिनेमाई दोस्ती मानी जाती है। वीरू के मुंह से निकलता, 'बसंती, इन कुत्तों के सामने मत नाचना!'

आज भी पूरी एक पीढ़ी के स्मृति-एल्बम में वैसे ही चमकता है।

आज जब धर्मेंद्र जा चुके हैं, जय–वीरू की जोड़ी का आधा आसमान सूना लगता है।

उनकी अंतिम फिल्म इक्कीस  अगले महीने रिलीज होने वाली है। उन्हें पता भी नहीं होगा कि कैमरे के सामने दिया गया उनका अंतिम संवाद, शायद दर्शकों से उनका अंतिम संवाद बन जाएगा। वह कैमरे को देखकर वही पुरानी गर्माहट बिखेरते रहे—जैसे कह रहे हों: 'मैं यहां हूं और हमेशा यहीं रहूंगा—तुम्हारी यादों में।'

उनकी सेहत भले साथ न दे रही थी, लेकिन अभिनय उनका पहला और अंतिम प्रेम था।

सबके होंठों पर एक ही वाक्य—

'धर्मेंद्र चले गए'

लेकिन कोई यह कहने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था कि वह सचमुच चले गए हैं। धर्मेंद्र को खोना, हमारे समय से एक हिस्सा खोने जैसा है।

उन्होंने हमें रोमांस दिया, दोस्ती दी, हंसी दी, आंसू दिए—और सबसे बढ़कर, ईमानदार अभिनय दिया।

आज वह इस दुनिया से भले चले गए हों, मगर

हर बार जब टीवी पर वीरू की हंसी गूंजेगी,

हर बार जब 'चुपके चुपके' वाला प्रोफेसर बनावटी हिंदी बोलेगा,

हर बार जब उनकी आंखों की मासूम उदासी किसी फ्रेम में लौटेगी—

हम समझ जाएंगे—

धर्मेंद्र यहां हैं... यहीं हैं...।

# तीन बहनें

# काव्य-सी बहती कहानी और मंच पर खिलती संवेदनाएं

श्रीराजेश

कोलकाता की ठंडी होती 23 नवंबर की शाम ने एक अनोखा दृश्य देखा—जब रंगकर्मी ने उषा गांगुली मंच पर एंतोन चेखव की अमर कृति 'तीन बहने' को जीवन-श्वासों की नई लय से भर दिया। अभिनय की दुनिया में उभरते नवांकुरों को तराशने और उन्हें मंच का आत्मविश्वास देने की दिशा में रंगकर्मी की पहल 'रॉ रिहर्सल' ने इस प्रस्तुति को केवल नाटक नहीं रहने दिया—यह मानवीय लिप्सा, टूटती उम्मीदों और समय के धीमे बहाव का ऐसा पारदर्शी दर्पण बन गया, जिसमें दर्शक स्वयं का प्रतिबिंब देखते-देखते भीतर तक उतरते चले गए।

## धीमी पर गहरी लय में बहता मंचन

अनिरुद्ध सरकार के संयमित और सूक्ष्म निर्देशन में नाटक किसी धीमी धुन-सा आगे बढ़ा—मानो किसी दूरस्थ स्टेशन पर रुकी हुई पुरानी ट्रेन, जिसकी खिड़कियों से टिमटिमाती रोशनियां उम्मीद और इंतज़ार दोनों को एक साथ बयान कर रही हों।

ओल्गा, माशा और इरीना—तीन बहनें—अपने ही धूसर जीवन के गलियारों में आकांक्षाओं को थामने की जद्दोजहद में खोती-बिखरती रहीं। उनका मॉस्को लौटने का साझा स्वप्न किसी दूर दिखाई देने वाले तारे-सा था—सुंदर, उजला, पर पकड़ में न आने वाला।

## अभिनय—जो शब्दों से आगे का संसार रचता है

ओल्गा के रूप में मिलन कुमारी पांडा ने संयम, थकान और भीतर टूटते साहस को ऐसी निपुणता से जिया कि उनके चेहरे की हर झिलमिलाहट कहानी बनने लगी। तो श्रृष्टि शुक्ला की माशा—अधूरी प्रेमकथा से उपजा विद्रोह, भीतर पलता तूफ़ान, और चेहरे पर बसी निश्छल पीड़ा—उन्होंने मंच की धड़कनों को मानो अपने भीतर पिरो लिया। जबकि ऋतिका अग्रवाल की इरीना में सपनों की निष्कपट चमक और जीवन की कठोर सच्चाइयों के बीच का संघर्ष

## अनिरुद्ध सरकार—भाव, मौन और गति के शिल्पी

अनिरुद्ध सरकार—जो स्वयं उषा गांगुली की सांस्कृतिक परंपरा के उत्तराधिकारी हैं— उन्होंने इस प्रस्तुति में भावनाओं, मौन और गति के महीन संतुलन को असाधारण संवेदनशीलता के साथ साधा। उन्होंने सिद्ध कर दिया कि चेखव के नाटक ऊंची आवाज़ में नहीं बोलते—वे धीमे-धीमे मन में उतरते हैं, और वहां एक गहरी, अहसास भरी आग जलाते हैं। उनकी दिशा में 'रॉ रिहर्सल' केवल एक प्रशिक्षण मंच नहीं, बल्कि कलाकारों को भीतर से गढ़ने वाली प्रयोगशाला प्रतीत होती है—जहां आवाज़, शरीर, आवेग और सत्य को साधना ही मूल अभ्यास है।

रंगकर्मी, कोलकाता द्वारा ऊषा गांगुली मंच पर मंचित एंतोन चेखव की अमर कृति 'तीन बहनें' नाटक का दृश्य।

अत्यंत सजीव हो उठा—उनका हर भाव एक नई परत खोलता गया। अन्य कलाकार— श्रीश दत्ता (आंद्रे), दीपान्विता सरकार (नताशा), अरिंदम सिंह (सोल्योनी), राज रॉय (शेबुतिकिन), वर्धनम डागा (तुझेन्बाख)—सभी ने चेखव के संसार को इतनी सहजता से जीवंत किया कि लगा मानो दर्शक-दीर्घा और मंच के बीच की दूरी समाप्त ही हो गई हो। विशेष उल्लेखनीय अभिनय रहा ऊर्जास प्रत्युष का, जिन्होंने फिदौतिक के भूमिका में उस क्षण को—जब उनके जीवन की सारी संपदा आग में जलकर राख हो जाती है—इतनी मार्मिकता से रचा कि दर्शकों की सांसें वहीं थम-सी गईं। उनकी बदहवासी और हताशा मंच पर नहीं, दर्शकों के मन में उतरती चली गई।

वहीं समीर अली, रुद्रनील पाइक, शुभम तिग्रानिया, बबीता शर्मा, सृजन शर्मा, अंकित चौधरी और अन्य कलाकारों ने अपने छोटे किंतु महत्वपूर्ण पात्रों से नाटक की बुनावट को और दृढ़ किया—मानो हर तंतु अपनी जगह पर चमकता हुआ।

## रॉ रिहर्सल—कला की तपोभूमि

कोलकाता में अभिनय सीखने वालों के लिए ऐसा कठोर, ईमानदार और आत्म-अन्वेषण से भरा परिसर कम ही मिलता है। यही कारण है कि इस प्रस्तुति में प्रत्येक अभिनेता केवल किरदार निभा नहीं रहा था—वह उस किरदार को जी रहा था।'तीन बहनें' अपनी शांत लय, सरल दृश्य-विन्यास और भावनाओं की महीन परतों के साथ दर्शकों के भीतर देर तक बहती रही। मंच का मौन भी अपना स्वरों का संगीत रचता रहा—और वह संगीत किसी कोमल, अनदेखे हिस्से को छूकर लौटता रहा।

कोलकाता के नाट्य-प्रेमियों के लिए यह शाम यह याद दिलाने वाली रही कि थिएटर मनोरंजन नहीं—आत्मा और संवेदना के गहरे, अनकहे संवाद का माध्यम है।

रंगकर्मी के मंच पर चेखव की 'तीन बहनें' का यह रूपांतरण—निस्संदेह इस वर्ष की सबसे संवेदनशील, सबसे आत्मस्पर्शी प्रस्तुतियों में शामिल होगा।

# बॉयफ्रेंड संग फिर स्पॉट हुईं Malaika Arora

बॉलीवुड एक्ट्रेस मलाइका अरोड़ा आए दिन कहीं ना कहीं स्पॉट होती हैं और पैपराजी के कैमरे में कैद हो जाती हैं। अब वह एयरपोर्ट पर नजर आई और उनका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो के सामने आने के बाद मलाइका अरोड़ा अपनी लव लाइफ को लेकर फिर चर्चा में आ गई हैं। दरअसल, एक बार फिर वह बिजनेसमैन हर्ष मेहता के साथ स्पॉट हुई हैं। इसके बाद दोनों के डेटिंग की अटकलें तेज हो गई हैं। बताते चलें कि मुंबई के एक कॉन्सर्ट में मलाइका अरोड़ा और हर्ष मेहता को साथ में देखा गया था और तभी से दोनों के डेटिंग की खबरें आ रही हैं।

## 'तेरे इश्क में' से पहले कृति सैनन इन फिल्मों से जीत चुकी हैं जनता का दिल

अभिनेत्री कृति सैनन बॉलीवुड की उन बेहतरीन अभिनेत्रियों में से हैं, जिन्होंने कई सुपरस्टार के साथ स्क्रीन साझा की है। फिलहाल वह अपनी फिल्म 'तेरे इश्क में' को लेकर लोगों का ध्यान खींच रही हैं जिसमें उनके साथ सुपरस्टार धनुष हैं।

फिल्म में कृति ऐसी रोमांटिक लड़की का किरदार निभा रही हैं, जो उनके जुनून और आक्रामक प्यार को दर्शाता है। हालांकि, पहले भी उन्होंने फिल्मी पर्दे पर अपनी रोमांटिक फिल्मों के जरिए दर्शकों का फुल मनोरंजन किया है।

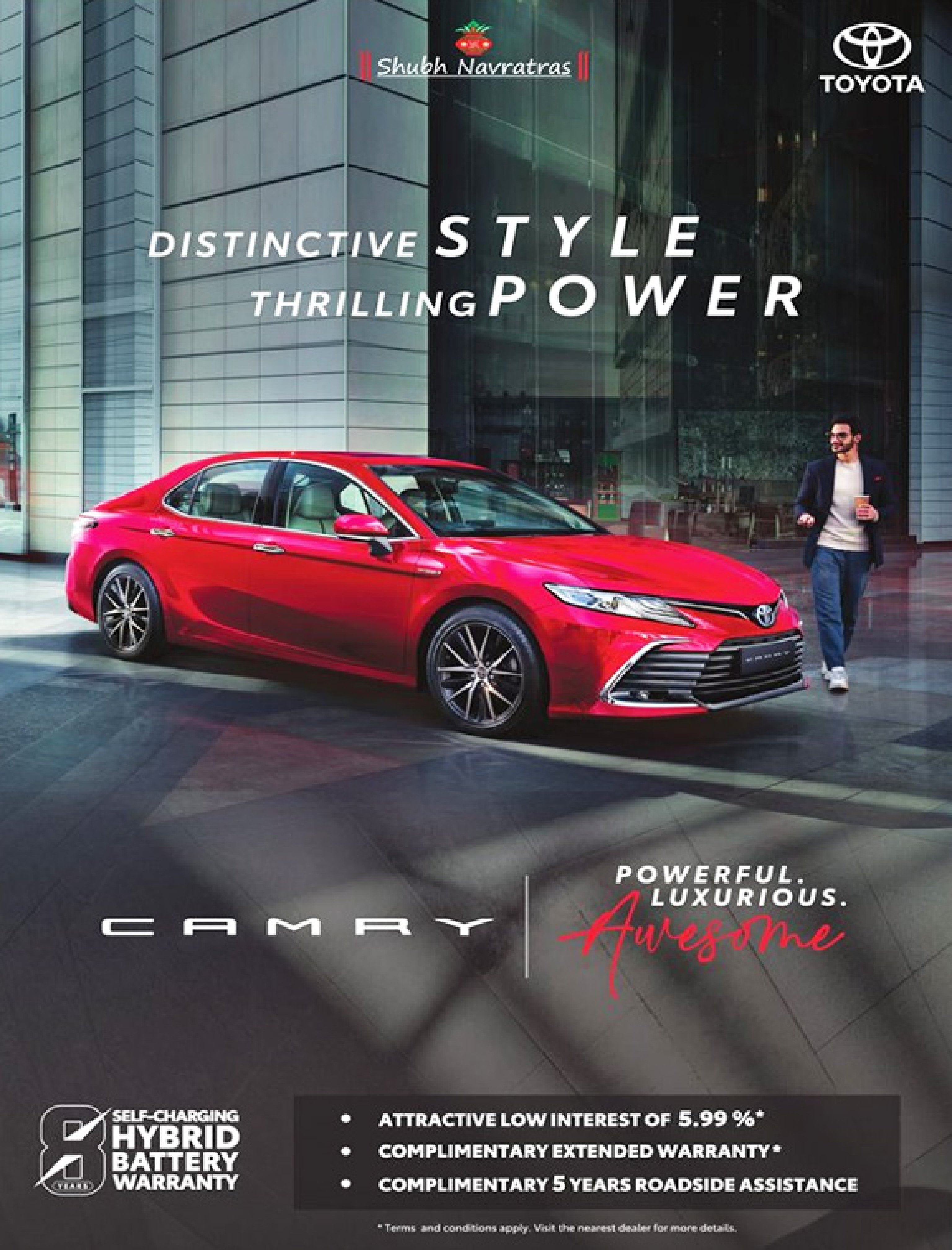
Shubh Navratras
TOYOTA
DISTINCTIVE STYLE
THRILLING POWER
CAMRY
POWERFUL.
LUXURIOUS.
Awesome
8 YEARS
SELF-CHARGING HYBRID BATTERY WARRANTY
• ATTRACTIVE LOW INTEREST OF 5.99 %*
• COMPLIMENTARY EXTENDED WARRANTY*
• COMPLIMENTARY 5 YEARS ROADSIDE ASSISTANCE
* Terms and conditions apply. Visit the nearest dealer for more details.

RNI TITLE CODE : DELENG19447

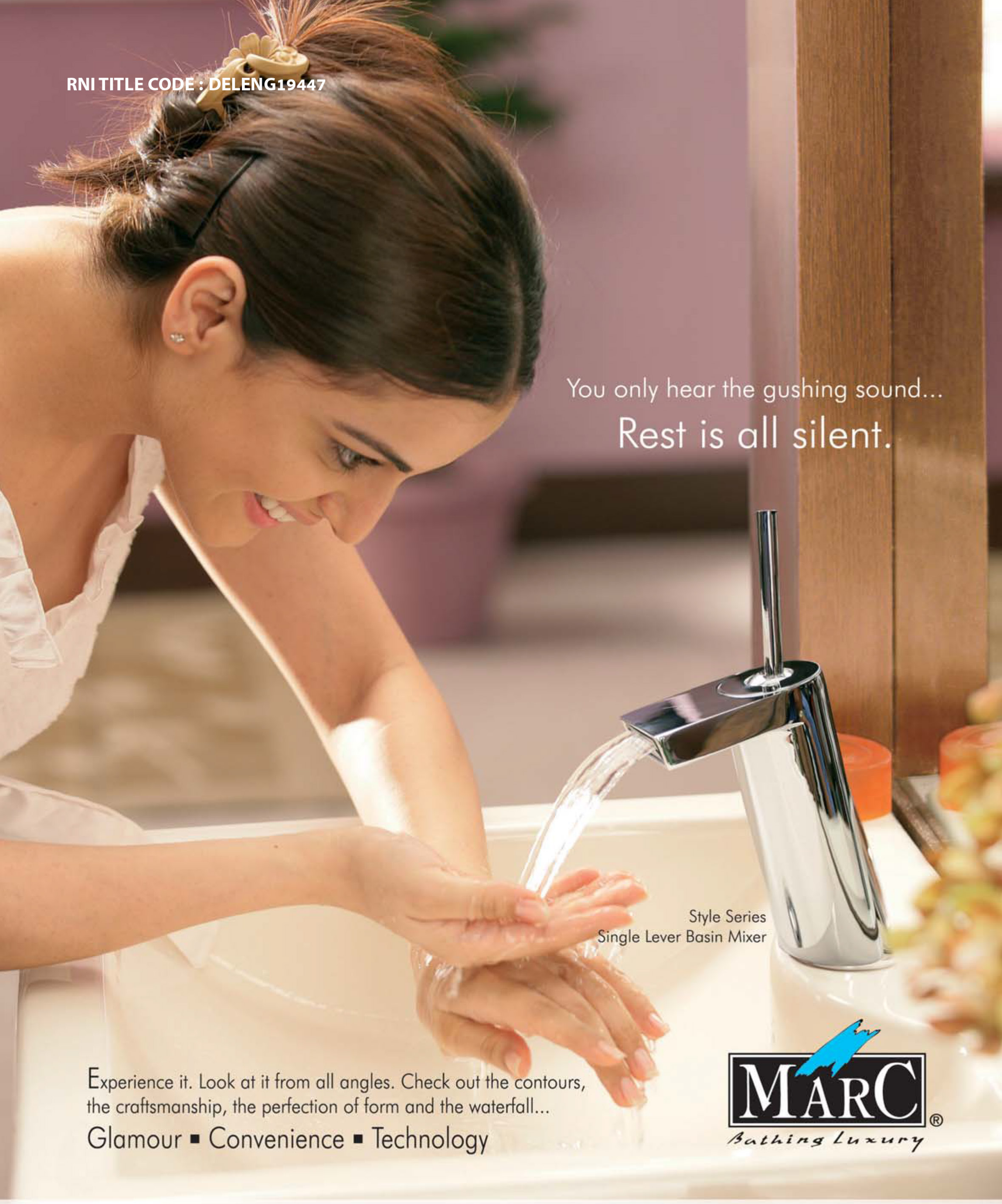


**MARC SANITATION PVT. LTD.**
A-2, S.M.A. Co-op. Industrial Estate, G.T. Kamal Road, Delhi-110 033
Ph: 27691410, Fax: 011-27691445/27692295 E-mail: info@marcindia.com Website : www.marcindia.com